भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

Insolvency and Bankruptcy Board of India

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

www.ibbi.gov.in

सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट | 2016-17

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में
1 मई, 2018 को अधिसूचित
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
(वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली, 2018 में
निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India
7th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Place
New Delhi-110001 Tel: +91 11 23462801
E-mail: chairperson@ibbi.gov.in Web.: www.ibbi.gov.in

सत्यमेव जयते

Dr. M. S. Sahoo
Chairperson

बोर्ड-18011/2/2019-आई बी बी आई
31 मई 2019

सचिव, भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली–110001.

प्रिय महोदय,

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 229 के प्रावधानों के अनुसरण में, मै भारत के राजपत्र में 1 मई, 2018 को अधिसूचित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली, 2018 में निर्धारित प्रारूप में 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित कर रहा हूं।

भवदीय,
एम. एस. साहू
(डॉ. एम. एस. साहू)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

Board/18011/2/2019-IBBI
31st May, 2019

The Secretary to Government of India
Ministry of Corporate Affairs
'A' Wing, Shastri Bhawan
New Delhi- 110001.

Dear Sir,

In accordance with the provisions of section 229 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, I forward herewith a copy of the Annual Report of the Insolvency and Bankruptcy Board of India for the period 1st October, 2016 to 31st March, 2017, in the form prescribed in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Annual Report) Rules, 2018 notified on 1st May, 2018 in the Gazette of India.

Yours faithfully,
M. S. Sahoo
(Dr. M. S. Sahoo)

Encl.: As above.

अधिशासी बोर्ड

(31 मार्च, 2017 को)

अध्यक्ष

डॉ. एम.एस. साहू

पूर्णकालिक सदस्य

सुश्री सुमन सक्सेना

डॉ. नवरंग सैनी

पदेन सदस्य

श्री अमरदीप एस. भाटिया
संयुक्त सचिव
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

श्री जी.एस. यादव
संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार
विधिक मामले विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

श्री उन्नीकृष्णन ए.
विधिक सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अधिकारी

(31 मार्च, 2017 के अनुसार)

(बाएं से दाएं)

बैठे हुए: **सुश्री सुमन सक्सेना**, पूर्णकालिक सदस्या; **डॉ. एम.एस. साहू**, अध्यक्ष; **डॉ. नवरंग सैनी**, पूर्णकालिक सदस्य

खड़े हुए: **श्री संजीव पांडेय**, उप महाप्रबंधक; **श्री रितेश कावड़िया**, मुख्य महाप्रबंधक; **सुश्री रंजीता दूबे**, उप महाप्रबंधक; **सुश्री अनीता कुलश्रेष्ठ**, उप महाप्रबंधक; **श्री आई. श्रीकारा राव**, उप महाप्रबंधक; **श्री उमेश कुमार शर्मा**, उप महाप्रबंधक

विषय सूची

खंड क अध्यक्ष का कथन 1

खंड ख समीक्षाधीन वर्ष 5

सूक्ष्म आर्थिक संदर्भ 5
शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति 6
दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 9
कोड का कार्यान्वयन 13
विकास का कालक्रम 16

खंड ग नीतियाँ, कार्यक्रम और गतिविधियां 18

ग.1 सेवा प्रदातागण 18
दिवाला पेशेवर 18
दिवाला पेशेवर कम्पनियां 20
दिवाला पेशेवर एजेंसियां 20
सूचना उपयोगिता 22
ग.2 कारपोरेट प्रक्रियाएं 23
कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 23
कारपोरेट परिसमापन प्रक्रिया 29
स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया 30
ग.3 हिमायत और जागरूकता 31

खंड घ बोर्ड के कार्य 34

अर्ध-विधायी कार्य 34
कार्यपालक कार्य 35
अर्ध-न्यायिक कार्य 37

खंड ङ़ परिणामों का विश्लेषण 38

कारपोरेट दिवाला समाधान 38
उभरता विधि.संग्रह 38

खंड च कोड का प्रभाव 42

खंड छ बोर्ड का कार्य-निष्पादन 44

खंड ज अधिशासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन 45

खंड झ बोर्ड का वित्तीय निष्पादन 47

खंड ञ संगठनात्मक मामले 48

स्थापना 48
अधिषासी बोर्ड 49
संगठनात्मक संरचना 50
शक्तियों का प्रत्यायोजन 50
सलाहकार समितियां 52
अनुशासनात्मक समिति 53
राजभाषा 53
मानव संसाधन 53
सूचना प्रौद्योगिकी 54
परिसर 54
सूचना का अधिकार 54

बॉक्स मदों की सूची

1. जुड़वां तुलन पत्र संलक्षण का समाधान 8
2. आईपीः दिवाला व्यवस्था की एक प्रमुख संस्था 19
3. उपयुक्त और उचित व्यक्ति 21
4. समाधान योजनाः कोड की भावना 25
5. 180 दिनः बहुत अधिक या बहुत कम 27
6. सीओसीः लोक न्यास का एक संस्थान 28
7. विनियामक राज्य 51

तालिकाओं की सूची

1. जुड़वां तुलन पत्र संलक्षण के लिए दृष्टिकोण 9
2. कारपोरेट प्रक्रियाओं के संबंध में आईबीसी पूर्व बनाम आईबीसी प्रणाली 12
3. निगरानी समिति और कार्य समूह 15
4. विकास का कालक्रम 16
5. अध्यक्ष, आईबीबीआई की कार्यक्रमों में उपस्थिति 32
6. 2016–17 में अधिसूचित विनियमन 34
7. सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति की संरचना 35
8. कारपोरेट दिवाला समाधान सलाहकार समिति का गठन 35
9. दिवाला पेशेवरों का पंजीकरण 35
10. दिवाला पेशेवरों के क्षेत्रीय वितरण 36
11. 31 मार्च 2017 के अनुसार मान्यताप्राप्त आईपीई 36
12. 31 मार्च 2017 के अनुसार पंजीकृत आईपीए 36
13. सीमित दिवाला परीक्षा, 2016–17 37
14. सीआईआरपी का प्रारंभ 38
15. सीआईआरपी में आवेदनों की स्वीकृति 39
16. सीआईआरपी का क्षेत्रवार वितरण 40
17. बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति 46
18. आय और व्यय विवरण, 2016–17 47
19. अधिषासी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति 50
20. आईबीबीआई में अधिकारियों का पदानुक्रम 53
21. 31 मार्च, 2017 तक आईबीबीआई के कर्मचारीगण 54
22. 2016–17 में आवेदनों की प्राप्ति और निपटान 55

आंकड़ों की सूची

1. सकल घरेलू उत्पाद, ऋण और एनपीए की प्रगति 6
2. संगठनात्मक संरचना 52

इनस्क्रिप्ट की सूची

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का अधिनियमन 10
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय से पत्राचार 14
3. आईबीबीआई की स्थापना 48

संक्षिप्त अक्षरों की सूची

आईसीएआई	भारतीय चार्ट हित लेखाकार संस्थान
आईसीएमएआई	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आईसीआर	ब्याज कवरेज अनुपात
आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आईसीएसआई आईपीए	आईसीएसआई दिवाला पेशेवर एजेंसी
आईजीआईडीआर	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आईआईसीए	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान
आईआईआईपी ऑफ आईसीएआई	आईसीएआई का भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईएम	सूचना ज्ञापन
आईएमएस	प्रबंधन अध्य्यन संस्थान
आईपी (ज)	दिवाला पेशेवर/पेशेवरगण
आईपी विनियमन	आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर) विनियमन, 2016
आईपीए (ज)	दिवाला पेशेवर एजेंसी/एजेंसियां
आईपीए ऑफ आईसीएमएआई	आईसीएमएआई की दिवाला पेशेवर एजेंसी
आईपीए विनियमन	आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर एजेंसियां) विनियमन, 2016
आईपीई (ज)	दिवाला पेशेवर संस्था/संस्थाएं
आईआरपी	अंतरिम समाधान पेशेवर
आईयू (ज)	सूचना सुविधा/सुविधाएं
आईयू विनियम	आईबीबीआई (सूचना सुविधाएं) विनियमन, 2017
ओसी(ज)	प्रचालनात्मक लेनदार/लेनदारगण
ओटीएस	एकबारगी निपटारा
आरए (ज)	समाधान आवेदक/आवेदकगण
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडीडीबीएफआई	बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993
आरओसी	कंपनियों के पंजीकार
आरपी	समाधान पेशेवर
उप नियम विनियमन	आईबीबीआई (मॉडल उप नियम और दिवाला पेशेवर एजेंसियों का अधिषासी बोर्ड) विनियमन, 2016
एए	सहायक प्राधिकरण
एसी	सलाहकार समिति
एडवाइजरी रेगुलेशन्स	आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एक्यूआर	परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा

संक्षिप्त अक्षरों की सूची

एआरसी	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी/कंपनीयां
एसोचेम	एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एमसीसीआई	व्यापारियों का वाणिज्य और उद्योग मंडल
एमएल एंड जे	विधि और न्याय मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमआरयू	महाराष्ट्र राहत उपक्रम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1958
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनईएसएल	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
एनआईपीएफपी	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
एनआईएसएम	राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान
एनएलयू	राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय
एनपीए(ज)	गैर–निष्पादित परिसंपत्ति/परिसंपत्तियां
एस4ए	तनावपूर्ण परिसंपत्तियों की सतत संरचना की योजना
एफसी (एस)	वित्तीय लेनदार/लेनदारगण
एलबीएसएनएए	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
एलएलपी	सीमित देयता भागीदारी
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एससीबीज	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीआर	रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना
कोड/आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
जीबी	आईबीबीआई का अधिषासी बोर्ड
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएम	महाप्रबंधक
टीबीएस	जुड़वा तुलन पत्र समस्या
ट्राई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
डीसी	अनुशासन समिति
डीजीएम	उप महाप्रबंधक
डीआरएटी	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
डीआरटी	ऋण वसूली अधिकरण
डब्ल्यूजी	कार्य समूह
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

संक्षिप्त अक्षरों की सूची

परीक्षा	सीमित दिवाला परीक्षा
पीएचडीसीसीआई	वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
पीएसबीज	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
परिसमापन विनियम	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
फिक्की	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों का परिसंघ
बीसीसीएंडआई	बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलआरसी	शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति
बोर्ड/आईबीबीआई	बोर्ड/भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड के विनियमन	आईबीबीआई (अधिषासी बोर्ड बैठक के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
यूएनसीआईटीआरएएल	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
सरकार	केंद्र सरकार
सीएंडएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीएंडआई	प्रतिस्पर्धा और नव प्रवर्तन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीडी	कारपोरेट देनदार
सीडीआर	कारपोरेट ऋण पुर्नसंरचना योजना
सीईआरएसएआई	प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज की केन्द्रीय रजिस्ट्री
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईआरपी	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईआरपी विनियमन	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
सीएलबी	कंपनी विधि बोर्ड
सीएलबीए	प्रतिस्पर्धी विधि बार एसोसिएशन
सीओसी	लेनदारों की समिति
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार
सेबी	भारतीय–प्रतिभूर्ति एवं विनिमय बोर्ड
सरफेसी	वित्तीय प्रतिभूतियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
सिका	बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985
स्वैच्छिक विनियम	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन) विनियमन, 2017

क अध्यक्ष का वक्तव्य

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 ने कहानी को 'निराश अंत' से बदलकर 'अनंत आशा' कर दिया है।

निकास की स्वतंत्रता

मुख्यधारा के आर्थिक विचार के अनुसार प्रत्येक समय, मानव की इच्छाएं असीमित हैं जबकि उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन सीमित हैं। इसलिए, संसाधनों की अपर्याप्तता के साथ ही निरंतर बढ़ रही असीमित इच्छाएं, ही केंद्रीय आर्थिक समस्या हैं। मुख्यधारा के कानूनी विचार के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति से आर्थिक स्थिति में जाता है, वह किसी हद तक स्वतंत्रता खो देता है। इसलिए, आर्थिक हितों को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता की अपर्याप्तता केंद्रीय कानूनी समस्या है।

इस प्रकार, संसाधन और स्वतंत्रता दोनों की जुड़वां अपर्याप्तताएं हैं: जैसे संसाधन सीमित हैं, वैसे ही स्वतंत्रता भी। पर्याप्तताएं भी जुड़वां हैं: संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जाता हैं और कंपनियां अपने हितों को देखती हैं। कोई अर्थव्यवस्था तब पनपती है जब उसके सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग किया जाता है। यह तब होता है जब स्वयं–इच्छुक फर्मों को निरंतर और निर्बाध रूप से अधिक कुशल उपयोग के लिए संसाधनों को स्थानांतरित करने की अधिकतम स्वतंत्रता होती है।

स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था में प्रत्येक फर्म और प्रत्येक संसाधन की पूरी क्षमता को प्रकट और महसूस करती है। यह सुस्थापित है कि आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक कार्य–निष्पादन का बहुत ही सकारात्मक परस्पर संबंध है। इसलिए, दुनिया भर के देशों का यह प्रयास रहा है कि वह अपने लोगों को सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाने के लिए उचित संस्थागत परिवेश प्रदान करें। ऐसा तब होता है जब वह (क) आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कराते, उसे बढ़ावा देते और उसका संरक्षण करते हैं और (ख) ऐसी स्वतंत्रता को केवल उस सीमा तक विनियमित करते हैं जितनी बाजार की विफलता(ओं) का समाधान करने के लिए आवश्यक हो।

किसी फर्म को मोटे तौर पर कारोबार के तीन चरणों – कारोबार शुरू करने, जारी रखने और बंद करने, में स्वतंत्रता की आवश्यक होती है। नई फर्मों को निरंतर उभरने में यह सक्षम बनाता है। सक्षम होने पर वे व्यवसाय करते हैं, और जब वे सक्षम नहीं रहते तो वे स्थान को खाली कर देते हैं। पहला चरण सर्वाधिक सक्षम उपयोग के लिए संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करता है, दूसरा चरण आवंटित संसाधनों का सक्षम उपयोग सुनिश्चित करता है और तीसरा चरण अक्षम उपयोग से संसाधनों की मुक्ति सुनिश्चित करता है। यह संसाधनों का सबसे सक्षम उपयोग और इसके पष्चात अभीष्ट आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करता है। आर्थिक सुधार आम तौर पर इन तीन चरणों में आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करता है।

भारत में 1990 के दशक में सुधारों ने प्रवेश की स्वतंत्रता पर ध्यान दिया। इसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। तब इसने लाइसेंस–परमिट–कोटा राज को विघटित किया, विवेकाधीन लाइसेंस में पंजीकरण की पात्रता प्रदान की। तब इसने प्रवेश की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार से किसी विशेष अनुमोदन की अपेक्षा के बिना, संसाधन जुटाने के लिए पात्रता आवष्यकताओं को पूरा करने वाली फर्मों को अनुमति दी।

2000 के दशक के सुधारों ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा बनाने पर ध्यान दिया। उन्होने बाजार में फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए फर्मों के एकाधिकार नियंत्रण को दूर किया। आकार या प्रभुत्व को अब बुरा नहीं समझा जाता था, सिवाय इसके दुरुपयोग को। इन सुधारों ने क्षेत्र में समान अवसर और प्रतिस्पर्धी तटस्थता प्रदान की और व्यवसाय करने की अन्य फर्मों की स्वतंत्रता को सीमित करने से फर्मों को रोका।

आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक, जो किसी अर्थव्यवस्था की नीतियों और संस्थानों द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थन करने की डिग्री का मापन करता है, में 1990 के दशक से भारत में काफी सुधार हुआ है। इसका परिणाम आश्चर्यजनक रहा है। 1992 के बाद से सुधार के बाद की अवधि में औसत वृद्धि दर सुधार–पूर्व अवधि की अपेक्षा दोगुनी से अधिक रही है। आज, भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही ट्रिलियन–डॉलर अर्थव्यवस्था है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के सीमित प्रवेश वाले समाजवाद के निकास रहित बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से, आसन्न निकास की लागत को पर्याप्त बनी। व्यवसाय शुरू करने के बाद, बाजार अर्थव्यवस्था में कोई फर्म योजना के अनुसार कार्य करने में, दो व्यापक परिस्थितियों में, विफल रहती है:

(क) फर्म ऐसे उद्योग से संबंधित हो, जो बाहरी कारणों (प्रौद्योगिकी, नीति, व्यापार, समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन) से व्यापार में अधिक व्यवहार्य नहीं है। ऐसे मामलों में, फर्म आर्थिक संकट में होती है। ऐसे में फर्म की परिसंपत्तियों

को व्यवहार्य व्यवसायों में पुनःनियोजित करना और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उद्यमी को मुक्त करना ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प होता है; या

(ख) फर्म ऐसे उद्योग से संबंधित हो, जहां उद्योग की अन्य फर्में अच्छा कर रही हैं, लेकिन अंतर्निहित कारणों (खराब संगठन, अक्षम प्रबंधन, दुर्भावना, आदि) की वजह से फर्म अच्छा नहीं कर रही है। ऐसे मामलों में, फर्म वित्तीय संकट में होती है। ऐसे समय परिसमापन से बचने के लिए फर्म को वर्तमान प्रबंधन के चंगुल से बचाना और एक विश्वस्त और सक्षम प्रबंधन के हाथों सौंपना आवश्यक होता है।

ऐसी स्थिति में, फर्म के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कम हो जाता है और प्रबंधन/उद्यमी विफल हो जाता है। जब कोई फर्म लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहती है, उसका तुलन–पत्र सिकुड़ जाता है। अनेक फर्मों, खास तौर पर बड़ी फर्मों, की ऐसी विफलता लेनदारों, खास तौर से बैंकों के तुलनपत्र को प्रभावित करती है। इससे लेनदारों के पास धन की उपलब्धता घटती है जिससे वस्तुतः व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए उधार देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है और इस प्रकार ऋण की प्रगति बाधित होती है। यह प्रभाव तब स्पष्ट होता है जब कंपनियां जानबूझकर ऋण नहीं चुकाती। इस प्रकार, इस दशक के मध्य में उभरने वाली स्थिति को लोकप्रिय रूप से 'जुडवां तुलन–पत्र' समस्या के रूप में जाना जाता है, जिसमें बैंक और फर्म दोनों ही अशोध्य ऋणों के तनाव से जूझ रहे थे, जिससे समग्र आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

यह कदया गया कि संसाधनों की दुर्लभता और विफलता गतिशील हुई है। बाजार अर्थव्यवस्था भारत में अल्प उपयोग किए गए संसाधनों को निरंतर अधिक सक्षम उपयोग में लाने और उद्यमियों को विफलता से मुक्त करने के लिए एक कूटीकृत और संरचित बाजार तंत्र की जरूरत थी। दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी/कोड), (कं) एक विफल, किंतु व्यवहार्य फर्म को बचाने; और (ख) अव्यवहार्य उद्यमों का परिसमापन करने और उद्यमी(मियों) सहित, इसके संसाधनों का प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए मोचन करने के लिए अनुकूल बाजार तंत्र उपलब्ध कराते हुए, इस प्रकार, निकास, अंततः निकास की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनंत आशा

कोड किसी हितधारक को एक सीमित राशि की चूक पर किसी फर्म की कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को सक्रिय करने का अधिकार देता है और ऐसा किए जाने पर फर्म 'कब्जेदार देनदार' से 'नियंत्रक लेनदार' के पास चली जाती है; फर्म और उसकी परिसंपत्तियों का प्रबंधन एक दिवाला पेशेवर (आईपी) में निहित हो जाता है, जो फर्म को एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में चलाता है, और फर्म के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) गठित की जाती है। आईपी फर्म की शोधन अक्षमता के समाधान के लिए पात्र और विश्वसनीय समाधान आवेदकों (आरए) से संभाव्य और व्यवहार्य समाधान योजनाएं आमंत्रित करता है। यदि सीओसी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक बहुमत से किसी समाधान योजना को मंजूरी दी जाती है, तो फर्म को चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखा जाता है। यदि इस अवधि के भीतर सीओसी द्वारा आवश्यक बहुमत से, किसी समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो फर्म का अनिवार्यतः परिसमापन किया जाता है।

कोड एक समाधान योजना के माध्यम से एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में फर्म के दिवालेपन को हल करने का प्रयास करता है। इसमें समाधान योजना का आकार, रंग और बनावट निर्धारित नहीं किया जाता है, इसे हितधारकों की निष्ठा पर छोड़ा गया है। किसी योजना में, यद्यपि, तुरंत या किसी समय अवधि में व्यापार, वित्तीय और प्रचालन पुनर्गठन का अनोखा संयोजन आवश्यक होता है, जो एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में फर्म की शोधन अक्षमता के समाधान के लिए अपेक्षित हो। प्रत्येक समाधान योजना में दिवाला के समाधान की विशिष्ट संभावना को देखते हुए, कोड में विचार–विमर्श और मतदान के जरिए, सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना के अनुमोदन में, सीओसी द्वारा विवेक के प्रयोग की परिकल्पना की गई है।

कोड के अधिनियमन से पहले, दिवालिया परिदृश्य कई अतिव्यापी कानूनों – केंद्रीय और प्रांतीय – के साथ ही बिना किसी समन्वय के अलग–अलग लागू की गई गैर–सांविधिक योजनाओं के कारण अत्यधिक विखंडित था। इसका परिणाम कमजोर, खर्चीला और अनिश्चित था। कोड में पिछली व्यवस्था की चार मूलभूत चिंताओं का समाधान किया गया है:

(क) किसी फर्म को इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। जब तक ऋण की चुकौती की जाती है; इक्विटी पर फर्म का पूरा नियंत्रण रहता है। जब फर्म ऋण की चुकौती करने में विफल रहती है, तो कोड दिवाला के समाधान के लिए लेनदारों को फर्म का नियंत्रण सौंप देता है;

(ख) समाधान में वाणिज्यिक के साथ ही सहायक निर्णयों को आवश्यक बनाया जाता है। कोड, फर्म के हितधारकों और सहायक प्राधिकारी (एए) को उनके संबंधित महत्वाकांक्षी दायरे में तेजी से निर्णय लेने की शक्ति और सुविधा प्रदान करता है;

(ग) फर्म का उद्यम मूल्य समय के साथ तेजी से घटता है, क्योंकि इसके स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है और दिवाला संबंधी सामान्य आशंका से ग्राहकों, विक्रेताओं, श्रमिकों, आदि में झगड़ा बना रहता है। कोड एक निश्चित समय में समाधान प्रक्रिया का आदेश देता है और इस प्रकार, मूल्य को संरक्षित करता है; और

(घ) फर्म की संपत्ति सबके लिए पर्याप्त नहीं होती। यदि लेनदार फर्म की उपलब्ध संपत्तियों से, अपना बकाया – एक के बाद एक या एक साथ – वसूलते हैं, तो बाद के लिए कुछ नहीं बच पाता, जिससे फर्म समाप्त हो जाती है। इसलिए कोड, सीआईआरपी के दौरान कई तरीकों से वसूली को रोकता और हतोत्साहित करता है।

इस प्रकार, कोड, जहां भी संभव हो, दिवालिया होने के समयबद्ध समाधान के लिए एक बाजार तंत्र प्रदान करता है, और संबंधित फर्म की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और इसके सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, निकास की सुविधा प्रदान करता है।

यदि उद्यमी को किसी व्यवसाय से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है तो व्यवसाय की विफलता पर उद्यमशीलता का विफल कर देती है। व्यवहार्य व्यवसायों को बचाकर और गैर–व्यवहार्य को बंद करके, कोड उद्यमियों को विफलता से मुक्त करता है। यह उन्हें असफलता से अडिग रहकर, आसानी से व्यापार में शामिल होने और आसानी से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। जैसे–जैसे अधिकाधिक संभावित उद्यमी इसे पहचानेंगे, कोड उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा।

कई फर्मों के चूक करने पर, लेनदारों के पास धन की उपलब्धता में कमी आती है, जिससे उपयुक्त परियोजनाओं के लिए भी उधार देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरी ओर, कम और विलंबित वसूली से ऋण देने की लागत बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप, ऋण की उपलब्धि उच्च लागत पर होती है जिसमे कई परियोजनाएं अव्यवहार्य हो जाती हैं। समाधान और परिसमापन के प्रावधान के माध्यम से, कोड चूक की घटनाओं में कमी करता है, और लेनदारों को भविष्य, में अर्जित राषि समाधान–पश्चात के अर्जनों या परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से धन की वसूली करने में सक्षम बनाता है। यह लेनदारों – प्रतिभूत और अप्रतिभूत, बैंक और गैर–बैंक, वित्तीय और प्रचालन – को परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस तरह, ऋण की उपलब्धता बढ़ाता है।

चूक आमतौर पर उद्योग में अन्य फर्मों की तुलना में फर्म में उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष में कम उपयोग को दर्शाती है। कोड (क) इष्टतम क्षमता से नीचे संसाधनों के उपयोग को रोककर; (ख) समाधान योजना के माध्यम से फर्म के भीतर संसाधन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करके; या (ग) फर्म को बंद करके अप्रयुक्त या कम उपयोग किए गए संसाधनों को अवमुक्त करके फर्म के मूल्य को अधिकतम बनाता है । यदि संसाधन, जो वर्तमान में किसी भी कारण(णों) से अप्रयुक्त हैं या कम उपयोग किए जा रहे या जंग खा रहे हैं, उन संसाधनों को और अधिक कुशल उपयोगों के लिए रखा जा सकता है, तो विकास दर कुछ प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

मुझे विश्वास है कि उद्यमी (मियों) को विफलता से मुक्त करते हुए और ऋण की बेहतर उपलब्धता और अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन सहित, निरंतर पुनःचक्रण के लिए अव्यवहार्य फर्मों के चक्रव्यूह से संसाधनों को मुक्त करते हुए, कोड ने कहानी को 'निराश अंत' से 'अनंत आशा' में बदल दिया है।

यात्रा में भागीदारी

भारत में दिवाला के समाधान के लिए किसी विधि का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, जो स्वप्रेरित, प्रोत्साहन षिकायत, बाजार–चालित और समयबद्ध हो। आधुनिक और मजबूत दिवाला व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कई संस्थानों का अस्तित्व नहीं था। इसलिए, कोड और कोड के तहत परिकल्पित सुधार, कई मायनों में, अज्ञात में प्रवेष और विश्वास में एक छलांग थी। फिर भी, कारपोरेट दिवाला, समाधान और परिसमापन दोनों, के संबंध में संपूर्ण विनियामक ढांचा और कारपोरेट दिवाला के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र 2016 के अंत तक लागू हुआ और कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान 1 दिसंबर 2016 से लागू हुए। एक फर्म को 17 जून, 2017 को सीआईआरपी में दाखिल किया गया। कोड के अधिनियमन और इसके क्रियान्वयन में बहुत तेजी आई है, जो मेरी जानकारी के अनुसार, शायद दुनिया में कहीं और नहीं है।

केंद्र सरकार (सरकार) ने अग्रभाग से सुधार की शुरूआत की और जल्द ही इसे 'यात्रा में भागीदारी' में बदल दिया। इसने इक्विटी को छोड़कर सभी हितधारकों के दावों को अपने अधीन कर लिया। कोड के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसने कई अन्य कानूनों में संशोधन किया। इसने कोड को अन्य सभी कानूनों पर वर्चस्व प्रदान किया। इसने 1 जून, 2016 को देश भर में कई पीठों सहित एए के नाम से संस्थागत बुनियादी ढांचे के एक प्रमुख स्तंभ की स्थापना की। इसने मसौदा नियम, विनियमन और आईबीबीआई, आईपी, दिवाला पेशेवर एजेंसियों (आईपीए'ज), सूचना सुविधाओं (आईयू'ज) और कारपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित अन्य मामले तैयार करने के लिए 22 जुलाई, 2016 को एक निरीक्षण समिति और चार कार्य समूहों (डब्ल्यूजी'ज) का गठन किया। इसने तीन पेशेवर संस्थानों के साथ मिलकर नवंबर, 2016 के अंत तक अनेक स्थान पर एक आईपीए की स्थापना की। इसने 1 अक्टूबर, 2016 को संस्थागत बुनियादी ढांचे के एक अन्य प्रमुख स्तंभ, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना की और इसे 1 दिसंबर, 2016 से कारपोरेट प्रक्रियाओं के प्रारंभ को सक्षम बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और विनियामक ढांचे को तैयार करने का कार्य सौंपा।

सरकार की प्राथमिकता और फोकस के साथ, आईबीबीआई स्वप्रेरित रूप से हितधारकों के साथ जुड़ा हुआ है। तीनों

पेशेवर संस्थानों ने एक–एक आईपीए स्थापित किया। जल्द ही आईपी'ज के एक कैडर को कोड के तहत प्रक्रियाओं के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईपी'ज, व्यापार और उद्योग निकाय, शिक्षा जगत और विश्वविद्यालय, देनदार और लेनदार और पेशेवरों ने सुधार को लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए समयोपरि कार्य किया। यद्यपि सरकार में सुधार शुरू हो गया, हितधारकों ने डब्ल्यूजी और सलाहकार समितियों (एसी'ज), गोल मेज़ सम्मेलनों में, और अन्यथा नियमों और विनियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिवाला सुधार हितधारकों द्वारा, के लिए और उनका एक सुधार बन गया है। व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सभी हितधारक एकजुट हैं।

उन्नति की ओर

जब भी किसी बड़े सुधार की परिकल्पना की जाती है, खास तौर पर जब यह हितधारकों के अधिकारों और दायित्वों को काफी हद तक प्रभावित करता हो जैसा कि कोड करता है, इस बारे में सामान्य आशंका के साथ ही परिवर्तनों और कई बार जोरदार प्रयासों को स्वीकार करने में अनिच्छा बनी रहती है, अक्सर अदालत की प्रक्रिया, पुराने आदेश पर अड़ी[1] रहती है। इसके अलावा, सुधार को लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता निर्मित करने और बाजारों और प्रथाओं को विकसित करने में समय लगता है।

आने वाले दिनों में, हितधारक, पारिस्थितिकी तंत्र और विनियामक ढांचा काम पर सीखेंगे और अनुभव के साथ परिपक्व होंगे। दिवाला और मूल्यांकन पेशा गहरी जड़ें पकड़ेगा और दिवाला सेवाओं को पेशेवर बनाएगा। दिवाला प्रक्रिया में प्रमुख कारक – वित्तीय लेनदार (एफसी), प्रचालन लेनदार (ओसी) और देनदार फर्में और आरए, सीआईआरपी के दौर से गुजर रही फर्म की विशिष्ट जरूरतों के लिए प्रक्रिया को तैयार करने के लिए प्रथाएं विकसित करेंगे। न्यायिक घोषणाएं उभरते हुए विवादास्पद मुद्दों को सुलझाएंगी और संदेहास्पद मामलों को शीघ्रता से हल करेंगी। प्रक्रिया, परिणाम और समय के संबंध में निश्चितता सामने आएगी। प्राधिकरण – सरकार और विनियामक – कोड के तहत प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ कार्य करेंगे। आने वाले वर्षों में, अंतरिम वित्त, समाधान योजनाओं और परिसमापन परिसंपत्तियों और अन्य सेवाओं के लिए बाजार विकसित होंगे। समाधान प्रक्रिया को जल्दी शुरू और शीघ्रता से सम्पन्न किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश असफल फर्मों को बचाया जाएगा। केवल कुछ अव्यवहार्य फर्मों का, संसाधनों को वैकल्पिक उपयोग के लिए तेजी से मुक्त करने के लिए, परिसमापन किया जाएगा। दुर्लभ संसाधनों का उनकी इष्टतम क्षमता पर उपयोग किया जाएगा। विफलता के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना उद्यमी नए व्यवसाय शुरू करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। प्रतियोगिता और नवप्रवर्तन में उछाल आएगा। क्रेडिट बाजार का विस्तार होगा, और कॉर्पोरेट वित्त में बैंकों और अन्य संस्थानों से प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋण का संतुलित मिश्रण होगा। इन सभी का आर्थिक प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

नवंबर, 2016 तक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और विनियामक ढांचे सहित, 2016–17 में कोड के कार्यान्वयन में प्रगति, और मार्च, 2017 तक कुछ फर्मों का सीआईआरपी में प्रवेश उत्साहजनक रहा है। हितधारकों के समग्र उत्साह के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिवाला व्यवस्था परिपक्वता की ओर बढ़ रही है और कोड के तहत प्रक्रियाएं प्रगति कर रहे दिवाला समाधान का पसंदीदा तरीका होगा। इस पृष्ठभूमि में, यह रिपोर्ट, आईबीबीआई की पहली वार्षिक रिपोर्ट, 1 अक्टूबर, 2016 को इसकी स्थापना के समय से 31 मार्च, 2017 तक हुए घटनाक्रम को प्रस्तुत करती है।

यद्यपि किसी संगठन (आईबीबीआई) या एक अधिनियमन (कोड) के जीवन में छह महीने की अवधि बहुत ही कम है, यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही है। मैं कारपोरेट कार्य मंत्रालय को देश में दिवाला सुधार आरंभ करने और आईबीबीआई की स्थापना के दो महीने के भीतर कारपोरेट दिवाला समाधान शुरू करने के लिए सभी खंडो को एक साथ रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आईबीबीआई (जीबी) के अधिषासी बोर्ड में अपने सदस्य सहयोगियों को अपने शुरुआती दिनों में आईबीबीआई को आकार देने के लिए काफी समय देने और एक अनुभवहीन दिवाला व्यवस्था में विनियामक ढांचे को डिज़ाइन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आईबीबीआई में 31 मार्च, 2017 को लगभग आधा दर्जन अधिकारी थे। उनमें से प्रत्येक ने गंभीर बाधाओं के बावजूद कार्य समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। आईपी और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और उम्मीद से अधिक कार्य किया। वर्ष 2016–17 बेहद संतोषजनक और पूणकर्ता रहा है। मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2017–18 और भी बेहतर होगा।

(डॉ. एम.एस. साहू)

[1]कोई पर्यावरण में परिवर्तन पर ध्यान नहीं देता और पुरानी प्रणाली से चिपके रहने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जिसे स्पेंसर जॉनसन द्वारा ''हू मूव्ड माय चीज 'में बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है।

ख समीक्षाधीन वर्ष

सूक्ष्म आर्थिक संदर्भ

अवरुद्ध निकास

भारत ने 1990 के दशक में व्यापक आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के सरकारी प्रावधान से बाजार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए राज्य विनियमन की ओर निर्णायक प्रतिमान परिवर्तित किया। उसने आर्थिक कानूनों की एक नई शैली लागू की है, जिससे 'कौन, क्या और कैसे करें' सूची का विस्तार हुआ है, और पूंजी निर्गम ''नियंत्रण'' अधिनियम, 1947 और आयात और निर्यात ''नियंत्रण'' अधिनियम 1947 जैसे अधिनियमों को निरस्त करके आर्थिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया। इनसे आर्थिक स्वतंत्रता के आकार और फलस्वरूप विकास की सीमाओं का विस्तार हुआ। इसने अर्थव्यवस्था में नई फर्मों और नए विचारों के प्रवेश की अनुमति दी और बाजार में गहन प्रतिस्पर्धा और नवाचार (सीएंडआई) को प्रोत्साहित किया।

किसी अर्थव्यवस्था में व्यापक तौर पर विकास[2] के तीन स्रोत[1] होते हैं जिनके नाम (क) कारक वृत्तिदान, (ख) प्रतिस्पर्धा, और (ग) नवप्रवर्तन हैं। जहां सीएंडआई पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम यानी लगभग 40% है, वहां अर्थव्यवस्था विकास के पहले चरण में है, जिसमें आमतौर पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2,000 अमेरिकी डॉलर से कम है। जहां सीएंडआई पर निर्भरता महत्वपूर्ण यानी लगभग 80% है, वहां अर्थव्यवस्था विकास के पांचवें चरण में है, जिसमें आमतौर पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 17,000 अमेरिकी डॉलर है। सीएंडआई का स्तर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2,000 डॉलर से 17,000 डॉलर तक आने के बारे में बहुत कुछ कहता है।

प्रतिस्पर्धा अकुशल फर्मों को चलाने में कुशल फर्मों की मदद करती है, जबकि नवप्रवर्तन पुरानी व्यवस्था को चलाने में नई व्यवस्था की मदद करता है। इस प्रकार, सीएंडआई दोनों में ही फर्मों की विफलता के रोगाणु रहते हैं। सीएंडआई की तीव्रता जितनी अधिक होगी, विफलता की घटनाएं उतनी ही अधिक होंगी। चूंकि सीएंडआई तीव्र आर्थिक विकास और सफलता के लिए आवश्यक हैं, इसलिए बाजार को विफलताओं से चालाकी से निपटना होगा। यह बाजार में विफल रहने वालों (फर्म, उद्यमी, पूंजी और संसाधनों), के लिए कम से कम लागत में बाहर निकलने और अन्य उभरते अवसरों का पता लगाने के लिए आसान होना चाहिए।

किसी अर्थव्यवस्था के दो व्यापक प्रकार के संस्थान होते हैं, अर्थात् समावेशी और निस्सारक संस्थान। समावेशी संस्थान हर किसी को अर्थव्यवस्था में भाग लेने देते हैं, जबकि निस्सारक संस्थान उन्हें रोकते हैं। समावेशी संस्थान प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद की कोई भी आर्थिक गतिविधि(धियां) (व्यवसाय) को उस तरीके से और पैमाने पर करने देते हैं जिसमें वह सहज है। ये उन्मुक्त होते हैं और किसी व्यक्ति को अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन, निवेश और योगदान करने की पूर्ण क्षमता का एहसास कराते हैं। दूसरी ओर, निस्सारक संस्थान शक्ति और अवसर को कुछ के हाथों में केंद्रित करते हैं या व्यक्तियों के एक छोटे समूह की ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। यह जाहिर है, समावेशी संस्थानों के साथ अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकसित होती हैं क्योंकि सबका योगदान कुछ के योगदान से अधिक होता है।

वर्षों से नई फर्में बाजार में प्रवेश और बाजार में प्रतिस्पर्धा करती रहीं हैं तथापि, जो सीएंडआई के समक्ष अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही, उनके पास रचनात्मक विनाश को सीमित करके, व्यवस्थित निकास के लिए एक संरचित मार्ग नहीं था। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद से निकलकर निकास रहित 'बाजारवाद' में प्रतिबंधित प्रवेश कर गई। यह एक प्रकार का चक्रव्यूह था, जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता था, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता था। अवरुद्ध निकास[3] की लागत, यानी 'बीमार' फर्मों को जीवित रखने की लागत निषेधात्मक हो रही थी। इस दशक के मध्य तक व्यवस्थित निकास की आवश्यकता तीव्र हो गई थी। सक्षम निकास मार्ग की चाहत में, कई लोग व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक नहीं थे, और यह समावेशी विकास के रास्ते में बाधक बन रहा था।

इससे भारत में कारोबार करने की आसानी भी प्रभावित हो रही थी। विश्व बैंक करीब 200 अर्थव्यवस्थाओं के कारोबारी विनियमों की अनुकूलता का मापन करता और दस विषयों के संदर्भ में उन्हें, कारोबार करने में उनकी आसानी को रैंक देता है, जिसमें शोधन अक्षमता को हल करना भी शामिल है। 2015 में भारत 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में 142 वें स्थान पर था। शोधन अक्षमता को हल करने के मामले में वह 137वें स्थान पर था। सरकार ने कारोबार करने में आसानी सूचकांक पर शीर्ष 50 स्थान वाले देशों में शामिल होने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, और जहां भी संभव हो, विफल फर्मों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए दिवाला ढांचे की मरम्मत और जहां अपेक्षित हो विफल फर्मों को बंद करने सहित गहन संस्थागत सुधारों की पहल की है।

जुड़वां तुलन पत्र

आम तौर पर उदार क्रेडिट के सहयोग से, उछाल समय के दौरान फर्मों का अति–विस्तार होता है। ऐसे मामलों में, उनका राजस्व अक्सर ऋण सेवा दायित्वों से मेल नहीं खाता है और उनका तुलन पत्र खिंच जाता है। जैसे–जैसे वे अपने ऋणों पर चूक करते जाते हैं, बैंकों का तुलन पत्र भी खिंचता जाता है। इससे ऐसी स्थिति बनती है जिसमें तानित तुलन पत्र वाली फर्में निवेश करने की इच्छुक नहीं रहतीं, जबकि अन्य फर्में निवेश नहीं कर पाती क्योंकि तानित तुलन पत्र वाले बैंक उन्हें उधार देने में सक्षम नहीं होते हैं। विस्तार के लिए उधारी में वृद्धि के बाद ऋण की अदायगी में कठिनाइयां, विशिष्ट जुड़वां तुलन पत्र (टीबीएस) समस्या, प्रगति को बाधित करती है।

2000 के दशक के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था 9–10% वार्षिक[4] की वृद्धि दर से बढ़ रही थी। वैश्विक वित्तीय संकट के साथ सहानुभूति में एक संक्षिप्त व्यवधान के बाद, 2009 से 2011 तक विकास दर में लगभग 8.5% सुधार हुआ। अनुमानित दोहरे अंकों की विकास दर के चलते फर्मों ने, क्रेडिट उछाल द्वारा, भारी निवेश किया। आर्थिक प्रगति और ऋण वृद्धि के बीच यह दोहरा सकारात्मक सहसंबंध है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी'ज) द्वारा गैर–खाद्य ऋण 2011–12 में 17%, 2012–2014 में औसतन 13% और

[2]विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, 2015–2016। इसमें अर्थव्यवस्था को उसके विकास के चरण के अनुसार पांच वर्गों में वगीकृत किया गया है।
[3]भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2015–16
[4]डेटा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया

2014–2017[5] में औसतन 8.6% बढ़ा। गैर–खाद्य ऋण से जीडीपी (स्थिर कीमतों पर) अनुपात 2010–11 से 2016–17 तक औसतन 55% रहा है। एससीबी की सकल अग्रिम राशि 31 मार्च, 2008 को 25,03,431 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को 68,75,748 करोड़ रुपये हो गई।

चूंकि फर्में अधिक निवेश कर रही थीं और अधिक ऋण ले रही थीं, बातें गलत[6] होने लगीं। आर्थिक सर्वेक्षण, 2015–16 में इसके तीन कारण बताए गए हैं। लागतें बजटीय स्तर से काफी बढ़ गई क्योंकि विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करना बहुत कठिन और समय खपाऊ साबित हुआ। वास्तविक विकास दर के अनुमानित दो अंकों की विकास दर से कम होने के कारण राजस्व में कमी आई। मुद्रास्फीति के अनुरूप बैंक दर बढ़ने के कारण वित्तीय लागत में वृद्धि हुई। उच्च लागत, कम राजस्व और अधिकाधिक वित्तपोषण लागतों ने नकदी प्रवाह को निचोड़ दिया, जिससे ऋण की अदायगी में कठिनाइयां आईं। 2013 तक, कारपोरेट ऋण का एक तिहाई 1 से कम ब्याज कवरेज दर (आईसीआर) वाली फर्मों पर बकाया था। 2015 तक, ऐसी फर्मों की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई। 2010–11 से 2015–16 के दौरान शीर्ष 10 तनावग्रस्त कारपोरेट समूहों के ऋण तिगुने हो गए। फर्में समायोजन और लेनदारों को उन्हें ऋण की अदायगी के लिए और अधिक समय देने और, कई मौकों पर, तनावग्रस्त फर्मों की तत्काल परेशानियों का सामना करने के लिए नई निधि जारी करने के लिए बाध्य करना चाहती थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई, 2015 में एक परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) आयोजित की, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में तीव्र वृद्धि हुई, जो मार्च, 2013 में सकल अग्रिम 3.2% से बढ़कर मार्च 2015 में 4.3%, और सितंबर, 2016 में 9% तक हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में यह 12% थी। घरेलू प्रचालनों में, एससीबी के सकल एनपीए, 31 मार्च, 2014 को 2,63,015 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को 7,90,268 करोड़ रुपये हो गए। इस प्रकार, ऋण में वृद्धि के बाद एनपीए में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप ऋण वृद्धि में 2011–12 में 17% से 2014–16 में 9% तक की उल्लेखनीय गिरावट आई। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में तेजी के प्राथमिक कारणों में अन्य बातों के अलावा, आक्रामक ऋण प्रथाएं, कुछ मामलों में इरादतन चूक/ऋण में धोखाधड़ी और आर्थिक मंदी शामिल हैं। चित्र 1 में 2011–12 के बाद से सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू उत्पाद, क्रेडिट और सकल एनपीए की वृद्धि दर को दर्शाया गया है।

उच्च एनपीए ने बैंकों की, विशेष रूप से पीएसबी में, लाभप्रदता को क्षीण किया और नए ऋण देने में बाधा डाली। कई फर्मों ने 1 से कम के आईसीआर की रिपोर्ट की, जिसका अर्थ है कि उनके पास अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं थी। इसने अपने तुलन पत्रों का अधिक फायदा उठाने के लिए बैंकों के तुलन पत्र को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा की गई एक्यूआर और उसके उपरांत पीएसबी द्वारा एनपीए की पारदर्शी पहचान से प्रभावित खातों का, एनपीए के तौर पर, पुनर्वर्गीकरण किया गया, ताकि प्रभावित ऋणों पर अपेक्षित नुकसान, जिनका पहले प्रावधान नहीं किया गया था, का प्रावधान किया गया। समस्या लगातार बनी रही[7], एनपीए बढ़ता रहा, जबकि क्रेडिट और निवेश गिरता रहा – जो बढ़ते टीबीएस का एक लक्षण था **(बॉक्स 1)**।

चित्र 1: सकल घरेलू उत्पाद, ऋण और एनपीए की वृद्धि

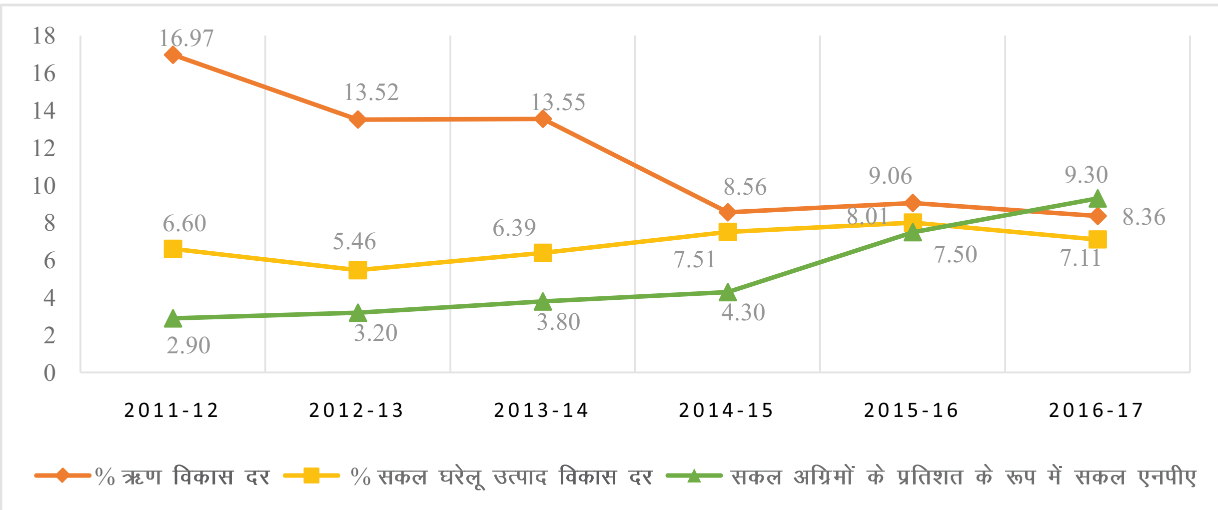

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक डेटाबेस

बढ़ते टीबीएस और निकास की बाधित लागत की पृष्ठभूमि में, एक प्रभावी शोधन अक्षमता कानून, जो एनपीए को हल करने और प्रभावित परिसंपत्तियों के तीव्र और लागत प्रभावी समाधान को सक्षम करके क्रेडिट उपलब्धता में सुधार कर सके, समय की मांग थी।

शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति

ऋण चूक से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ तालमेल नहीं रखा। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के माध्यम से या बैंकों और वित्तीय संस्थानों की देयताओं की वसूली अधिनियम, 1993

[5] आरबीआई डेटाबेस
[6] भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2015–16
[7] भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2016–17

(आरडीडीबीएफआई) और प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परियसंपत्तियों के पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) जैसे विशेष कानूनों के माध्यम से, लेनदारों द्वारा वसूली की कार्रवाई ने वांछित परिणाम नहीं दिए। इसी तरह, सूक्ष्म औधोगिक कंपनीज (विषेष प्रवधान) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन प्रावधानों के माध्यम से कार्रवाई उधारदाताओं द्वारा वसूली या फर्मों के पुनर्गठन के लिए बहुत मददगार साबित नहीं हो रही थी। इसके अलावा, व्यक्तिगत दिवाला से संबंधित कानून जैसे प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 उस समय की बदलती जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसने उधारदाताओं, परिणामस्वरूप ऋण बाजार, के विश्वास को बाधित किया। जबकि बैंकों से प्रतिभूत ऋण क्रेडिट का प्रभावी रूप था, कारपोरेट ऋण बाजार को विकसित[8] करना बाकी था।

कोड के अधिनियमन से पहले, दिवाला परिदृश्य कई अतिव्यापी कानूनों – केंद्रीय और प्रांतीय – के साथ ही बिना किसी समन्वय के अलग–अलग लागू की गई गैर–सांविधिक योजनाओं के कारण अत्यधिक विखंडित था। लेनदार और दिवाला के तहत कर्जदार की शक्तियों का प्रावधान अलग–अलग कानूनों के तहत प्रदान किया गया। दिवाला के समाधान में लेनदारों और देनदारों के हितों के बीच संघर्ष को देखते हुए, स्थिरता और सक्षमता की संभावना कम थी। इसके अलावा, विभिन्न न्यायिक मंचों में अलग–अलग कानून लागू किए गए। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अधिकरण/बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा निर्णीत मामले अक्सर उच्च न्यायालयों की समीक्षा के लिए आते हैं। इसने समाधान ढांचे के कार्यान्वयन में दो प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। पहली, क्षेत्राधिकार की स्पष्टता की कमी थी। ऐसी स्थिति में जहां एक मंच लेनदार के अधिकारों से संबंधित मामलों पर निर्णय करता है, जबकि दूसरा कर्जदार के अधिकारों से संबंधित मामलों पर निर्णय करता है, जिनके खिलाफ अपील की गई और उन्हें उच्च न्यायालय में या तो स्थगन दिया गया या पलट दिया गया। दूसरे, दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामले सौंपे गए मंचों के पास ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए व्यवसाय या वित्तीय विशेषज्ञता, सूचना या बैंडविड्थ नहीं था। इससे परिणाम आने में देरी और समय का विस्तार हुआ और परिणाम के खिलाफ अपील करने के लिए भेद्यता बढ़ गई। उदाहरण के लिए, एसआईसीए बीमार फर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए अधिनियमित किया गया, बिना इस बात पर खास ध्यान दिए कि वे व्यवहार्य थे या नहीं। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद, यह कर्जदार के चारों ओर सुरक्षा का कार्य करता था, जो लेनदारों को अनिश्चित तौर पर वसूली करने से रोकता था।

पूर्ववर्ती प्रणाली में विलंब और खराब परिणाम के लिए जिम्मेदार कई कारकों में शामिल हैं: (i) प्रबंधकीय विलंब कार्यनीति, (ii) अदालत की मंजूरी की आवष्यकता और अदालतों के पास प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप करने का उपलब्ध विवेक, अधिकार और (iii) संसाधनों, न्यायाधीशों और अच्छे प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या के संदर्भ में संस्थागत क्षमता का अभाव, (iv) परिसमापन में वितरण के लिए जटिल प्राथमिकता व्यवस्था, (v) बचाव के दौरान ऋण प्रवर्तन पर देनदारों द्वारा रोक का दुरुपयोग; (vi) अदालतों और सहायक निकायों के पुनर्वास संबंधी दृष्टिकोण, अव्यवहार्य व्यवसायों के मामले में भी, (vii) व्यवस्था की योजनाओं के माध्यम से बचाव में कुछ लेनदारों द्वारा पकड़ और लेनदारों के साथ समझौता, (viii) राज्य के स्वामित्व के लेनदारों द्वारा निर्णय लेने में देरीं, और (ix) एक ही कानून एवं संधर्ष हेतु विभिन्न कानूनों में विस्तार बहुलता से समान कार्रवाई और कानूनी कार्यों की बहुलता।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, 10 जुलाई, 2014 को 2014–15 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहाः *"एसएमई के लिए आसान निकास को सक्षम बनाने के लिए उद्यमी अनुकूल कानूनी शोधन अक्षमता ढांचा भी विकसित किया जाएगा।"* इस घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में कारपोरेट शोधन अक्षमता के लिए कानूनी ढांचे का अध्ययन करने के लिए 22 अगस्त, 2014 को डॉ टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक शोधन अक्षमता कानून सुधार समिति (बीएलआरसी) का गठन किया गया।

बीएलआरसी ने 11 फरवरी, 2015 को एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की। 28 फरवरी, 2015 को 2015–16 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहाः

"शोधन अक्षमता कानून में सुधार, जो कानूनी निश्चितता और गति देने वाला है, को व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया है। सिका (बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम) और बीआईएफआर (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। हम वित्तीय वर्ष 2015–16 में एक व्यापक शोधन अक्षमता कोड लाएंगे, जो वैश्विक मानकों को पूरा करेगा और आवश्यक न्यायिक क्षमता प्रदान करेगा।"

बीएलआरसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 नवंबर, 2015 को दो भागों में प्रस्तुत कीः खंड 1 में विधान के लिए औचित्य और डिजाइन का विवरण, और खंड 2 में मसौदा दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक का सुझाव दिया गया है। इसने नए दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान ढांचा प्रस्तावित किया जो (क) बहुत प्रारंभिक चरण में उद्यम की व्यवहार्यता के आकलन की सुविधा प्रदान करता है; (ख) लेनदारों और देनदारों के बीच सूचना की समरूपता को सक्षम करता है; (ग) आर्थिक मूल्य को बेहतर बनाए रखने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करता है; (घ) एक सामूहिक प्रक्रिया का उपयोग करता है; (ङ) सभी लेनदारों के अधिकारों का समान रूप से सम्मान करता है; (च) यह सुनिश्चित करता है कि, जब

[8] वित्त मंत्रालय, प्रेस विज्ञप्ति, 2016, 11 मई दिनांकित।

बॉक्स 1 जुड़वां तुलन पत्र लक्षण का समाधान

टीबीएस लक्षण से निपटने के लिए मोटे तौर पर तीन दृष्टिकोण हैं: (क) फर्मों की आपदाग्रस्त तुलन पत्र में इक्विटी, (ख) बैंकों के आपदाग्रस्त तुलन पत्र में ऋण, और (ग) फर्मों के आपदाग्रस्त तुलन पत्र में इक्विटी और बैंकों के आपदाग्रस्त तुलन पत्र में ऋण।

(क) फर्मों का तुलन पत्रः प्रतिभूति बाजार प्राथमिक बाजार के माध्यम से सबसे सक्षम उपयोग के लिए पूंजी आवंटित करता है। प्राथमिक बाजार के माध्यम से किसी फर्म को पूंजी आवंटित किए जाने के बाद, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फर्म हमेशा सर्वोत्तम संभावित प्रतिफल देगी। यदि यह विफल होती है, तो कारपोरेट नियंत्रण के लिए बाजार, जिसे आम तौर पर अधिग्रहण के रूप में जाना जाता है, फर्मों/उत्पादक परिसंपत्तियों को – चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में – अधिक आशाजनक इक्विटी आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित करता है, जो मौजूदा इक्विटी मालिकों से फर्म की बागडोर ले लेते हैं। यह इक्विटी से संबंधित सौदा है, जो अक्सर मौजूदा और संभावित इक्विटी मालिकों के बीच, राज्य की नगण्य भूमिका सहित एक नियामक ढांचे के तहत होता है। यह दो तरीकों से फर्म के कार्यनिष्पादन में सुधार करता हैः सबसे पहले, यह फर्म को अधिग्रहण किए जाने के लिए भेद्यता होने से बचने के लिए इसकी क्षमता से नीचे संचालन करने से रोकता है और दूसरी ओर, यह फर्म के अधिग्रहण के माध्यम से अधिक कुशल प्रबंधन पेश करता है। इस प्रकार, अधिग्रहण सतत् आधार पर पूंजी में उच्च प्रतिफल में योगदान देता है और परिणामस्वरूप, फर्मों के तुलन पत्र में सुधार करता है। हालांकि, ज्यादातर कंपनियों के लिए, खास तौर पर गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट नियंत्रण का बाजार दिखाई नही देता। असूचीबद्ध फर्मों पर नियंत्रण के लिए एक विनियमित बाजार के न होने से, मौजूदा इक्विटी मालिक औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से अधिग्रहण का विरोध करते हैं। इसके अलावा, संभावित इक्विटी आपूर्तिकर्ता अक्सर विभिन्न बाजार खामियों खास तौर पर नगण्य इक्विटी मूल्य वाले प्रभावित तुलन पत्र के कारण अवसर का लाभ उठाने में विफल होते हैं। कारपोरेट नियंत्रण के लिए एक प्रभावी और विकसित बाजार न होने से, फर्म के तुलन पत्र में संकट जाहिर हो जाता है यदि इसका व्यवसाय गहन सीएंडआई में प्रकट हो जाता है।

(ख) बैंकों का तुलन पत्रः यह ऋण से संबंधित सौदा है, जो अक्सर एक विनियामक ढांचे के तहत होता है और कई बार, बैंक और फर्म के मौजूदा इक्विटी मालिकों के बीच चुकौती योजना के पुनर्गठन के लिए राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके कई प्रकार होते हैं: (i) ऐसी कई पुनर्गठन योजनाएं हैं जैसे कि कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर), नीतिगत ऋण पुनर्गठन (एसडीआर), प्रभावित परिसंपत्तियों की सतत संरचना की योजना (एस4ए) इत्यादि, जिनका ऋण की अवधि को बढ़ाने या चूक को मान्य नहीं करने में, कई बार प्रयोग किया जाता है। इससे बैंकों की आगे उधार देने की क्षमता में सुधार के बिना तुलन पत्र की दृश्यता में सुधार होता है। बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) ने बीमार व्यवसायों के पुनर्गठन के लिए एक सुविधा प्रदान की। इस तरह मामलों को बंद करने में काफी लंबा समय लगा और इसे ऋण की वसूली के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए उपयोग किया गया। (ii) बैंक एनपीए को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) सहित, अधिग्राहकों को बेचते हैं, जो इन परिसंपत्तियों को बैंकों के तुलन पत्र से हटाते हैं, उन्हें संग्रह बोझ और परिसंपत्ति प्रावधान से छुटकारा दिलाते हैं, और पूंजी को नए ऋण के लिए मुक्त करते हैं। एनपीए के अधिग्राहक बैंकों की जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि, वे अक्सर अपने द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों में बदलाव लाने में विफल रहे और उन्हें उन परिसंपत्तियों की बिक्री करनी पड़ी जिनके मूल्य इस बीच में कम हो गए। खरीद के लिए चुकाई गई रकम भी अधिक आकर्षक नहीं रही। निर्दिष्ट ऋण खरीदने और उन पर काम करने[8] – वाणिज्यिक सिद्धांतों पर बड़े संदिग्ध ऋणों को एक निर्दिष्ट, यथोचित समय अवधि के भीतर अधिकतम वसूली के स्पष्ट अधिदेश के साथ हल करने के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी' बनाने का प्रस्ताव किया गया। कोशिश करने से पहले विचार छोड़ दिया गया। ऋणों के व्यापार के लिए द्वितीयक बाजार बहुत तरल नहीं है और बैंकों द्वारा ऋण की बिक्री का सीमित प्रभाव था। (iii) एक अन्य प्रकार, लोक अदालतों के माध्यम से समाधान, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के माध्यम से वसूली, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत बिक्री है। ये माध्यम समय खपाऊ साबित हुए, इनसे लेनदारों की बातचीत की शक्ति कमजोर हुई और उन्हें किसी भी प्रकार के निपटान को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। परिणामस्वरूप, अक्सर हजामत के घाव काफी गहरे होते थे।

(ग) फर्मों और बैंकों के तुलन पत्रः पहले के दो दृष्टिकोणों में फर्म के मौजूदा इक्विटी मालिकों से लेनदेन निहित था। परिणाम उत्साहजनक नहीं होता था क्योंकि वे सहयोग नहीं करते थे, क्योंकि उनके हित लेनदारों के हितों से टकराते थे। इसका तरीका संभावित इक्विटी मालिकों को इस प्रक्रिया में शामिल करना था, जो फर्म के व्यवसाय को पुनर्गठित करने के लिए मौजूदा इक्विटी मालिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करे और साथ ही साथ बाजार द्वारा पेश की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना के माध्यम से लेनदारों को फिर से पुनर्गठन को मंजूरी देने के लिए सशक्त करे। यह दृष्टिकोण ऋण और इक्विटी दोनों को एक विनियामक ढांचे के तहत और सरकारी सुविधा के साथ, बैंक और संभावित इक्विटी मालिकों के बीच व्यापार के पुनर्गठन के लिए सौदा प्रदान करता है, जो फर्म के तुलन पत्र में तनाव को कम करता है, जिसके साथ चुकौती योजना के पुनर्गठन के साथ, बैंक के तुलन पत्र में तनाव को भी कम करता है। यह अनिवार्य रूप से प्रभावित संपत्ति के लिए बाजार के विकास के लिए एक रूपरेखा है, जो बाजार को बाजार की समस्या का समाधान खोजने देता है। प्रभावित परिसंपत्ति के लिए विकसित बाजार आमतौर पर एनपीए के खतरे से निपटने का एक प्रभावी साधन है। यह कारपोरेट पुनर्गठन का समर्थन और वित्तपोषण के स्रोतों का विस्तार करता है। यह कारपोरेट पुनर्गठन में सहायता करने के लिए संस्थागत निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है,

[8]पूर्वोक्त

जैसे कि निजी इक्विटी फंड, उद्यम पूंजीपति, परिसंपत्ति प्रबंधक, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड। ये संस्थागत निवेशक वित्त के गैर–बैंक स्रोतों के विस्तार में सहायता करते हैं। समय के साथ, प्रभावित ऋण बाजार को अधिक व्यापक तौर पर, अधिक उत्पादक कारपोरेट्स की ओर संसाधनों के पुनःआवंटन और उनके पुनर्गठन और विस्तार[10] में सहायता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसके लिए एक ठोस विधिक और विनियामक ढांचा, विशेष दिवालिया अदालत, प्रभावित फर्मों के खिलाफ दावों का पदानुक्रम, अंतरिम में व्यवसाय चलाने के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर और समाधान योजनाओं के डिजाइन के लिए हितधारकों को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने, और एक समय सीमा के भीतर परिस्थितियों में सर्वोत्तम परिणाम के लिए निर्णय लेने और प्रोत्साहनों और दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए लेनदारों का सशक्तिकरण आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में, एक मजबूत दिवाला ढांचा प्रभावित संपत्ति के लिए जीवंत बाजार विकसित करने की कुंजी है, जो फर्मों और बैंकों के तुलन पत्र में तनाव से राहत देता है। तालिका 1 में इन तीन दृष्टिकोणों की विशिष्ट विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1: जुड़वां तुलन पत्र लक्षण का समाधान करने के दृष्टिकोण

विवरण	दृष्टिकोण क	दृष्टिकोण ख	दृष्टिकोण ग
सौदों का दायरा	इक्विटी	ऋण	इक्विटी और ऋण
सौदा किसके बीच	मौजूदा इक्विटी मालिक और संभावित इक्विटी	मालिक लेनदार और मौजूदा इक्विटी	मालिक लेनदार और मौजूदा और संभावित दोनों इक्विटी मालिक
सरकार की भूमिका	नगण्य	परोक्ष। समय पर पर्याप्त	इक्विटी समन्वयक
किसके तुलन पत्र में तनाव का समाधान	फर्में	बैंक	फर्में और बैंक

बातचीत व्यवहार्यता स्थापित करने में विफल रहती है, तो शोधन अक्षमता का परिणाम बाध्यकारी होना चाहिए; और (च) प्राथमिकता की स्पष्टता प्रदान करता है, और शोधन अक्षमता को हल करने में सभी हितधारकों के अधिकारों को बरकरार रखा जाता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016

बीएलआरसी की सिफारिशों के आधार पर, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड से संबंधित एक विधेयक दिसंबर, 2015 में संसद में पेश किया गया। 28 अप्रैल, 2016 को लोकसभा और 11 मई, 2016 को राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने 11 मई, 2016 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आकलन किया गया:

"आज का दिन भारत में आर्थिक सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब राज्यसभा ने सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख आर्थिक सुधार विधेयक, यानी "दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016" को पारित कर दिया। इसे केवल जीएसटी से अगला सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है।"

कोड को 28 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया।

इस प्रकार दिवाला और शोधन अक्षमता कोड ऐसा व्यापक और प्रणालीगत सुधार है, जो क्रेडिट बाजार के कामकाज को एक काफी बढ़त देगा। यह भारत को अपेक्षाकृत कमजोर शोधन अक्षमता प्रणालियों से हटाकर दुनिया की एक सबसे अच्छी शोधन अक्षमता प्रणाली बनाएगा। इसने कारपोरेट बांड बाजार के विकास की नींव रखी है, जिससे भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषण प्राप्त होगा। इस कोड के पारित होने और इसके कार्यान्वयन से भारत में व्यापार करने की आसानी को बढ़ावा मिलेगा।"

उक्त विधेयक से संलग्न 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' संक्षिप्त रूप से कोड का औचित्य निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है:

"भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित हो। कंपनियों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली, अधिनियम 1993, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 में पाए जा सकते हैं। इन कानूनों में कई मंचों जैसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान किया गया है। कंपनियों के परिसमापन का प्रबंधन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत शोधन अक्षमता और दिवाला का निपटान प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत न्यायालयों द्वारा किया जाता है। दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए मौजूदा ढांचा अपर्याप्त, अप्रभावी है और इसके परिणामस्वरूप समाधान में देरी होती है, इसलिए कानून प्रस्तावित किया जाता है।"

भारत में मध्यस्थता और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की राष्ट्रीय पहल पर 23 अक्टूबर, 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधनः

"इस दिशा की ओर, हमने दूरगामी कानूनी सुधार शुरू किए हैं। एक हजार से अधिक पुरातन कानूनों को खत्म कर दिया गया है। हमने एक व्यापक दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 लागू किया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण लागू किया है ... । शोधन अक्षमता कोड के साथ ही, बदलते क्रेडिट परिदृश्य के अनुकूल बनने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए हमने इस साल सरफेसी और डीआरटी अधिनियमों में संशोधन किया है।"

[10] आईएमएफ वर्किंग पेपर नंबर नं. डब्ल्यूपी/15/24, "इटली में गैरनिष्पादक ऋण के लिए एक बाजार विकसित करने की रणनीति" नादेज जसौद और केनेथ कांग, फरवरी, 2015

इनस्क्रिप्ट 1: दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 लागू किया जाना

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 37] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 2016/ ज्येष्ठ 7, 1938 (शक)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 2016/JYAISTHA 7, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28th May, 2016/*Jyaistha* 7, 1938 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th May, 2016, and is hereby published for general information:—

THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

No. 31 of 2016

[28*th May*, 2016.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximisation of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interests of all the stakeholders including alteration in the order of priority of payment of Government dues and to establish an Insolvency and Bankruptcy Board of India, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

PART I

Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Code may be called the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

(*2*) It extends to the whole of India:

Provided that Part III of this Code shall not extend to the State of Jammu and Kashmir.

(*3*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

कोड कंपनियों और सीमित देयता संस्थाओं {सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) और सीमित देयता वाली अन्य संस्थाओं सहित}, असीमित देयता भागीदारी और व्यक्तियों के दिवाला से संबंधित, वर्तमान में अनेक विधानों में निहित, कई कानूनों का एक विधान में समेकन करता है। ऐसे समेकन का उद्देश्य कानून में अधिक स्पष्टता प्रदान करना और व्यवसाय की विफलता या कर्ज का भुगतान करने में असमर्थता से प्रभावित विभिन्न हितधारकों के लिए संगत और सुसंगत प्रावधानों के अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिए, कोड में प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रावधान है और इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013, आरडीडीबीएफआई और सरफेसी सहित 11 विधानों में संशोधन किया गया है। कोड के प्रावधान अन्य कानूनों का उस सीमा तक अध्यारोहण करते हैं, जहां ऐसा अन्य कानून कोड से असंगत हो।

कोड की मुख्य विशेषताएं

(क) *उद्देश्य:* जैसा कि इसके विस्तृत शीर्षक में कहा गया है, कोड का उद्देश्य पुनर्गठन और संबंधित फर्म की संपत्ति का अधिकतम मूल्य दिलाने, उद्यमशीलता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और उसके सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए, समयबद्ध तरीके से, कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का दिवाला समाधान करना है।

(ख) *प्रयोज्यता:* कोड दिवाला के कानूनों का समेकन करता है और कंपनियों, एलएलपी फर्मों, अन्य निकाय कंपनियों, व्यक्तिगत गारंटरों, साझेदारी फर्मों, मालिकाना फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होता है। तथापि, यह वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए लागू नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो खास तौर से प्रक्रियाओं द्वारा शामिल किए जाने के तौर पर अधिसूचित हैं।

(ग) *संस्थागत ढांचा:* कोड द्वारा स्थापित संस्थागत बुनियादी ढांचे के चार स्तंभ इसका एक प्रमुख नवप्रवर्तन हैं। इनमें से पहला स्तंभ विनियमित व्यक्तियों, दिवाला पेशेवरों (आईपी) की एक श्रेणी है। वे दिवाला, परिसमापन और दिवाला प्रक्रियाओं के कुशल कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा स्तंभ आईयू का एक नया उद्योग है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उधारदाताओं और ऋण देने की शर्तों के बारे में तथ्यों का संग्रहण करते हैं और चूक होने पर देरी और तथ्यों के बारे में विवादों को समाप्त करते हैं। तीसरा सहायक प्राधिकरण अर्थात, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) उस फोरम के रूप में कार्य करता है जिसमें कारपोरेट दिवाला की सुनवाई की जाती है और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरटी) में व्यक्तिगत दिवाला की सुनवाई की जाती है। चौथा स्तंभ विनियामक अर्थात, आईबीबीआई है जो आईपी, आईपीए और आईयू पर विनियामक निगरानी रखता है और कोड के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कोड की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

कोड की अन्य विशेषताऐं हैं:

(घ) *प्रक्रिया:* कोड एक रैखिक, सामूहिक प्रक्रिया स्थापित करता है जो देनदार, लेनदार और अन्य सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है। कारपोरेट दिवाला के मामले में, यह लेनदारों को कारपोरेट देनदार (सीडी) की व्यवहार्यता का आकलन करने का मौका प्रदान करता है। सीआईआरपी का समापन विफल सीडी के पुनर्वास या सीडी के परिसमापन की शुरूआत की समाधान योजना से होता है। व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही या तो एक नए सिरे से शुरूआत की प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप अर्हक ऋणों को बट्टे खाते डाला जाता है या दिवाला समाधान प्रक्रिया जिसमें देनदारों को भुगतान के लिए बातचीत करने का मौका दिया जाता है, के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। कोई शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जिसमें देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री निहित है, दिवाला समाधान प्रक्रिया की विफलता पर उत्पन्न हो सकती है।

(ङ) *समय–सीमा:* कोड दिवाला के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित करता है। उदाहरण के माध्यम से, कारपोरेट व्यक्ति के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को 270 दिनों के भीतर (नब्बे दिनों तक के एकबारगी विस्तार सहित) समाप्त करना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह, व्यक्तिगत गारंटरों, साझेदारों और मालिकाना कंपनियों और व्यक्तियों (व्यक्तिगत दिवाला) के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर समाप्त होनी है।

(च) *नियंत्रण:* सीआईआरपी शुरू होने के बाद, सीडी का प्रबंधन आईपी के हाथों में निहित हो जाता है, जो निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करता है। यह सूचना समरूपता सुनिश्चित करता है, सीडी की व्यवहार्यता के निष्पक्ष मूल्यांकन को सक्षम बनाता है और सीआईआरपी के लंबित रहने के दौरान सीडी के मूल्य को एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में संरक्षित करने में मदद करता है।

(छ) *अपराध और शास्तियां:* कोड में कुछ अपराधों और दंडों के लिए विशेष न्यायालय का निर्धारण किया गया है जो कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करने की आईबीबीआई या सरकार द्वारा शिकायत पर अपराधों की जांच करता है।

कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया

कारपोरेट प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान 1 दिसंबर, 2016 को लागू हुए। कोड में मोटे तौर पर तीन कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं – सीआईआरपी, कारपोरेट परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, का प्रावधान किया गया है। इन प्रक्रियाओं का विवरण इस रिपोर्ट के खंड–ग में वर्णित है। कोड में, इसकी शक्तियों की पूर्ववर्ती व्यवस्था से वंचित करके, इसमें समाधान योजना तैयार होने तक फर्म के व्यवसाय को एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने के लिए, एक स्वतंत्र पेशेवर की शक्तियां निहित की गई हैं। उसके बाद प्रबंधन को अनुमोदित समाधान योजना के तहत सौंप दिया जाता है, ताकि फर्म अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने ऋणों का भुगतान कर सके। यह सब 180 दिनों की अवधि के भीतर किया जाता है, जिसमें 90 दिनों तक एकमुश्त विस्तार दिया जाता है या फिर परिसमापन प्रक्रिया शुरू होती है।

बोर्ड एक व्यापक और प्रणालीगत सुधार है जिसका उद्देश्य देश में दिवाला के परिदृश्य को बदलना है। पूर्ववर्ती व्यवस्था की तुलना में प्रमुख परिवर्तन, तालिका 2 में संक्षेप में दिए गए हैं।

तालिका 2: कारपोरेट प्रक्रियाओं के संबंध में आईबीसी–पूर्व बनाम आईबीसी व्यवस्था

आधार	आईबीसी–पूर्व व्यवस्था	आईबीसी व्यवस्था
संस्थागत ढांचा	दिवाला के मामलों के निपटान के लिए कई कानून (सिविलएकल कानून, एसआईसीए, आरडीडीबीएफआई, सरफेसी, आदि) और कई मंच (सिविल कोर्ट, डीआरटी, बीआईएफआर, उच्च न्यायालय) थे।	एकल कानून में कारपोरेट व्यक्तियों की दिवाला प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान है। एनसीएलटी कारपोरेट दिवाला के लिए एए है।
दृष्टिकोण	यह आमतौर पर पूर्व–व्यापी थी। यह प्रक्रिया चूक होने के बाद शुरू होती है।	यह अधिकांशतः प्रत्याषित है। यह चूक को रोकने का प्रयास करती है इसमें रोकथाम के बावजूद चूक होने पर प्रक्रिया का प्रावधान
उद्देश्य	अधिकांश विधानों में वसूली की परिकल्पना थी। सिका ने पुनर्गठन की परिकल्पना की थी। हालांकि, अक्सर वसूली को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता था।	कोड का उद्देश्य फर्म को अपने स्वयं के प्रबंधन और परिसमापन से बचाकर फर्म का पुनरुद्धार और उसे जारी रखना है। यह परिसमापन या वसूली नहीं है।
शुरुआत	सिका के तहत बीमार होने वाली फर्म पर हितधारक, सरकार, आरबीआई, आदि द्वारा आवेदन पर प्रक्रिया शुरू की जाती थी। ऋण चुकाने में असमर्थता के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिसमापन शुरू किया जाता था।	सीआईआरपी किसी एफसी, ओसी या सीडी द्वारा, देहली राशि की चूक होने की स्थिति में शुरू किया जाता है। परिसमापन, सीआईआरपी के समापन पर ही शुरू होता है। तथापि, विलायक सीडी सीधे स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर सकता है।
समाधान के दौरान नियंत्रण	सिका के तहत, और गैर–सांविधिक ऋण पुनर्गठन योजनाओं में, देनदार का शोधन अक्षम फर्म (कब्जेदार देनदार) के मामलों पर नियंत्रण जारी रहता था, जबकि देनदार के दिवाला के समाधान पर बातचीत की जाती थी।	यह 'लेनदार की नियंत्रण' व्यवस्था है, जिसमें एक स्वतंत्र आईपी, एफसी से गठित सीओसी के मार्गदर्शन में सीडी के मामलों का प्रबंधन करता है।
व्यवसायीकरण	कोई विनियमित सेवाएं और विनियामक नहीं थे।	इसमें आईपी, आईपीए और आईयू जैसे विनियमित उद्योग और पेशे हैं। विनियामक यानी आईबीबीआई प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के नियम लिखता है और सेवा प्रदाताओं का संचालन नियंत्रित करता है।
अधिस्थगन	सीडी के खिलाफ निरंतर मुकदमे जारी रहने से समाधान प्रक्रिया को पटरी से उतर गई। यद्यपि सिका ने अधिस्थगन का प्रावधान किया था, इसका उपयोग वसूली को रोकने के लिए किया गया।	कोड में समाधान अवधि के दौरान संस्था पर अधिस्थगन या फर्म के खिलाफ मुकदमा या कार्यवाही जारी रखने की परिकल्पना की गई है। इसमें फर्म को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के निलंबन या समाप्ति पर रोक लगाई गई है।
निर्णय लेना	सिका के तहत, बीआईएफआर वाणिज्यिक मामलों का निर्णय लेता था। इसके अलावा, कब्जेदार देनदार के दृष्टिकोण के कारण, निर्णय लेने में देनदार का अनुचित हस्तक्षेप रहता था।	यह कोड सीडी के हितधारकों और एए को उनके संबंधित महत्वाकांक्षी मामलों में तेजी से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। सीओसी एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में सीडी की व्यवहार्यता निर्धारित करता है और इसके दिवाला के समाधान का तरीका तय करता है। सभी प्रमुख निर्णयों के लिए सीओसी का अनुमोदन अपेक्षित होता है।
समय सीमा	यह समयबद्ध प्रक्रिया नहीं थी। असामान्य विलम्ब प्रत्येक कार्यवाही की विशेषता रही, जिससे समाधान मुश्किल हो गया।	कोड में समयबद्ध तरीके से समाधान प्रक्रिया को बंद करने का अधिदेश है और इसलिए, मूल्य के संरक्षण में सहायता करता है।
एलआईएस	यह अक्सर लेनदार और देनदार के बीच एक लिस होता है। इसके अलावा, देनदार और लेनदारों के हितों में अक्सर टकराव हुआ और इसलिए, उन्होंने विपरीत उद्देश्यों से कार्य किया। कई बार, लेनदारों के हित परस्पर समाधान के आड़े आ जाते हैं।	कोड देनदार के दिवाला के समाधान के लिए लेनदारों को अधिकार देता है। यह देनदार और लेनदार के बीच एक लिस नहीं है। यह समाधान के लिए प्रयास करने का एक सामूहिक तंत्र है।
जल-प्रपात में प्राथमिकता	परिसमापन जलप्रपात में, सरकार सूची में सबसे ऊपर रहती थी।	परिसमापन जलप्रपात में, सरकार सूची में सबसे नीचे है, केवल इक्विटी से ऊपर।
परिसमापन के दौरान प्रबंधन	कंपनी अधिनियम के तहत, सीडी की परिसंपत्तियों को आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय द्वारा निपटाया जाता था, जिन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा नियुक्त किया गया था।	एक आईपी एनसीएलटी की देखरेख में, परिसमापक के रूप में सीडी की परिसंपत्तियों से संबंधित कार्य करता है।
सीमा–पारीय दिवाला	हालांकि सीमा–पारीय दिवाला से संबंधित मामले सिविल प्रक्रिया कोड, 1908 के तहत अदालतों के समन्वय के लिए सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार नियंत्रित किए जाते थे और अदालतों द्वारा लागू किए गए सामान्य कानूनी सिद्धांत, सीमा–पारीय दिवाला के प्रबंधन को नियंत्रित करते थे, भारत में सीमा–पारीय दिवाला पर कोई विशिष्ट कानून नहीं था।	कोड में सीमा–पारीय दिवाला से निपटने के लिए सरकार को संधियां करने की शक्ति प्रदान करने और कोड के तहत, एए को किसी देश जिसके साथ एक करार किया गया है, की अदालत में सीडी की परिसंपत्ति से निर्दिष्ट तरीके से व्यवहार करने का अनुरोध पत्र जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रियाएं

कोड के व्यक्तिगत दिवाला से संबंधित प्रावधान लागू होने बाकी हैं। कोड में तीन व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।

(क) नई शुरुआत प्रक्रियाः यह केवल उन देनदारों के लिए उपलब्ध है, जिनकी वार्षिक आय रु. 60,000, परिसंपत्तियां रु. 20,000, ऋण रु. 35,000 से कम हैं और उनके पास आवासीय इकाई नहीं है। केवल देनदार अपने ऋण के निस्तारण के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है। एक समाधान पेशेवर (आरपी) आवेदन की जांच करता है और आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफारिश करते हुए एए को एक रिपोर्ट सौंपता है। आरपी की रिपोर्ट पर विचार करके, एए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए एक आदेश पारित करता है। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो लेनदारों को सीमित आधार पर प्रक्रिया पर आपत्ति करने का अवसर मिलता है। प्रक्रिया के समापन पर, एए देनदार के निस्तारण का आदेश पारित करता है या आवेदन के प्रवेश को रद्द करता है। मोचन आदेश में अप्रतिभूत ऋण को बट्टे डाला जाता है, जिससे देनदार क्रेडिट इतिहास में प्रवेश की शर्त पर नई शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करता है।

(ख) दिवाला समाधान प्रक्रियाः यह एक आरपी की देखरेख में देनदारों और लेनदारों के लिए, सामूहिक रूप से चुकौती योजना, फिर से तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। देनदार या लेनदार यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि एए द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो सभी लेनदारों से दावे आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है। देनदार, आरपी के परामर्श से चुकौती योजना तैयार करता है। यदि लेनदारों के 75% भाग का और उसके बाद एए द्वारा योजना का अनुमोदन किया जाता है, आरपी इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। चुकौती योजना के निष्पादन पर, एए योजना के संदर्भ में देनदार को उसकी देयता से मुक्त करने के लिए एक मोचन आदेश जारी करता है, और देनदार को 'अर्जित शुरुआत' मिल जाती है।

(ग) शोधन अक्षमता प्रक्रियाः यदि समाधान प्रक्रिया विफल हो जाती है या चुकौती योजना लागू नहीं की जाती है, तो देनदार या लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो एए लेनदारों के दावे आमंत्रित करने के बाद एक दिवालिया आदेश पारित करता है और एक दिवालिया ट्रस्टी नियुक्त करता है। दिवालिया ट्रस्टी दिवालिया के कामकाज की जांच करता है, दिवालिया की संपत्ति का मूल्यांकन करता है और कोड में दी गई प्राथमिकता के अनुसार प्राप्तियों का वितरण करता है। वह दिवालिया की संपत्ति के प्रशासन की एक रिपोर्ट को मंजूरी के लिए सीओसी को सौंप देता है। शोधन अक्षमता शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर या सीओसी द्वारा अनुमोदन के सात दिनों के भीतर, दिवालिया ट्रस्टी मोचन आदेश के लिए आवेदन करता है और एए एक मोचन आदेश पारित करता है। यह मोचन आदेश देनदार को दिवाला ऋण से मुक्त करता है। तथापि, शोधन अक्षमता प्रक्रिया की अवधि के दौरान दिवालिया को कुछ अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है।

दो अधिनियम, अर्थात, प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 अब भी लागू हैं। कोड ने इन दो अधिनियमों में कई सुधार किए हैं। देनदार को दिवालिया मानने के विपरीत उसके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कोडः (क) 'शोधन अक्षमता के कृत्य' के आचरण पर निर्भर रहने की बजाय दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक उद्देश्य कारण प्रदान करता है; (ख) अधिस्थगन का अधिदेश देता है जो देनदार और लेनदारों को एक चुकौती योजना पर बातचीत करने के लिए राहत प्रदान करता है; (ग) हितधारकों और एए को प्रक्रियाओं के संचालन में सहायता करने के लिए स्वतंत्र और योग्य पेशेवरों का उपयोग करता है; (घ) एक रेखीय प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें शोधन अक्षम आमतौर पर दिवाला समाधान प्रक्रिया की विफलता का अनुसरण करता है; (ङ) दिवालिया होने की कार्रवाई और दिवालिया होने के दौरान दिवालिया व्यक्ति द्वारा खुद के अच्छे आचरण पर एए की संतुष्टि पर मोचन किए जाने की अपेक्षा की बजाय स्वचालित मोचन को सक्षम बनाता है; (च) 'नई शुरुआत' के रूप में ऋण राहत सहित एक अधिक व्यापक व्यवस्था उपलब्ध कराता है, और देनदार की कुछ परिसंपत्ति देनदार के निर्वाह के लिए लेनदारों की पहुंच से परे रखता है।

कोड का कार्यान्वयन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को कोड के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपने के लिए भारत सरकार (कामकाज का आबंटन) नियम, 1961 में 29 जुलाई, 2016 को संशोधन किया गया। यह निर्णय लिया गया कि अन्य बातों के साथ, संस्थानों के गठन के साथ ही कोड के तहत अपेक्षित पेशेवरों में क्षमता निर्माण की जरूरत को देखते हुए कोड का कार्यान्वयन, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, और पहले चरण में, कॉरपोरेट दिवाला से संबंधित प्रावधानों को लिया जाएगा।

कोड के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने संस्थागत बुनियादी ढांचे में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए। उसने क्रमशः 1 जून, 2016 और 1 अक्टूबर, 2016 को त्वरित क्रम में एए और आईबीबीआई की स्थापना की। सरकार द्वारा कोड के क्रियान्वयन की सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए, कारपोरेट दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित प्रावधानों को 1 दिसंबर, 2016 से लागू करने का निर्णय लिया गया और यह उसी तारीख से लागू हुआ। **(इनस्क्रिप्ट 2)।**

इनस्क्रिप्ट 2: एमसीए से पत्राचार

अमरदीप सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव
Amardeep S Bhatia
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
Government of India
Ministry of Corporate Affairs
New Delhi

DO No. 30/10/2016 – Insolvency
Dated 20th October, 2016

Dear Shri Sahoo

As you are aware, Government is giving the highest priority for commencing the provisions relating to corporate resolution in the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 (Code). In keeping with this priority, and in order to facilitate the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) in taking the minimum time for putting the regulations and other pre-requisites for commencing the provisions in place, a number of activities were initiated pending its establishment. The steps taken have already been outlined to you and were also discussed in the first meeting of the IBBI Board.

2. It has been decided by the Government that the above mentioned provisions should be commenced with effect from **1st December 2016**. In view of this, it is requested that necessary steps may be taken at your end to fast track the remaining activities in order to meet the target date.

With regards,

Yours sincerely,

20/X/2016

(Amardeep S Bhatia)

Shri M S Sahoo,
Chairperson,
Insolvency and Bankruptcy Board of India
CMA Bhawan,
Lodi Road,
NEW DELHI-110003

कमरा नं. 505, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
Room No. 505, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001
Phone : 011-23389068, Fax : 011-23074213, E-mail : asbhatia@gov.in

सरकार ने कोड के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियमों, विनियमों और अन्य मामलों की सिफारिश करने के लिए 22 जुलाई, 2016 को चार कार्य समूहों और उनका मार्गदर्शन और संचालन करने और उनकी सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया। विवरण तालिका 3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3: निगरानी समिति और कार्य समूह

समिति/समूह	अध्यक्ष/संयोजक/सदस्य	व्यापक अधिदेश
निगरानी समिति	अध्यक्षः श्री तपन रे, सचिव, एमसीए सदस्यगण • डॉ. टी के विश्वनाथन, अध्यक्ष, बीएलआरसी • वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के प्रतिनिधि • आरबीआई के प्रतिनिधि, और • विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि	कार्य समूहों का मार्गदर्शन और संचालन
कार्य समूह 1	संयोजकः डॉ. एम.एस. साहू, सदस्य, सीसीआई सदस्यगण • श्री पी.के. नागपाल, कार्यकारी निदेशक, सेबी • श्री रवि नारायण, उपाध्यक्ष, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज • डॉ सुसान थॉमस, सहायक प्रोफेसर, आईजीआईडीआर, और • श्री राकेश त्यागी, निदेशक, एमसीए	आईबीबीआई की संगठन रचना और डिजाइन
कार्य समूह 2	संयोजकः डॉ नवरंग सैनी, निरीक्षण निदेशक, एमसीए सदस्यगण • श्री बीरेंद्र कुमार, भारत में एआरसी संघ के अध्यक्ष • श्री हरिंदरजीत सिंह, भागीदार, पीडब्ल्यूसी • श्री निर्मल गंगवाल, प्रबंध निदेशक, ब्रेस्कॉन एडवाइजर्स • श्री दिनकर वेंकटसुब्रमण्यन, भागीदार, ईएंडवाई • श्री शैलन शाह, निदेशक, केपीएमजी • श्री धिनाल शाह, अध्यक्ष, कॉर्पोरेट लॉज और कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी ऑफ आईसीएआई • सुश्री ममता बिनानी, अध्यक्ष, आईसीएसआई • श्री यू.के. चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता • श्री संजय शौरी, निदेशक, डीएफएस • विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि, और • आईसीएमएआई के प्रतिनिधि	आईपी और आईपीए से संबंधित नियम, विनियम और अन्य मामले
कार्य समूह 3	संयोजकः श्री एन.के. भोला, क्षेत्रीय निदेशक, एमसीए सदस्यगण • श्री बहराम वकिल, भागीदार, एजेडबी एंड पार्टनर्स • श्री वरुण गुप्ता, भागीदार, केपीएमजी • श्री अबीजर दीवानजी, भागीदार, ईएंडवाई • श्री राजन वधावन, भागीदार, पीडब्ल्यूसी एंड कंपनी एलएलपी • श्री एन.एस. कन्नन, कार्यकारी निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक • श्री डी पी ओझा, आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली • श्री निखिल शाह, प्रबंध निदेशक, अल्वारेज एंड मार्सल इंडिया • श्री एम आर उमरजी, सलाहकार, भारतीय बैंक संघ • श्री वेंकटरू श्रीनिवासन, समूह प्रमुख, कोटक महिंद्रा बैंक • सुश्री के श्रीप्रिया, उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी ऑफ आईसीएआई • श्री एस एम सुंदरम, आईसीएसआई के अधिवक्ता और प्रतिनिधि • श्री सुमंत बत्रा, अध्यक्ष, केसर दास बी एंड एसोसिएट्स • आरबीआई के प्रतिनिधि, और • आईसीएमएआई के प्रतिनिधि।	दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और एनसीएलटी प्रक्रियाओं के लिए नियम, विनियम और अन्य संबंधित मामले।
कार्य समूह 4	संयोजकः श्री के वी आर मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए सदस्यगण • डॉ अजय शाह, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी • श्री मिहिर कुमार, निदेशक, सीईआरएसएआई • श्री राजिंदर कुमार, मुख्य महाप्रबधंक, आरबीआई • श्री जयेश सुले, पूर्णकालिक निदेशक, एनएसडीएल ई–गवर्नेंस • श्री मृत्युंजय महापात्रा, उप प्रबंध निदेशक, एसबीआई तथा • डॉ निवेदिता हरन, निदेशक, एनईएसएल	सूचना सुविधाओं से संबंधित नियम, विनियम और अन्य मामले

अपनी स्थापना पर, आईबीबीआई ने क्रमशः कार्यसमूह 2 और 3 द्वारा विकसित सेवा प्रदाताओं (आईपी और आईपीए) और कारपोरेट प्रक्रियाओं (सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया) से संबंधित मसौदा नियमों को, जनता से प्राप्त टिप्पणियों, गोल मेज़ में हितधारकों से प्राप्त इनपुट्स और सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर विचार करते हुए अंतिम रूप दिया और अपनी स्थापना के दो महीने के भीतर उन्हें अधिसूचित किया। सरकार ने पेशेवर संस्थानों के साथ आईपीए की स्थापना पर चर्चा की, जिन्होंने शीघ्र आईपीए की स्थापना की। इससे नवंबर, 2016 के अंतिम सप्ताह में तीन आईपीए का पंजीकरण संभव हुआ। सरकार, एए, आईबीबीआई और हितधारकों ने मिलकर कार्य किया और 1 दिसंबर, 2016 को सीआईआरपी के प्रारंभ को सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए। आईबीबीआई ने संबंधित मसौदा नियमों को भी अंतिम रूप दिया। कार्यसमूह 4 द्वारा विकसित आईयू से संबंधित मसौदे को भी अंतिम रूप दिया और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए, अपनी स्थापना के छह महीने के भीतर उन्हें अधिसूचित किया। विधिक नीति विधि सेंटर ने विनियमों के पहले सेट को तैयार करने में सहायता की। श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री ने बताया[11]: *"दिवाला और शोधन अक्षमता कानून न केवल पारित हुआ, बल्कि साल के अंत तक प्रभावी रूप से लागू हो गया।"* भारत द्वारा कोड तैयार करने और लागू करने की तेजी दुनिया[12] में शायद अब और कहीं नहीं है।

विकास का कालक्रम

तालिका 4 में कोड के अधिनियमन और आईबीबीआई की स्थापना और 31 मार्च, 2017 तक कोड के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का कालक्रम दिया गया है।

तालिका 4: विकास का कालक्रम

तारीख	यात्रा में कदम
10.07.2014	वित्त मंत्री ने 2014–15 के अपने बजट भाषण में कहा: *"आसान निकास को सुगम बनाने के लिए एसएमई के लिए उद्यमी अनुकूल कानूनी शोधन अक्षमता ढांचा भी विकसित किया जाएगा।"*
22.08.2014	भारत में कारपोरेट शोधन अक्षमता कानूनी ढांचे का अध्ययन करने के लिए डॉ टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता में बीएलआरसी का गठन किया गया।
11.02.2015	बीएलआरसी ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एमओएफ ने अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशों पर 20.02.2015 तक सुझाव/टिप्पणी मांगी।
28.02.2015	2015–16 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा: *"शोधन अक्षमता कानून में सुधार, जो कानूनी निश्चितता और गति देने वाला है, को व्यापार करने में आसानी हेतु सुधार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया है। सिका (बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम) और बीआईएफआर (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। हम वित्तीय वर्ष 2015–16 में एक व्यापक शोधन अक्षमता कोड लाएंगे, जो वैश्विक मानकों को पूरा करेगा और आवश्यक न्यायिक क्षमता प्रदान करेगा।"*
04.11.2015	बीएलआरसी ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एमओएफ ने रिपोर्ट पर 19.11.2015 तक सुझाव/टिप्पणी मांगी।
21.12.2015	दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2015 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
23.12.2015	विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया।
28.04.2016	दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2015 पर श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई।
05.05.2016	लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 विधेयक पारित किया।
11.05.2016	राज्यसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 विधेयक पारित किया।
28.05.2016	दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 को अधिनियमित किया गया।
01.06.2016	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।
22.07.2016	एमसीए ने कोड के कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति और चार कार्य समूहों का गठन किया।
29.07.2016	एमसीए को कोड के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई।
05.08.2016	कोड में आईबीबीआई की स्थापना से संबंधित प्रावधान लागू हुए।
19.08.2016	आईबीबीआई के वित्त और कोड में अन्य मामलों से संबंधित प्रावधान लागू हुए।
23.08.2016	वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने एमओएफ और एमसीए के वरिष्ठ अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कोड के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
01.10.2016	आईबीबीआई की स्थापना हुई। आईबीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। डॉ एम.एस. साहू को आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आईबीबीआई के चार पदेन सदस्य नियुक्त किए गए।
07.10.2016	वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आईबीबीआई के अधिषासी बोर्ड की पहली बैठक को संबोधित किया।
18.10.2016	आईबीबीआई ने एक सेवा प्रदाताओं, हेतु और दूसरी कारपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन पर दो सलाहकार समितियों का गठन किया।
01.11.2016	कोड में आईबीबीआई की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान लागू हुए।
15.11.2016	आईपीए और आईपी से संबंधित प्रावधान लागू हुए।

[11] 24 दिसंबर, 2016 को एनआईएसएम परिसर के उद्घाटन पर।
[12] अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा "सूरज भी उगता है" में एक संवाद हैः "आप कैसे दिवालिया हो गए?"; "धीरे–धीरे और फिर अचानक"। अधिकतर शोधन अक्षमता ऐसे ही आती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में दिवाला सुधार भी उसी तरह से हुए। कई वर्षों से काम करते हुए, दिवाला सुधारों ने अचानक आकार ले लिया।

22.11.2016	21.11.2016 को अधिसूचित, आईबीबीआई (मॉडल उप–नियम और दिवाला पेशेवर एजेंसियों का अधिषासी बोर्ड) विनियमन, 2016 और आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर एजेंसी) विनियमन, 2016, लागू हो गया।
28.11.2016	वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने आईबीबीआई के साथ पंजीकृत दो आईपीए को पंजीकरण के प्रमाणपत्र सौंपे।
29.11.2016	23.11.2016 को अधिसूचित आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर) विनियमन, 2016 लागू हुआ।
30.11.2016	श्री तपन रे, सचिव, एमसीए ने 18 आईपीज को पंजीकरण के प्रमाणपत्र सौंपे।
01.12.2016	कोड में कारपोरेट दिवाला समाधान से संबंधित प्रावधान लागू हुए। 30.11.2016 को अधिसूचित, दिवाला और शोधन अक्षमता (सहायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2016, लागू हुआ। 30.11.2016 को अधिसूचित, आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 लागू हुआ।
15.12.2016	9 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित, परिसमापन से संबंधित प्रावधान लागू हुए।आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 लागू हुआ।
31.12.2016	सीमित दिवाला परीक्षा आरंभ हुई।
17.01.2017	किसी एफसी द्वारा पहली सीआईआरपी आरंभ की गई।
18.01.2017	किसी सीडी द्वारा पहली सीआईआरपी आरंभ की गई।
31.01.2017	आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन अधिसूचित किए गए।
17.02.2017	किसी ओसी द्वारा पहली सीआईआरपी आरंभ की गई।
30.03.2017	स्वैच्छिक परिसमापन, आईयू और सीमा पारीय दिवाला से संबंधित प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की गई।
31.03.2017	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 अधिसूचित किए गए। आईबीबीआई (सूचना सुविधाएं) विनियमन, 2017 अधिसूचित किए गए।

ग नीतियां, कार्यक्रम और गतिविधियाँ

ग.1 सेवा प्रदातागण

कोड एक ऐसे कारपोरेट कर्जदार (सीडी) के लिए जिसने चुकौती दायित्वों में चूक कर दी है, जहाँ भी संभव हो, दिवाला के समाधान के लिए और जहाँ भी आवश्यकता हो, निकास की आसानी के लिए बाज़ार तंत्र प्रदान करता है। इसमें एक चूककर्ता सीडी की दो चरणों में दिवाला समाधान की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में, एक चूककर्ता सीडी के लिए अपेक्षित है कि वह तब एक समयबद्ध कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजरे जब इस बात का प्रयत्न रहता है कि सीडी को एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में बचाने के लिए एक समाधान योजना तैयार की जाए। यदि सीआईआरपी सीडी को बचाने में विफल रहता है तो दूसरे चरण में, इसमें सीडी के परिसमापन की परिकल्पना की गई है ताकि वैकल्पिक उपयोगों के लिए संसाधनों को अवमुक्त किया जाए। इसी तरह, संहिता में चुकौती योजना तैयार करने की कोशिश के साथ एक चूककर्ता व्यक्ति के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने की व्यवस्था की गई है ताकि संबंधित व्यक्ति का पुनर्वास किया जा सके। दिवाला समाधान प्रक्रिया के विफल होने पर, व्यक्ति दिवालिया होने की प्रक्रिया से तब गुजर सकता है जब व्यक्ति की परिसंपत्तियां संभव सीमा तक चूक को चुकाने के लिए बेची जाती हैं। पूर्ववर्ती व्यवस्था के विपरीत, कोड में हितधारकों के लिए विनियमित पेशेवर सेवाओं के लिए व्यवस्था की गई है ताकि दिवाला, परिसमापन और दिवालियापन प्रक्रियाओं का संचालन किया जा सके। इसमें तीन प्रकार के सेवा प्रदाताओं के लिए व्यवस्था की गई है, नामतः आईपी, आईपीए और आईयू।

दिवाला पेशेवर

कोड में विनियमित पेशेवरों की एक श्रेणी के लिए व्यवस्था की गई है, नामतः, आईपी। यह किसी व्यक्ति को कोड के तहत आईपी के रूप में सेवाएं प्रदान करने से तब तक रोकता है जब तक कि वहः (क) आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित न हो, और (ख) आईबीबीआई के साथ पंजीकृत न हो। यह आईबीबीआई को इस बात के लिए समर्थ बनाती है कि वह पेशेवरों या ऐसी योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों को आईपी के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए आईपीज के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र बनाए।

एक आईपी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, बीएलआरसी ने देखाः *''यह पूरी दिवाला और दिवाला प्रक्रिया एक विनियमित और लाइसेंसशुदा पेशेवर, जिसे दिवाला पेशेवर या एक आईपी के रूप में जाना जाता है, द्वारा संचालित की जाती है। आईपी को अधिनिर्णायक द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधि द्वारा संचालित दिवाला एवं दिवाला समाधान प्रक्रिया में अधिनिर्णायक द्वारा न्यायिक निर्णय लिए जाते रहे हैं। लेकिन जांच और लेखांकन भी होता है और साथ ही साथ, नियत प्रक्रिया का पालन भी आईपीज द्वारा किया जाता है। यह नियत प्रक्रिया आईपी द्वारा निष्पादित की जाती है। दिवाला पेशेवर उस जटिल स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिस पर प्रभावी, यथासमय कार्य–संचालन के साथ–साथ दिवाला और दिवाला समाधान प्रक्रिया की सम्पूर्ण संरचना की विश्वसनीयता टिकी होती है।''* कोड का, इसलिए प्रयास है कि आईपी पेशे को एक संस्था के रूप में बनाया जाए। **(बॉक्स 2)**

एक आईपी की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करते हुए, दिवाला कानून पर अनसिट्रॉल लेजिस्लेटिव गाइड में कहा गया हैः *''हालांकि दिवाला प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, फिर भी वह देनदारों और उनकी संपत्तियों पर कुछ शक्तियों और उन परिसंपत्तियों और उनके मूल्य के साथ–साथ लेनदारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के कर्तव्य के साथ और यह सुनिश्चित करने के साथ कि कानून प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए, दिवालिया कानून के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तदनुसार, यह आवश्यक है कि दिवाला प्रतिनिधि उचित रूप से योग्य हो और उसके पास ऐसे ज्ञान, अनुभव और व्यक्तिगत गुण हों, जो न केवल कार्यवाहियों के प्रभावी और कुशल संचालन को सुनिश्चित करे बल्कि यह भी कि दिवाला व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न हो।''*

आईपी विनियम

जैसा कि खंड ख में कहा गया है, कारपोरेट दिवाला से संबंधित प्रावधान 1 दिसंबर, 2016 से शुरू होने थे। इसके लिए आईपी को स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि, कोई आईपी नहीं था। बाजार में ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो आईपी बनाता। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं था जिसे पूरा किए जाने पर व्यक्ति आईपी बन जाए। दिवाला कोर्स को तैयार करना और लॉन्च करना और 30 नवंबर, 2016 तक कोर्स पूरा करने वालों को पंजीकृत करना संभव नहीं था। स्क्रीनिंग टेस्ट करना और 30 नवंबर, 2016 तक टेस्ट पास करने वालों का रजिस्ट्रेशन कराना भी संभव नहीं था। एक अभिनव समाधान की दरकार थी। यह निर्णय लिया गया कि शुरू में ऐसे व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाए जिनके पास विनिर्दिष्ट पेशेवर योग्यताएं और अनुभव थे।

आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला पेषेवर) विनियमन, 2016 (आईपी विनियमन) को अधिसूचित किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ–साथ,* आईपी के पंजीकरण, विनियमन और निरीक्षण की व्यवस्था की गई थी। तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, आईपी विनियमों के विनियमन 9 में इस बात की अनुमति दी गई कि 15 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव और लागत लेखाकार आईपी के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा 31 दिसंबर, 2016 तक केवल एक महीने के लिए उपलब्ध थी और इस तरह का पंजीकरण केवल छह महीने की सीमित अवधि के लिए वैध था। इससे आईपी की एक नियमित व्यवस्था के बनने तक तैयारी करने के लिए कुछ समय मिला।

बॉक्स 2 आईपी: दिवाला व्यवस्था की एक प्रमुख संस्था

आईपीज दिवाला व्यवस्था की प्रमुख संस्था होते हैं। एक आईपी कंपनियों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों, प्रोपराइटरशिप फर्मों और व्यक्तियों के समाधान, परिसमापन और दिवालिया प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, आईपी समाधान के तहत सीडी के निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करता है, एक कार्यशील संस्था के रूप में इसके प्रचालनों की देखरेख करता है, और सीडी की ओर से लागू कानूनों का अनुपालन करता है। वह सीडी और उसके हितधारकों पर काफी असर डालने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक और वित्तीय फैसले लेता है, दावों को प्राप्त, संकलित और सत्यापन करता है, हितों के टकराव का समाधान करता है, सीओसी की बैठकों का संचालन करता है, निराकरण योजनाएं आमंत्रित करता है और उनकी जांच करता है, अनियमित लेनदेन पर रिपोर्ट करता है और अन्य जटिल जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। कोड की धारा 20 उससे इस बात की अपेक्षा करती है कि वह सीडी की संपत्ति के मूल्य की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करे और एक कार्यशील संस्था के रूप में उसके प्रचालनों की देखरेख करे। धारा 23 उससे इस बात की अपेक्षा करती है कि वह सम्पूर्ण सीआईआरपी का संचालन करे और सीडी के प्रचालनों की देखरेख करे। सांविधिक और विधिक कर्तव्यों एवं शक्तियों की एक सम्पूर्ण रेंज उसमें निहित होती है। वह दिवाला कार्यवाही का मूल आधार और अधिनिर्णायक प्राधिकारी (एए) होता है और हितधारकों – देनदार, एफसी, ओसी और आरए के बीच की कड़ी होता है।

एक दिवालिया कार्यवाही सीडी और उसके हितधारकों के लिए अक्सर अराजकतापूर्ण और परेशान करने वाली होती है। एक आईपी के लिए जरूरी है कि वह समस्यात्मक सीडी को कायम रखे और जहां यह संभव नहीं है, वहां हितधारकों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में सहायता करे। उसका काम, इसलिए लेनदारों और देनदारों दोनों के जीवन, और आजीविका को प्रभावित करता है और अक्सर इसमें कई प्रतिस्पर्धी हितों से निपटना शामिल होता है। उसमें उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा, वस्तुपरकता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता अवश्य होनी चाहिए। उसे एक उपयुक्त और निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए ताकि हितधारकों का दिवाला व्यवस्था और इसके पेशेवरों पर भरोसा कायम हो सके। विधिक दायित्वों के अलावा, एक आईपी का लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के प्रति नीतिपरक और नैतिक दायित्व होता है। उसके पास न केवल संसाधन क्षमता और व्यवसायिक कौशल जैसे गुण होने चाहिए, बल्कि उसमें हितधारकों के हितों के बीच परस्पर संतुलन बनाते समय दूसरे हितों और सांविधिक उद्देश्यों के प्रति न्याय और निष्पक्षता की अच्छी भावना भी होनी चाहिए। उसके लिए लेनदारों, चिंतित निदेशकों, संबंधित कर्मचारियों और कारोबार में भांति–भांति के अन्य हितधारकों से निपटने के लिए लिखित और अंतर्वैयक्तिक कौशल भी होना जरूरी है। उसके पास दिवालिया कार्यवाही से जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य कारकों की उचित समझ होनी चाहिए। उसे अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाने के लिए कई तरह के कौशलों की आवष्यकता है। दिवाला पेशा सिर्फ एक अन्य पेशा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक संस्था है।

विधि आईपी को इस बात की सुविधा प्रदान करता है और सशक्त बनाता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करे। यह सीडी के प्रत्येक अधिकारी को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे उसे रिपोर्ट करें। यह सीडी के प्रमोटर को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देने के लिए भी बाध्य करता है। अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए और सीडी के खिलाफ कार्यवाहियों पर अधिस्थगन का आष्वासन देता है। कोड आईपी को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह अपनी सहायता के लिए पेशेवरों को नियुक्त करे। यदि उसे किसी भी तरजीही, अल्पमूल्यांकित, बलात् या कपटपूर्ण लेन–देन का पता लगता है तो वह एए से आदेश मांग सकता है। वह एक आईपीई से समर्थन सेवाएं ले सकता है और अपनी सहायता के लिए पेशेवर (रों) को नियुक्त कर सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपी अपनी भूमिका निभाता है, कोड में उसके कार्य निष्पादन की निगरानी करने के लिए आईबीबीआई और आईपीए को सशक्त बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के गलत कार्य के लिए उचित प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। यद्यपि, ग्राहक नियुक्ति के लिए एक आईपी का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन वह वास्तव में एए द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि एए उसके कार्यनिष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो उसे एए प्रक्रिया से हटा सकता है। एए द्वारा नियुक्त करना और हटाया जाना एक आईपी के पद को सुरक्षित और अनुमोदित करता है। उसे सद्भाव में किए गए कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है। उसके आचरण की जांच केवल आईबीबीआई/आईपीए द्वारा की जा सकती है, जिसे इस उद्देश्य के लिए एक नियत प्रक्रिया का पालन करना होता है। विशेष अदालत के समक्ष आईबीबीआई द्वारा दायर शिकायत के सिवाय आईपी के खिलाफ अपराधों के विचारण पर रोक है।

दिवाला पेशा अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। यह उस चरण में है जब प्रतिष्ठा बनती है। समाज जब एक बार किसी पेशे के बारे में धारणा बना लेता है, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए, आईपी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे इस पेशे की प्रतिष्ठा का इस तरह निर्माण करें और उसे सुरक्षित रखें जिससे कि यह समाज का भरोसा जीते और सभी हितधारकों के विश्वास को प्रेरित करे। उन्हें कोड के तहत दी गई संस्था की महान हैसियत का औचित्य स्वयं अवश्य साबित करना चाहिए।

आईपी विनियमनों की नियमन 7 के तहत नियमित व्यवस्था में, चार्टरित लेखाकार, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार और सदस्यता–उपरांत 10 साल के अनुभव (प्रैक्टिस या रोजगार) वाले अधिवक्ता और अर्हता–उपरांत 15 साल का प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले स्नातक, सीमित दिवाला परीक्षा पास करने पर रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं। आईबीबीआई ने 31 दिसंबर, 2016 को परीक्षा करवाई। अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को 1 जनवरी, 2017 से नियमित धारा में आईपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। आईपी विनियमनों में किसी अन्य व्यक्ति को भी राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आईपी के रूप में पंजीकरण अनुमति दी गई है, लेकिन यह परीक्षा अभी तक शुरू नहीं हुई है।

एक दिवाला कार्यवाही में *आईपी की सत्यनिष्ठा पर जोर देते हुए बीएलआरसी ने कहाः ''दिवाला समाधान के मामले में, प्रक्रिया की विफलता दो मुख्य स्रोतों के परिणामस्वरूप हो सकती हैः इसमें शामिल पक्षकारों के बीच मिलीभगत और प्रक्रिया के ही निष्पादन की खराब गुणवत्ता। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए जिम्मेदार पेशेवर कुछ न्यूनतम मानकों का पालन करें ताकि प्रक्रिया की विफलताओं को रोका जा सके और प्रणाली की विश्वसनीयता को समग्र रूप में बढ़ाया जा सके।''* इस विचार के अनुरूप आईपी विनियमनों में अपेक्षा की गई है कि केवल एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति (बॉक्स 3) को आईपी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उसे अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने के लिए एक विस्तृत आचार कोड का अवश्य पालन करना चाहिए। आचार कोड में, *अन्य बातों के साथ–साथ,* आईपी से इस बात की अपेक्षा की गई है कि वह समय–सीमा का पालन करे, गोपनीयता बनाए रखे, रोज़गार और व्यवसाय पर प्रतिबंधों का पालन करे और हितों के टकराव से बचे।

आईपी विनियमनों के साथ पढ़ा जाने वाले कोड के तहत, केवल एक व्यक्ति आईपी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। एक कंपनी या साझेदारी फर्म पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा, केवल वह व्यक्ति जो भारत का निवासी हो, आईपी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। वह व्यक्ति, जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई गई है, वह आईपी होने के योग्य नहीं है।

दिवाला पेशेवर कम्पनियां

यह महसूस किया गया कि एक व्यक्तिक आईपी के पास हमेशा एक बड़े और जटिल सीआईआरपी को संभालने के लिए अपने स्वयं के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं। कोड के तहत प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक संसाधनों के एक पूल को विकसित करने और उसका उपयोग करने एक संरचना का उपयोग करने के लिए, अन्य आईपी के साथ संयुक्त रूप से उसे सक्षम बनाना आवश्यक माना गया। आईपी विनियमन आईपीई के रूप में ऐसी संरचना को सक्षम बनाते हैं। एक एलएलपी, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म और एक कंपनी को आईपीई के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब एलएलपी या पंजीकृत साझेदारी फर्म के अधिकांश भागीदार या कंपनी के अधिसंख्य पूर्णकालिक निदेशक कोड के तहत आईपी के रूप में पंजीकृत कर लिए जाते हैं। एक आईपी एक मान्यता प्राप्त आईपीई के संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग इस शर्त के अधीन कर सकता है कि कम्पनी के साथ–साथ आईपी संयुक्त रूप से और अलग–अलग अपने साझेदारों या निदेशकों द्वारा आईपी के रूप में की गयी भूल–चूक संमबधी कृत्यों के लिए जिम्मेवार होंगे। आईपीई को न तो आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है और न ही आईपी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और यह कोड के तहत आईपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

दिवाला पेशेवर एजेंसियां

दिवाला व्यवस्था में आईपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, कोड में फ्रंट–लाइन विनियामक के रूप में आईपीए, और आईपी के प्रधान विनियामक के रूप में आईबीबीआई से बने द्विस्तरीय विनियमित स्व–विनियमन की परिकल्पना की गई है। इसमें तदनुसार एक आईपी बनने के लिए दो चरणों की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है – पहले आईपीए के साथ इसके पेशेवर सदस्य के रूप में नामांकन और फिर बोर्ड के साथ पंजीकरण। यह बोर्ड और आईपीए को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे अनवरत आधार पर आईपी की निगरानी करें और जहां भी आवश्यकता हो, गलत आईपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। बीएलआरसी ने द्वि–स्तरीय विनियामक संरचना के तर्काधार की व्याख्या की हैः'' इस प्रकार, समिति का मानना है कि ''विनियमित स्व–विनियमन'' का एक नया मॉडल आईपी पेशे के लिए इष्टतम है। इसका मतलब है विनियमन की दो स्तरीय संरचना बनाना। विनियामक इसके तहत आईपी एजेंसियों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने में समर्थ होगा। यह पेशेवर एजेंसियों की वर्तमान संरचना के विपरीत है, जिनका अपने से संबंधित डोमेन पर विधिक एकाधिकार है। बोर्ड के तहत आईपी एजेंसियों को परिभाषित विनियामक ढांचे के भीतर, स्व–विनियमनकारी पेशेवर निकायों के रूप में कार्य करना होगा जो कोड के तहत अपनी भूमिका के लिए आईपी पेशे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे आईपी को अपने सदस्यों के रूप में शामिल करेंगे, पेशेवर मानकों और कोड के तहत आचारनीति का विकास करेंगे, अपने सदस्यों के कामकाज का लेख–परीक्षा करेंगे, उन्हें अनुशासित करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।'' यह सांविधिक विनियमन और स्व–नियमन के लाभों को जोड़ता है और आईपीए के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

बीएलआरसी ने एक विनियामक की देखरेख में कार्य करने वाले कई निजी स्व–नियामक आईपीए की स्थापना की परिकल्पना की। आईपीए, आईपी के कामकाज की देखरेख करेंगे और उद्योग के विकास में मदद करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आईपी उन विविध प्रकार के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम बनें जिनके लिए वे अधिकृत हैं और यह कि वे ईमानदार और निष्पक्ष बनें ताकि हितों के टकराव कम से कम

बॉक्स 3 उपयुक्त और उचित व्यक्ति

कोड के अत्यन्त कल्याणकारी उद्देश्य हैं। प्राथमिक उद्देश्य संकटग्रस्त व्यक्तियों (सीडी और अन्य) का पुनर्वास करना होता है, क्योंकि कई हितधारकों का जीवन और आजीविका ऐसे व्यक्तियों के भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। कोड में यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्था की गई है कि सीडी पुनः हो। हितधारक सीडी को पुनः कर सकें, इसके लिए कोड में सेवा प्रदाताओं–आईपी, आईपीए और आईयू –की पेशेवर सहायता के लिए व्यवस्था की गई है। यह देखते हुए कि कोड के तहत सेवा प्रदाता दिवाला और दिवालिया प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विनियमनों में इस बात की अपेक्षा की गई है कि आईपी के रूप में पंजीकरण के समय व्यक्ति को अवश्य उपयुक्त और उचित व्यक्ति होना चाहिए और आईपी के रूप में पंजीकरण जारी रखने के लिए अवश्यतया उपयुक्त और उचित बने रहना चाहिए। विनियमनों में यह भी अपेक्षा की गई है कि आईपीए और आईयू, उनके पुवर्तक, उनके अधिषासी बोर्ड के निदेशक और उनके प्रमुख शेयरधारकों को भी इसी तरह अवश्य उपयुक्त और उचित व्यक्ति होना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उपयुक्त और उचित है या नहीं, आईबीबीआई विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें (i) सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र, (ii) दोषसिद्धि और संयम बरतने के आदेशों का न होना और (iii) सक्षमता और वित्तीय शोधन क्षमता, शामिल हैं।

आईपी कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के निराकरण, परिसमापन और दिवाला प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई कंपनी सीआईआरपी से गुजरती है, तो एक आईपी को कंपनी के कामकाज की देखरेख के साथ अधिकृत किया जाता है और वह अधिकृत निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करता है। ऐसी कंपनी लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो सकती है। वह ऐसी कंपनी की संपत्ति का अभिरक्षक बन जाता है और एक कार्यशील संस्था के रूप में कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, वह इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव योजना की जांच करता है कि वह तत्समय प्रवृत्त कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता हो। इन जिम्मेदारियों के लिए उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र की आवश्यकता होती है। जिम्मेदारियों के अनुरूप, विनियमनों में बोर्ड से इस बात की अपेक्षा की गई है कि एक आवेदक ''उपयुक्त और उचित'' है, इसका निर्धारण करने के लिए व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र को ध्यान में रखा जाए।[13]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों में ''उपयुक्त और उचित'' व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए समान प्रावधान हैं। इस तरह के प्रावधान को सुलझाते समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहाः *''वित्तीय सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, चरित्र और ईमानदारी ऐसे विषय हैं जिनका प्रतिभूति बाजार के उद्देश्य, पारदर्शी और निष्पक्ष कामकाज पर गंभीर असर पड़ता है।''*[14]

इसी तरह के प्रावधान से निपटते हुए, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने उपयुक्त और उचित व्यक्ति के आयाम की जांच निम्नानुसार कीः *''आवेदक की अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र अत्यन्त तात्विक विचार है जो इस संबंध में बोर्ड (सेबी) के दिमाग में अवश्य आना चाहिए। प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे आपको अनुभव कराते हैं। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति के बारे में दूसरों की व्यक्तिपरक राय या धारणा है और वह, विनियमनों के अनुसार, अच्छा होना चाहिए। यह धारणा या राय आम तौर पर उस साहचर्य के आधार पर बनती है जो उसका दूसरों के साथ होता है और/या उसके अतीत के आचरण के आधार पर बनती है। एक व्यक्ति को उस कंपनी द्वारा जाना जाता है जिसे वह रखता है। चीजों की वास्तविक प्रकृति में, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक कॉरपोरेट निकास। कॉरपोरेट निकाय या किसी फर्म के मामले में, उसके पूर्णकालिक निदेशक (कों) या प्रबंध साझेदार (रों) की प्रतिष्ठा ध्यान में आएगी। एक नियामक के रूप में बोर्ड को प्रतिभूति बाजार की सत्यनिष्ठा और ऐसे उपायों, जो वह उपयुक्त समझे, के द्वारा बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसका विनियमन करने के अलावा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करने का एक सांविधिक कर्तव्य सौंपा गया है। यह इस सांविधिक दायित्व के निर्वहन में है कि बोर्ड ने अवांछनीय तत्वों को बाहर रखकर निवेश करने के लिए बाजार स्थान को निवेशकों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विनियमनों को तैयार किया है। विनियम नियमों के सभी सेटों और प्रतिभूति बाजार के सभी बिचौलियों पर लागू होते हैं, जिनमें वे शामिल हैं जो खुद को बाजार के साथ जोड़ते हैं और उन सभी को संबंधित विनियमों में से किसी के तहत पंजीकृत होने से पहले ''उपयुक्त और उचित व्यक्ति'' के मानदंडों को पूरा करना है और यह मानदंड उन्हें अपने पंजीकरण की वैधता की पूरी अवधि के दौरान और बाजार के साथ उनके संबंध की पूरी अवधि के दौरान जारी रखना चाहिए। विनियमनों का प्रयोजन पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करना और प्रतिभूति बाजार को निवेश के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है। एक खराब तत्व न केवल बाजार को दूषित कर सकता है, बल्कि उस पर कहर भी बरपा सकता है, जो निर्दोष निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में, दिए गए मामले में बोर्ड द्वारा एक संदिग्ध चरित्र या अवांछनीय तत्व को बाजार से बाहर रखने को उचित ठहराया जा सकता है ताकि बाजार को प्रदूषित करने की अनुमति देने का जोखिम लेने से बचा जा सके।''*[15]

ऐसे व्यक्ति को इस आदर्श पेशे से दूर रखना महत्वपूर्ण है जिसका पूर्ववृत्त संदिग्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय कियाः ''यह देखा गया है कि चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करना परीक्षण करने के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है कि चयनित उम्मीदवार राज्य के तहत किसी पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। हालांकि वह उपयुक्त पाया गया था और अनंतिम रूप से चयनित किया गया था, उसके

[13]आईपी पंजीकरण के मामले में दिनांक 14 मार्च, 2017 का आदेश।
[14]यू. पी. स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स बनाम सेबी (2012 की सिविल रिट याचिका 45893) के मामले में दिनांक 23 मई 2014 का आदेश।
[15]जर्माइन कैपिटल एलएलसी बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मामले में दिनांक 6 सितंबर, 2006 का आदेश।

पूर्ववृत्त रिकॉर्ड के कारण नियुक्ति प्राधिकारी ने इस तरह के रिकॉर्ड के कारण किसी व्यक्ति को नियुक्त करना वांछनीय नहीं पाया और मामले की पृष्ठभूमि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बनाई गई राय अनुचित नहीं कही जा सकती, हालांकि उम्मीदवार को अपराधों से उन्मोचित या बरी कर दिया गया, फिर भी उसका इस सवाल से कोई लेना–देना नहीं है। नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार का आचरण या चरित्र प्रासंगिक होगा न कि उसका वास्तविक परिणाम। यदि वास्तविक परिणाम एक विशेष तरीके से घटित हुआ हो, तो कानून परिणामों का ध्यान रखेगा। मामले से संगत विचारणीयता उम्मीदवार का पूर्ववृत्त है। इसलिए, नियुक्ति प्राधिकारी ने इस पहलू को सही रूप से ध्यान में रखा है और उसे नियुक्त करने के लिए वांछनीय नहीं पाया है।"[16]

घटित हों। वे उप–नियमों के माध्यम से अपने सदस्यों के लिए नियम और मानक स्थापित करेंगे, संगत प्रवेश बाधाओं को बनाएंगे और अद्यतन करेंगे, और अपने नियमों और मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तंत्र स्थापित करेंगे। कई आईपीए के बीच प्रतिस्पर्धा से दक्षता में सुधार होगा जिससे मानक और नियम बेहतर बनेंगे और बेहतर प्रवर्तन होगा।

एक आईपीए एक छोटा राज्य के समान है जिसके प्रकार्य हैं: (क) अर्ध–विधायी कार्य – उप–नियमों के माध्यम से विस्तृत मानकों और आचार संहिता का मसौदा तैयार करना, जो इसके सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं; (ख) कार्यकारी कार्य – नियमित आधार पर सदस्यों की निगरानी, निरीक्षण और जांच करना, और उनके कर्तव्यों के संचालन में तुच्छ व्यवहार और दुर्भावना को रोकने के अतिव्यापी उद्देश्य के साथ, उनके कार्य–निष्पादन पर जानकारी इकट्ठा करना; और (ग) अर्ध–न्यायिक कार्य – दुखी पक्षों की शिकायतों का निराकरण करना, सदस्यों के खिलाफ शिकायत सुनना और उपयुक्त कार्रवाई करना।

आईपीए विनियमन

आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला प्रोफेशनल एजेंसियों के मॉडल उप–नियम एवं अधिशासी बोर्ड) विनियमन, 2016 और आईबीबीआई (दिवाला प्रोफेशनल एजेंसी) विनियमन, 2016 (आईपीए विनियमन) को 21 नवंबर, 2016 को अधिसूचित कर दिया। इन दोनों विनियमनों में, अन्य बातों के साथ–साथ, आईपीए के एक पेशेवर सदस्य होने के लिए मानदंडों और एक आईपीए के रूप में आईबीबीआई के साथ पंजीकृत होने के लिए पात्रता मानदंडों का उपबंध किया गया है। केवल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी जिसकी न्यूनतम निवल मूल्य रु. 10 करोड़ है और रु. 5 करोड़ की कुल पूँजी है, आईपीए होने के योग्य है। आईपीए की कम से कम 51% शेयर पूंजी भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित की जानी चाहिए। आईपीए, इसके प्रवर्तक, इसके निदेशक और इसकी शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा धारित करने वाले व्यक्तियों को अवश्यही ''उपयुक्त और उचित'' व्यक्ति होना चाहिए। इसके अधिशासी बोर्ड के आधे से अधिक निदेशक अवश्यही स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और एक चौथाई से अधिक निदेशक आईपी नहीं होंगे। पेशेवर सदस्यों के विनियमन और निगरानी के लिए इसमें सदस्यता समिति (यां), निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति (यां) और अनुशासनात्मक समिति (यां) होंगी।

सूचना उपयोगिता

कोड में आईयू की परिकल्पना ऐसी वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए की गई है जिससे चूक साबित करने के साथ–साथ दावों को शीघ्रता से सत्यापित करने में मदद मिलती है और इस तरह, कोड के तहत प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुविधा होती है। बीएलआरसी ने बाजार की विफलता से बचने के लिए अंतर्प्रचालनीय आईयू के लिए राज्य के साथ एक केंद्रीकृत डिपॉजिटरी के बजाय एक निजी प्रतिस्पर्धी बाजार की परिकल्पना की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईयू दिवाला और शोधन अक्षमता के निराकरण के लिए आवश्यक सूचनाओं को दर्ज करे, कोड ने एफसी के लिए डाटा प्रस्तुतीकरण अनिवार्य कर दिया और इस तरह के डाटा को स्वीकार करने के लिए आईयू पर एक बाध्यता लगा दी। शुद्धता सुनिश्चित करने और विवादों को रोकने के लिए, संहिता में अधिदेशित किया गया कि इस तरह के अभिलेख को सभी संबंधित पक्षों के साथ सह–सत्यापित किया जाना चाहिए। आईयू एक आदर्श संरचना है और इसका किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई समरूप नहीं है।

बीएलआरसी ने तर्काधार को स्पष्ट किया है: "आईआरपी के शुरू होने से पहले, सभी पक्षकारों को मौजूदा क्रेडिट के बारे में तथ्यों, संपार्श्विक जिसे गिरवी रखा गया है, आदि के बारे में सही और निर्विवाद सेट की आवश्यकता होती है। वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत, सभी पक्ष यह सूचना प्राप्त करने से पहले काफी समय गंवा सकते हैं। इन तथ्यों के बारे में विवादों को अदालत में हल करने में कई साल लग सकते हैं। एक आईआरपी का उद्देश्य जो 180 से अधिक दिनों में पूरा होता है, इन समस्याओं के कारण निष्फल हो सकता है। इसलिए, समिति ने सूचना उपयोगिता के एक ऐसे प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना की जो ''हर समय सभी फर्मों के बारे में भांति–भांति की जानकारी का धारण करे। जब आईआरपी शुरू होता है, तो एक दिन से भी कम समय के भीतर, निर्विवाद और पूरी जानकारी आईआरपी में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और इस तरह देरी के इस स्रोत का निराकरण किया जाएगा।'' तदनुसार, बीएलआरसी ने एक

[16] दिल्ली प्रशासन और अन्य बनाम सुशील कुमार के मामले में दिनांक 4 अक्टूबर, 1996 का आदेश।

विनियमित आईयू को बनाने की सिफारिश की, जो दिवाला और शोधन अक्षमता का निराकरण करने के लिए सभी हितधारकों से सभी प्रकार की सूचना को प्राप्त करे और उन्हें उपलब्ध कराए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट की त्वरित सूचना देने के लिए, लेनदारों की पहचान करने में और देनदार (व्यक्तिगत या उद्यम) की परिसंपत्तियों की पहचान करने में सक्षम होंगे। इससे विवादों में कमी आएगी और अधिनिर्णयक में होने वाली देरी में कमी होगी।

आईयू विनियमन

आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2017 को आईबीबीआई (सूचना यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (आईयू विनियम) को अधिसूचित किया। आईयू विनियमन में आईयू के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मूल्य वाली सार्वजनिक कंपनी आईयू के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य है। इसके आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। आईयू, इसके प्रवर्तक, इसके निदेशक, इसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या इसकी कुल मतदान शक्ति का 5% से अधिक रखने वाले व्यक्ति, उपयुक्त और उचित व्यक्ति होंगे। सामान्यतौर पर, किसी व्यक्ति को प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10% से अधिक का धारण नहीं करना चाहिए, जबकि कुछ निर्दिष्ट व्यक्ति प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 25% से अधिक का भाग धारण कर सकते हैं। हालांकि, शुरू करने के लिए, एक व्यक्ति आईयू की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% तक का धारण कर सकता है, लेकिन उसे पंजीकरण से तीन साल की समाप्ति से पहले इसे घटाकर 10% या 25%, जैसा भी मामला हो, तक रखना है।

आईयू आईबीबीआई को इस बात के लिए सक्षम बनाता है कि वह आईयू द्वारा कोर सेवाओं और अन्य सेवाओं के निष्पादन के लिए दिशानिर्देशों के माध्यम से तकनीकी मानक निर्धारित करे। तकनीकी मानकों में, अन्य बातों के साथ–साथ, आईयू के साथ संग्रहित होने वाली सूचनाओं के प्रमाणीकरण और सत्यापन से संबंधित मामलों, उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण, डाटा सत्यनिष्ठा और सुरक्षा, आईयू के बीच सूचना के पोर्टिंग, अंतर–संचालनीयता, आदि के लिए व्यवस्था की जाएगी। विनियिमों में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए और आईयू को प्रस्तुत हरेक सूचना के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता होगा। विनियमनों में एक आईयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों और प्रदान की जाने वाली सेवाएं निर्धारित की गई हैं। उपयोगकर्ता के हितों की सुरक्षा के लिए, विनियमों में इस बात की अपेक्षा की गई है कि आईयू में एक शिकायत निवारण नीति के साथ–साथ एक निकास प्रबंधन योजना भी हो। एक आईयू में एक अनुपालन अधिकारी भी होगा जो कोड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और उसके द्वारा देखे गए कोड के किसी भी प्रावधान का पालन न करने की रिपोर्ट तत्काल और स्वतंत्र रूप से आईबीबीआई को करेगा।

ग. 2 कारपोरेट प्रक्रियाएँ

सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित कोड में प्रावधान 2016–17 में लागू हुए और तदनुसार आईबीबीआई ने इन प्रक्रियाओं से संबंधित विनियमनों को अधिसूचित किया।

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

कुछ व्यावसायिक योजनाओं की विफलता बाजार अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जब व्यापार में विफलता होती है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम फाइनेंसरों के बीच तेजी से पुनर्मध्यस्थाता हो, देनदारियों की एक नई व्यवस्था का उपयोग करके और नई प्रबंधन टीम के साथ कार्यशील संस्था का वित्तपोषण किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम तीव्र परिसमापन है। जब इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, तो रचनात्मक विनाष की बाजार प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी जोश और कहीं अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ सुचारू रूप से काम करेगी।[17]

यह कोड, जिसे आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (सीआईआरपी विनियमन) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता (अधिनिर्णायक प्राधिकारी को लागू करना) नियम, 2016 के साथ पठित, सीआईआरपी को नियंत्रित करती है। मोटे तौर पर, चूक की शुरुआती राशि (वर्तमान में रु 1 लाख) एक एफसी, एक ओसी या सीडी को अपने आप सीडी की सीआईआरपी आरंभ करने के लिए एक आवेदन दायर करने का हक देती है और यदि उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाता है, तो सीआईआरपी प्रारंभ हो जाता है। इसका अर्थ है कि (क) सीडी 'अधिकृत देनदार' से हटकर 'नियंत्रक लेनदार' हो जाता है, (ख) सीडी का प्रबंधन और उसकी परिसंपत्ति एक अंतरिम समाधान पेषेवर (आईआरपी) में निहित हो जाती है, जो सीडी को कार्यशील संस्था के रूप में चलाता है, और (ग) सीडी के खिलाफ मुकदमा और कार्यवाही संस्थित करने या जारी रखने पर रोक लगाते हुए अधिस्थगन है। आईआरपी दावों को प्रस्तुत करने का आमंत्रण देते हुए एक सार्वजनिक घोषणा करता है। दावों के सत्यापन के बाद, वह एक सीओसी का गठन करता है, जो अपनी पहली बैठक में आरपी के रूप में एक आईपी नियुक्त करता है। सीडी को एक कार्यशील संस्था के रूप में चलाने के दौरान, आरपी को कुछ मामलों के लिए सीओसी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वह सीडी की दिवालियेपन के समाधान के लिए पात्र और विष्वसनीय आरए से संभव और व्यवहार्य समाधान योजनाओं को आमंत्रित करता है। वह एक सूचना ज्ञापन (आईएम) जारी करता है और भावी आरए को

[17]बीएलआरसी की रिपोर्ट।

सीडी के बारे में संपूर्ण, सही और यथासमय जानकारी प्रदान करता है ताकि वे समाधान योजनाएं तैयार करने में सक्षम हो सकें। समाधान योजनाओं के प्राप्त होने पर, वह उनमें से प्रत्येक की जांच यह पुष्टि करने के लिए करता है कि क्या वे कोड और विनियमनों में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं और सीओसी के विचारार्थ अनुपालन योजनाएं प्रस्तुत करता है। यदि सीओसी 75% बहुमत[18] के साथ निर्धारित समय के भीतर एक समाधान योजना को मंजूरी देता है, तो आरपी अनुमोदित योजना को एए द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। यदि एए एक समाधान योजना को मंजूरी देता है, तो सीडी कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहता है। यदि सीओसी इस अवधि के भीतर आवश्यक बहुमत के साथ एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देता है या एए समाधान योजना को मंजूरी नहीं देता है, तो सीडी अनिवार्य रूप से परिसमापन से गुजरता है।

उपयुर्क से यह स्पष्ट है कि संहिता में चूक/विफलता की रोकथाम पर काफी अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। यह किसी को भी चूककर्ता सीडी के दिवालियेपन के समाधान के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने में समर्थ बनाता है। मौजूदा प्रवर्तक और प्रबंधन सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी समाधान योजना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं या सीओसी परिसमापन का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में, मौजूदा प्रवर्तक और प्रबंधन फर्म पर हमेशा के लिए नियंत्रण खो सकते हैं। स्थापित संहिता के साथ, फर्म का स्वामित्व अब कोई दैवीय अधिकार नहीं रहा।

सीआईआरपी का वह संभव जोखिम कि फर्म का नियंत्रण और प्रबंधन मौजूदा प्रमोटरों और प्रबंधकों से दूर हो सकता है, संभवतः सबसे अधिक, हमेशा के लिए, फर्म के प्रबंधन और प्रमोटरों को इस बात से रोकता है कि वे फर्म को दक्षता के आवश्यक स्तर से नीचे प्रचालित नहीं करे और डिफॉल्ट से बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, यह देनदारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे जल्द से जल्द, अधिमानतः कोड के बाहर लेनदार (रों) के साथ चूक का निपटारा करें। कोड महत्वपूर्ण व्यवहारपूर्ण बदलाव लाएगी और इस तरह देनदार–लेनदार संबंध को फिर से परिभाषित करेगी। कोड के स्थापित होने के साथ, ऋण का पुनर्भुगतान अब एक विकल्प नहीं रह गया है; यह एक दायित्व है।

दूसरी ओर, लेनदार यह जानता है कि यदि दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है या दिवालिया होने का समाधान नहीं किया जाता है तो देनदार के लिए चूक के क्या परिणाम होंगे। यह डिफ़ॉल्ट की घटनाओं को कम करने के लिए अधिक जिम्मेदार (गुणात्मक) ऋण देने का सहारा लेने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा, जैसे ही शुरुआती राशि का डिफ़ॉल्ट होता है, एक लेनदार के पास संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होता है, लेकिन वह पहले उपलब्ध अवसर पर ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होता है, यदि उसके लिए कारण मौजूद हैं। हालांकि, यह चूक को बढ़ने देते हुए कार्यवाही की शुरुआत को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकता है। सीएण्डआई की दशा में विफलताओं/चूक को रोकना हमेशा संभव नहीं हो सकता और ऐसे मामलों में कोड में एक असफल होती, व्यवहार्य फर्म को बचाने के लिए एक बाजार तंत्र की परिकल्पना की गई है।

सीआईआरपी की मुख्य विशेषताएं

(क) कोड में इस बात का प्रयास किया गया है कि सीडी को अपने स्वयं के प्रबंधन से परिसमापन से सुरक्षित करके इसका पुनरुद्धार किया जाए और इसे जारी रखा जाए। इसमें दिवाला के समाधान के लिए एक योजना की परिकल्पना की गई है। यह लेनदारों की बकाया राशि की वसूली के लिए एक वसूली कार्यवाही नहीं है। इसमें ऋण की वसूली के लिए सीडी की बिक्री या परिसमापन की परिकल्पना नहीं की गई है (बॉक्स 4)। वास्तव में, इसमें उस स्थिति में दंड देने की व्यवस्था की गई है जब कोड के तहत प्रक्रिया का कोड के प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया जाए।

(ख) कोड में दिवाला को **शीघ्रातिशीघ्र, अधिमानतः एकदम पहले चूक पर, निपटाया जाना संभव बनाया गया है ताकि इसे** निपटाए न जा सकने वाले अनुपात तक पहुंचने से रोका जा सके। चूक के शुरुआती दिनों में, उद्यम मूल्य आमतौर पर उसके परिसमापन मूल्य से अधिक होता है और इसलिए हितधारक इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि सीडी को परिसमाप्त करने के बजाय उसके दिवाला का निपटारा किया जाए। इसलिए, यह हितधारकों को इस बात का हक देता है कि जब और जैसे ही चूक निर्णायक राशि तक पहुंचे, सीआईआरपी शुरू कर दिया जाए।

(ग) संहिता में **समयबद्ध तरीके से** समाधान को अनिवार्य बनाया गया है, क्योंकि अनुचित देरी से सीडी के उप मूल्य के कम होने की संभावना होती है। जब सीडी सुदृढ़ वित्तीय हालत में नहीं होती है, तो उसके स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में लंबे समय तक कायम अनिश्चितता समाधान की संभावना को असंभव कर सकती है। समय कोड का सार है (बॉक्स 5)। विनियमों में प्रक्रिया के प्रत्येक कार्य के लिए एक मॉडल समय–सीमा दी गई है।

(घ) कोड में सीडी के समाधान की परिकल्पना एक **कार्यशील संस्था** के रूप में की गई है, क्योंकि सीडी को बंद करने से

[18] 6 जून, 2018 के अध्यादेश के माध्यम से घटकर 66% रह गई।

बॉक्स 4 समाधान योजनाः कोड की भावना

कोड की आत्माा फर्म के पुनरुद्धार के लिए एक समाधान योजना होती है। कोड प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं के सृजन और फर्म के पुनःजीवित के लिए उनमें से सर्वश्रेष्ठ को अनुमोदित किए जाने को सुविधा प्रदान करता है प्रोत्साहित करता है। यह आईपी को इस बात का उत्तर दायित्व देता है कि वह एक कार्यशील संस्था के रूप में कर्जदार के कामकाज की देखरेख करे और उसकी परिसंपत्तियों के मूल्य को सुरक्षित और संरक्षित करे। यह अंतरिम रूप से वित्त जुटाने में समर्थ बनाता है और फर्म के सतत बिजनेस संचालन के लिए आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का आदेश देता है। यह फर्म के लिए तब एक शांत अवधि सुनिश्चित करता है जब कोई भी समाधान की प्रक्रिया से गुजर रहे फर्म को व्यवधान नहीं पहुंचाता है।

कोड में शोधन अक्षमता को निपटाए न जा सकने वाले अनुपात तक पहुंचने से काफी पहले प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की परिकल्पना की गई है। चूक के शुरुआती दिनों में, एक फर्म का उद्यम मूल्य आमतौर पर उसके परिसमापन मूल्य से अधिक होता है और इसलिए सीओसी इस बात के लिए प्रेरित होती है कि फर्म को परिसमाप्त करने के बजाय उसके मूल्य को संरक्षित करने करने के लिए इसे पुनःजीवित किया जाए। हालांकि, उद्यम मूल्य समय के साथ तेजी से कम हो जाता है। जब कोई फर्म दिवालिया हो जाती है, तो उसके स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता और दिवालियापन से जुड़ी सामान्य आशंका से ग्राहकों, विक्रेताओं, श्रमिकों आदि का पलायन हो जाता है। इसलिए, संहिता में 180वें दिन तक प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश दिया गया है।

यह न्यायिक पहलुओं एवं प्रोत्साहनों से वाणिज्यिक पहलुओं को अलग करता है और हितधारकों को तेजी से वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित और समर्थ करता है।

वसूली लेनदार द्वारा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने बकाया राषि की वसूली के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास है जिसमें देनदार और लेनदार विपरीत पक्षों में होते हैं। जब लेनदार फर्म की उपलब्ध संपत्तियों से अपने बकाया की वसूली करें – एक के बाद एक या एक साथ – तो नियत समय में कुछ भी नहीं छोड़ा जाए। इस प्रकार, वसूली फर्म को परिसमापन की ओर ले जाती है, जबकि समाधान में इसे जीवित रखने का प्रयास किया जाता है। यह एक आर्थिक तबाही होगी जब लेनदार कई दिवालिया कंपनियों से वसूली चाहेंगे।

वसूली फर्म और अन्य लेनदारों के विपरीत अकेले लेनदार के मूल्य को अधिक से अधिक करता है। यह पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर लेनदारों के हितों की पूर्ति करता है – लेनदार, जो पहले वसूली शुरू करता है, सबसे अधिक पाता है, और जो आखिर में शुरुआत करता है, उसे सबसे कम वसूली मिलती है – और उपलब्ध संपत्ति का असमान वितरण अर्जित करता है। इस प्रकार, वसूली, सामूहिक प्रयास नहीं होने के कारण, सभी हितधारकों के हितों में फर्म की संपत्तियों के मूल्य को अधिक से अधिक नहीं करता है, जबकि समाधान हितधारकों को फर्म के भाग्य को साझा करने में सक्षम बनाता है। इसलिए, वसूली समाधान का विलोम पक्ष है। यही कारण है कि कोड समाधान प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रतिभूति हित को प्रतिबंधित करने, वसूल करने या प्रवर्तित करने के लिए की जाने वाली कोई कार्रवाई को रोकती है और इस तरह, लेनदार (रों) को अपने बकाया राषि को वसूल करने से रोकती है। इसमें प्रक्रिया की परिसमापन की परिकल्पना नहीं की गई है, चाहे लेनदार, जिसने प्रक्रिया शुरू की थी, का बकाया मिल गया हो।

परिसमापन एक फर्म के जीवन को समाप्त कर देता है। यह संगठनात्मक पूंजी को नष्ट कर देता है और संसाधनों को पुनर्आबंटन होने तक वैकल्पिक उपयोग के लिए निष्क्रिय कर देता है। यह हितधारकों के अगले सेट के दावे पर केवल तभी विचार करता है, जब हितधारकों के पहले सेट के दावों की पूर्ण रूप से पूर्ति हो जाने के बाद कोई अधिशेष बचता है। इस प्रकार, परिसमापन भी समाधान के प्रतिकूल होता है। इसलिए, कोड सीधे किसी फर्म के परिसमापन की अनुमति नहीं देता है। यह समाधान प्रक्रिया से कोई समाधान न निकलने के बाद ही परिसमापन की अनुमति देती है।

परिसमापन से बचने के उद्देश्य से सीओसी में एफसी शामिल किए गए हैं। बीएलआरसी ने सीओसी की संरचना के औचित्य को अग्रलिखित शब्दों में व्यक्त किया हैः ''समिति ने कम्पनी को अंततोगत्वा कार्यशील संस्था के रूप में बनाए रखने या उसे परिसमाप्त करने की लेनदारों की समिति की शक्ति को देखते हुए यह विचार किया कि लेनदारों की समिति में कौन होना चाहिए।'' समिति ने तर्क दिया कि लेनदारों की समिति के सदस्यों को व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता के साथ–साथ मोलभाव में मौजूदा देनदारियों की शर्तों को संशोधित करने के लिए तैयार रहने दोनों बातों के लिए, इच्छुक रहना है। इसने नोट किया,''आमतौर पर, प्रचालनात्मक लेनदार न तो कम्पनी के दिवालियेपन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, और न ही कम्पनी के लिए बेहतर भावी संभावनाओं के लिए भुगतान स्थगित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रक्रिया का तेज और कुशल करने के लिए कोड इस बात की व्यवस्था करेगी कि लेनदारों की समिति को केवल वित्तीय लेनदारों के लिए सीमित किया जाना चाहिए।''

हालांकि, कोड में यह माना गया है कि कतिपय परिस्थितियों में, लेनदारों के लिए परिसमापन सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसी फर्में हो सकती हैं, जो नाम भर के लिए जीवित हों। उन्होंने अपनी स्थिति में बिना किसी सुधार के बीआईएफआर या अन्य रिकवरी/पुनर्गठन ढांचे में कई साल बिताए होंगे। उनकी अधिकांश भौतिक और संगठनात्मक पूंजी समाप्त हो गई होगी। ऐसे मामलों में, यह प्रत्यक्षतया स्पष्ट हो सकता है कि फर्म व्यवहार्य नहीं है और समाधान योजना संभव नहीं है। यदि फर्म को सीआईआरपी अवधि खत्म तक इंतजार करना है, तो अवशिष्ट संपत्तियों का मूल्य अनावश्यक रूप से आगे और कम हो जाएगा। इसलिए, कोड में सीओसी को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे परिसमापन के लिए एए से सीधे संपर्क करें।

कोड में सीडी की बिक्री या नीलामी की परिकल्पना नहीं की गई है। यदि ऐसा होता है, तो व्यक्ति सीडी को एक ट्रेडिंग/नीलामी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है और जो सबसे अधिक कीमत का भुगतान करेगा वह उसे प्राप्त करेगा। समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए मतदान

करने या दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उच्चतम मूल्य पर बेचा जाएगा। किसी को बिक्री के प्रयोजन के लिए सीआईआरपी, आईआइरपी, आरपी, अंतरिम वित, शांत अवधि, आवश्यक सेवाएं, सीओसी या समाधान आवेदक और विस्तृत, विनियमित प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

जहां एक फर्म ने पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक की है, लेनदार के पास मोटे तौर पर दो विकल्प होते हैं, नामतः वसूली और समाधान। इसमें चूक को पुनर्प्राप्त करने के लिए कई विकल्प होते हैं; इसी तरह, फर्म के दिवालिया होने के समाधान के लिए भी कई विकल्प होते हैं। यह समाधान के लिए कोड का उपयोग कर सकता है, हालांकि वह कोड के बाहर दिवालिएपन का समाधान कर सकता है। इसे पुनर्प्राप्ति के लिए कोड का उपयोग अवश्य नहीं करना चाहिए, हालांकि वह चूक राशि के समाधान की आनुषंगिक राशि के रूप में वसूली कर सकता है। इसके अलावा, संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया दो परिणामों में से किसी एक की ओर जाती है, अर्थात, फर्म का पुनरुद्धार या फर्म का परिसमापन। सीओसी को, अगर यह व्यवहार्य है तो फर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और परिसमापन से बचना चाहिए।

संगठनात्मक पूंजी नष्ट हो जाती है और पुनर्आबंटन होने तक संसाधन वैकल्पिक उपयोग के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं और समाधान की संभावना अत्यन्त कम हो जाती है। इसलिए, यह सीआईआरपी के दौरान सीडी को एक कार्यशील संस्था के रूप में सतत प्रचालन को सक्षम करता है। यह सीडी, उसके प्रवर्तकों और उसके प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को अधिदेशित करता है कि वह आईपी को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग दे। यह अंतरिम रूप से वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है और दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, जिसे काफी अधिक प्राथमिकता दी जाती है, में अंतरिम वित की लागत शामिल करता है। यह सीडी को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के निलंबन या समाप्ति पर रोक लगाता है।

(ड) कोड में दिवालि के समाधान के लिए एक **सामूहिक तंत्र** की परिकल्पना की गई है। यह किसी भी एफसी को उस स्थिति में भी सीआईआरपी शुरू करने में सक्षम बनाता है, जबकि फर्म ने किसी अन्य एफसी के प्रति चूक की हो। यह देनदार को कम मुखर लोगों की अनदेखी करते हुए अधिक मुखर लेनदार के प्रति अधिमान्य बर्ताव करने से रोकता है। इसमें उस स्थिति में भी प्रक्रिया की समाप्ति की परिकल्पना नहीं गई है, जबकि संबंधित लेनदार के दावे की पूर्ति हो गई हो। सीआईआरपी से एक बार जुड़ जाने के बाद, अन्य लेनदारों को अपने दावे दायर करने का अधिकार मिल जाता है। इस तरह, दिवाला कार्यवाही की प्रकृति एक प्रतिनिधिक वाद में बदल जाती है और लेनदार और सीडी के बीच लंबित कोई वाद नहीं रह जाता है। इसलिए, उनके पास अकेले दिवाला याचिका वापस लेने का अधिकार नहीं रह जाता है, भले ही संबंधित लेनदार के बकाए का निपटान कर दिया गया हो। यह किसी चीज के विरुद्ध कार्यवाही होती है और विरोधात्मक नहीं होती है और इसमें कोई विपरीत पक्षकार नहीं होते हैं।

(च) कोड **सर्वोत्तम दीर्घस्थायी समाधान** प्रदान करती है। यह समाधान योजना के माध्यम से समाधान की असीम संभावनाओं पर विचार करने में समर्थ बनाती है। समाधान योजना के लिए प्रबंधन, प्रौद्योगिकी या उत्पाद पोर्टफोलियो में बदलाव; परिसंपत्तियों, व्यवसायों या उपक्रमों के अधिग्रहण या निपटान; संगठन, व्यवसाय मॉडल, स्वामित्व, तुलन पत्र का पुनर्गठन; कायापलट, बाय–आउट, विलय, अधिग्रहण, अधिग्रहण की कार्यनीति; इत्यादि आवश्यक होते हैं।

(छ) कोड दिवाला प्रस्ताव के **वाणिज्यिक पहलुओं** को न्यायिक पहलुओं से अलग करती है और सीडी एवं एए के हितधारकों को इस बात के लिए सषक्त बनाती है कि वे अपने संबंधित डोमेनों के भीतर मामलों पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय लें। यह पूरी प्रक्रिया को हितधारकों के नियंत्रण में डाल देती है और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहनों और नुकसानो के साथ प्रेरित करती है। (बॉक्स 6)

(ज) कोड समाधान प्रक्रिया में हितधारकों के **हितों को संतुलित करती है।** यह महत्व रखता है क्योंकि सीआईआरपी से गुजरने वाले सीडी के पास सीआईआरपी के प्रारंभ होते समय इतना नहीं हो सकता है कि वह सभी हितधारकों के दावों को पूरी तरह निपटा दे। यह विशिष्ट शेष प्रदान करता है, जैसे कि एफसी पर प्राथमिकता देते हुए ओसी को न्यूनतम भुगतान। यह सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है और एफसी के लिए मूल्य को अधिकतम नहीं करता है। चूंकि इसमें सीआईआरपी के दौरान वसूली की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए इसमें बरामद राशि को लेनदारों के बीच वितरित करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से आगम राषि के वितरण के लिए प्राथमिकता के क्रम की व्यवस्था की गई है।

(झ) कोड में अपेक्षा है कि समाधान योजना देश के **सभी अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुरूप** हो और इसे अवश्य क्रियान्वयन–योग्य होना चाहिए। अन्यथा, योजना क्रियान्वयन–योग्य नहीं हो सकती है, और समाधान का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। यदि अनुमोदित समाधान योजना लागू नहीं की जाती है तो कोड में गंभीर दंडात्मक परिणामों की व्यवस्था की गई है।

बॉक्स 5 180 दिनः बहुत अधिक या बहुत कम?

कोड के लंबे शीर्षक में कहा गया हैः ''यह अधिनियम जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए.......कॉरपोरेट व्यक्तियो के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधि को.......परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिक से अधिक करने के लिए समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करता है.....'' इन उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोड के तहत दिवाला समाधान और अन्य प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वास्तव में, संहिता की 'समयबद्ध' विशिष्टता इसे मामले के पूर्ववर्ती विधानों से अलग करती है। कोड सीआईआरपी को पूरा करने के लिए 180 दिनों की अनुमति देती है। इसमें पात्र मामलों में एए द्वारा 90 दिनों तक के एक बारगी विस्तार की अनुमति दी गई है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सीडी व्यक्तियों की सीआईआरपी के लिए समान स्तर की जटिलता हो और कुछ का पहले भी निपटारा किया जा सकता है। कोड में तदनुसार सीडी की कतिपय श्रेणियों के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है जिसमें समाधान प्रक्रिया को, 45 दिनों के एक बारगी विस्तार के प्रावधान के साथ, 90 दिनों के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है।

जब भी किसी प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है, तो कुछ इसे कम पाते हैं, जबकि अन्य इसे अधिक पाते हैं। वास्तव में, यह संदर्भ पर निर्भर करता है जैसे कि प्रक्रिया निष्पादित करने वाले व्यक्ति और उनके नियंत्रण में मौजूद संसाधन, उपलब्ध सुविधादाता, और प्रक्रिया की जटिलता। इसके अलावा, वह समयसीमा जो शुरुआत में कम दिखाई देती है, वह सहायक संस्थानों, प्रौद्योगिकियों और कौशल के उद्भव के साथ लंबी साबित हो सकती है। हर लेनदेन में कल की तुलना में आज कम समय लगता है। उदाहरण के लिए, जबकि एक समय प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए दो महीने की अवधि कम थी, डीमेटेरियलाइजेशन के बाद आज एक मिनट की अवधि लंबी मानी जाती है।

सीआईआरपी के लिए समयसीमा को तीन दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले, समयसीमा के पालन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मौजूद है। हितधारकों के पास सीआईआरपी को जल्दी पूरा करने के लिए आवश्यक प्रेरणा है क्योंकि उन्हें समाधान से लाभ मिलने वाला है, और यदि वे दी गई समय सीमा के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें परिसमापन के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया उनके नियंत्रण में है, इसी तरह समाधान योजना का कार्यान्वयन भी। दूसरा, त्वरित सीआईआरपी के लिए सुविधादाता हैं। आईपी योग्य, सक्षम और सशक्त पेशेवर हैं, जो पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। शांत अवधि के प्रावधान हैं जब कोई भी सीआईआरपी के तहत सीडी को परेशान नहीं करता है और अंतरिम वित्त की व्यवस्था भी करता है। तीसरा, चूंकि समय के साथ–साथ अधिक से अधिक सीआईआरपी को स्वीकृत किया जाता है और निस्तारित किया जाता है, इसलिए प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित और मानकीकृत और अक्सर स्वचलीकृत होती जाएंगी। संभवतः, मानक समाधान योजनाएँ सहजता से उपलब्ध होंगी। कुछ न्यायिक क्षेत्राधिकारों में प्रीपैक नामक एक प्रथा है, जहां हितधारक प्रक्रिया को केवल तभी शुरू करता है जब वह एक समाधान योजना के साथ उचित रूप से तैयार हो जाता है और उसके तुरंत बाद इसे बंद कर देता है।

हालांकि, समयसीमा के महत्व की सराहना करना महत्वपूर्ण है। जब सीडी ने चूक का तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी और इसलिए, उसको समाधान की जरूरत थी। सीआईआरपी अवधि के दौरान, आईपी निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करता है और सीडी के प्रचालनों की देखरेख एक कार्यशील संस्था के रूप में करता है और समाधान के बाद सीडी के स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में अनिश्चितता होती है। यदि इस तरह की स्थिति बहुत अधिक समय तक जारी रहती है, तो यह संभावना है कि संगठनात्मक पूंजी कम हो जाएगी, जिससे समाधान मुश्किल हो जाएगा। बहुत लंबी सीआईआरपी अवधि से सीडी को परिसमापन की ओर धकेले जाने की संभावना है, जो उसके परिसमापन मूल्य को भी कम करेगा। इसके अलावा, अपेक्षाकृत अधिक लंबी सीआईआरपी अवधि का अर्थ है एक निश्चित समय में बड़ी संख्या में सीडी का समाधान प्रक्रिया से गुजरना, जो आर्थिक विकास को बाधित करेगा। इसलिए, सीआईआरपी को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है 180 दिन के पश्चात नहीं।

उपन्यास 'एराउंड दी वर्ल्ड इन एट्टी डेज' में नायक 79 दिनों में पृथ्वी ग्रह की जहाज से परिकर्मा कर लेता है जबकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परिवहन और संचार सुविधाएं अल्पविकसित थीं। आधुनिक प्रौद्योगिकी और अत्यन्त जागरूक दिमाग के सभी प्रकार के लाभों के साथ 180 दिनों की अवधि लंबी साबित हो सकती है। आगे जाकर, सीआईआरपी संभवतः कुछ दिनों या घंटों में पूरी की जा सकती है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धि के उपयोग के साथ। प्रयास यह होना चाहिए कि बाद में जितनी जल्दी हो सके, वहां तक पहुंचने के लिए न केवल कोड की यूएसपी को संरक्षित किया जाए, बल्कि उसे बेहतर बनाया जाए। आइए समय न गंवाएं, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के शब्दों में, 'जीवन उसी से बना है'।

बॉक्स 6 सीओसी: लोक न्यास का एक संस्थान

ऋण न चुकाने की एक फर्म की विफलता बाजार का एक परिणाम है। इसलिए, कोड में दिवाला का निराकरण करने के लिए बाजार के नेतृत्व वाले समाधान की परिकल्पना की गई है। यह जहां भी संभव हो, फर्म के समाधान और जहां भी आवश्यक हो, यह उसके परिसमापन की पेशकश करता है। कोड का मानना है कि एक सीमित देयता फर्म इक्विटी और ऋण के बीच एक अनुबंध है। जब तक ऋण की पूर्ति की जाती है; निदेशक मंडल के प्रतिनिधित्व वाली इक्विटी का फर्म पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जब फर्म ऋण की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, तो दिवाला के निराकरण के लिए फर्म का नियंत्रण लेनदारों को, जिसका प्रतिनिधित्व सीओसी द्वारा किया जाता है, चला जाता है। सीओसी आरए से प्राप्त समाधान योजनाओं पर विचार करती है और फर्म के दिवालियेपन के निराकरण के लिए उनमें से सर्वश्रेष्ठ को मंजूरी देती है।

समाधान योजनाओं पर विचार करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को मंजूर करने के लिए दो क्षमताओं की आवश्यकता होती है, अर्थात देनदारियों के पुनर्गठन की क्षमता और वाणिज्यिक निर्णय लेने की क्षमता। आमतौर पर ओसी के पास देनदारियों के पुनर्गठन की क्षमता और इच्छुकता नहीं होती है। सीओसी जो कुछ भी उपलब्ध है, उसे तुरंत हासिल करने के लिए परिसमापन का विकल्प चुन सकता है बशर्ते उसमें ओसी शामिल हो। आम तौर पर एफसी में पुनर्गठन के बाद अपनी बकाया राशि के लिए इंतजार करने की गुंजाइश होती है। उनके पास यह निर्धारित करने की क्षमता भी होती है कि क्या कोई समाधान योजना संहिता के उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। उनकी क्षमताओं को देखते हुए, सीओसी में एफसी को शामिल किया गया है।

सीओसी अपनी संपत्ति के मूल्य को अधिक से अधिक करने के लिए फर्म को एक कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में पुनर्गठित करने के लिए आम तौर पर सीआईआरपी में चार प्रमुख वाणिज्यिक निर्णय लेती है।

(क) बाजार अर्थव्यवस्था में एक फर्म दो व्यापक कारणों से निष्पादन करने में विफल रहती है। सबसे पहले, यह एक ऐसे व्यवसाय को करता है जो नवप्रर्वतन जैसे बहिर्जात कारणों से अधिक अर्थक्षम नहीं रह गया हो। इस तरह की ज्यादातर फर्मों में आर्थिक संकट है और वे अस्थिर हैं। हालांकि, उनमें से कुछ के पास व्यवसाय लाइन को बदलने और अर्थक्षम बनने के लिए संसाधन हो सकते हैं। दूसरा, फर्म अंतर्जात कारणों से अच्छा नहीं कर रही हो जैसे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में उसकी असमर्थता, जबकि उसी व्यवसाय में अन्य फर्में अच्छा कर रही हों। इस तरह की अधिकांश फर्में वित्तीय संकट में हैं और वे अर्थक्षम हैं। हालांकि, उनमें से कुछ ने अपने संसाधनों को काफी कम कर दिया और वे अर्थक्षम नहीं रह गई हैं। सीओसी को इस बात की ठीक–ठीक पहचान करने की आवश्यकता है कि सीआईआरपी के तहत फर्म अर्थक्षम है या नहीं।

(ख) यदि फर्म अर्थक्षम है तो सीओसी को फर्म के पुनर्गठन के लिए आवश्यक समाधान योजना की कल्पना करनी चाहिए। काफी कुछ उसी तरह जब प्रमोटर आईपीओ में शेयरों के लिए अंशदान आमंत्रित करता है, सीओसी को फर्म के अंतर्निहित मूल्य के प्रति दृश्यता तैयार करने और फर्म के पुनर्गठन के लिए उपयुक्त समाधान योजनाओं को आमंत्रित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसे अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि इसकी जटिलता और व्यवसाय के पैमाने को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का आरए फर्म को पुनर्गठित कर सकता है; वह संभवतः क्या चीज है जो फर्म की विफलता का निराकरण कर सकती है; प्रत्याशित आरए फर्म के पुनर्गठन के लिए प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं को डिजाइन और प्रस्तुत करने में सक्षम कर सकें, उसके लिए समाधान योजनाओं; आदि की अर्थक्षमता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए क्या पैरामीटर हैं।

(ग) सीओसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि फर्म एक कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में चलती रहे और सीआईआरपी के दौरान उसका मूल्य नहीं बिगड़े। इस उद्देश्य के लिए, उसे एक सक्षम आईपी नियुक्त करना चाहिए जो एक कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में फर्म के व्यवसाय को उसकी इष्टतम क्षमता पर चला सके, समाधान योजनाओं के डिजाइन के लिए आरए को फर्म के बारे में पूर्ण, सही और समय पर जानकारी प्रदान करे और फर्म की संपत्ति की सुरक्षा करे। कंपनी को उसे अंतरिम वित्त की सुविधा अवश्य प्रदान करनी चाहिए, और जहां भी आवश्यकता हो, परिहार्य लेनदेन का पता लगाने में सहयोग करना चाहिए। इसे जल्द से जल्द सीआईआरपी को बंद करने के लिए विभिन्न कार्यों में तेजी लानी चाहिए।

(घ) कोड में यह परिकल्पना की गई है कि सीओसी केवल उन समाधान योजनाओं पर विचार करे जो/जिनमें (i) विश्वसनीय और सक्षम आरए से प्राप्त की गई हों, (ii) लागू कानूनों का अनुपालन करती हो, (iii) अर्थक्षम और व्यवहार्य हों, (iv) चूक का निराकरण करने की क्षमता हो, और (v) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हो। ये विचारणीयताएं सुनिश्चित करती हैं कि समाधान योजना दीर्घस्थायी आधार पर एक कार्यशील प्रतिष्ठन के रूप में फर्म का पुनर्गठन करे। इन अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं में से सीओसी को उस समाधान योजना की अवश्य मंजूरी देनी चाहिए जो योजना के तहत लेनदारों के लिए वसूली के बावजूद फर्म की संपत्ति के मूल्य को अधिक से अधिक करे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक निर्णय सटीक गणितीय सूत्र के अनुरूप नहीं होते हैं। वास्तव में, इसके लिए काफी पेशेवर निपुणता और कौशल की आवश्यकता होती है। सीओसी को एक अर्थक्षम फर्म की उस फर्म से भेद करने की अपनी क्षमता अवश्य बढ़ानी

चाहिए जो अर्थक्षम नहीं है और अर्थव्यवस्था के हित में सभी अर्थक्षम फर्मों का बचाव सुनिश्चित करना चाहिए और केवल उन्हीं फर्मों को बंद करने की अनुमति देनी चाहिए जो अर्थक्षम नहीं हैं। केवल तभी अर्थव्यवस्था कोड होने के पूर्ण लाभों को प्राप्त कर सकती है और इसकी सुस्थापित उद्देश्यों और कारणों को सही ठहरा सकती है।

एक फर्म कई हितधारकों के हितों का प्रतीक होती है। सीओसी या इसके सदस्य फर्म की संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। सीओसी फर्म और उसके हितधारकों के भाग्य की कुंजी है। यह समाधान प्रक्रिया के दौरान जनता के भरोसे का संरक्षक है। बीएलआरसी ने, अन्य बातों के साथ–साथ, दो डिजाइन सिद्धांतों, अर्थात् (क) सभी ऐसे लेनदारों की देनदारियों, जो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, की पूर्ति होनी चाहिए; और (ख) सभी लेनदारों के अधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा, का उपयोग किया। तदनुसार, कोड में उद्यमशीलता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए फर्म की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समाधान की परिकल्पना की गई है। इसलिए, सीओसी को फर्म की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिक से अधिक करना चाहिए और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना चाहिए, चाहे उसकी संरचना कैसी भी हो।

इसलिए, यह जरूरी है कि समाधान से हुए फायदे या नुकसान का हितधारकों द्वारा निष्पक्षता और समानता की संरचना के भीतर बंटवारा किया जाए। इसलिए कोड में अधिदेश है कि ओसी को पहले भुगतान किया जाए और कम से कम परिसमापन मूल्य का भुगतान तो किया जाए। एक फर्म को एफसी और ओसी से क्रेडिट मिलता है। एक फर्म के लिए न तो क्रेडिट पर्याप्त होता है और न ही राज्य के पास इसे बढ़ावा देने का कोई भी कारण है। उदाहरण के लिए, यदि ओसी को एक लेवल कार्य क्षेत्र नहीं दिया जाता है, तो वे क्रेडिट पर सामान सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। यदि उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती है, तो वे खत्म हो जाएंगे। यह ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य को निरर्थक करता है।

सीओसी को संहिता के उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। इसे अवश्य समाधान का अनुशीलन करना चाहिए और वसूली, परिसमापन या फर्म की बिक्री से बचना चाहिए। समाधान का अनुशीलन करते समय, इसे सभी हितधारकों के लाभ के लिए फर्म के मूल्य को अधिकतम करना चाहिए। इसे अपनी हैसियत और कोड के तहत प्रदत्त प्राधिकार को बनाए रखने के लिए कसौटी पर अवश्य खरा उतरना चाहिए।

कारपोरेट परिसमापन प्रक्रिया

जब समाधान संभव नहीं है, वहां सीडी की सीआईआरपी के बाद परिसमापन के लिए एक आदेश पारित किया जा सकता है। कोड में वे चार परिस्थितियाँ दी गई है जब परिसमापन के लिए एए आदेश जारी करता है:

(क) एए समाधान योजना, जो आरपी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है, निर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन न किए जाने के कारण अस्वीकृत करती है,

(ख) एए सीआईआरपी को पूरा करने के लिए अनुमेय समय के भीतर सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्राप्त नहीं करती है,

(ग) सीआईआरपी अवधि के दौरान, किसी भी समय सीओसी ने आवश्यक बहुमत के साथ निर्णय लिया है कि सीडी को परिसमाप्त कर दिया जाए और आरपी ने इसके बारे में एए को सूचित कर दिया है,

(घ) जहां सीडी से इतर किसी व्यक्ति द्वारा इस आधार पर परिसमापन आदेश के लिए आवेदन किया गया हो कि संबंधित सीडी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया गया है।

आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (परिसमापन विनियमन) 15 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित किया। विनियमनों में सीडी के लिए आईपी को उस स्थिति में एक परिसमापक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है जबकि वह सीडी से स्वतंत्र नहीं हो। ये आईपीई, जिसमें आईपी एक भागीदार या निदेशक है, के भागीदारों या निदेशकों को उसी परिसमापन प्रक्रिया में अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिबंधित करते हैं। ये परिसमापक, और परिसमापन में मदद करने वाले पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (ओं) और पेशेवर (रों) के लिए यह अपेक्षित हैं कि वे परिसंपत्ति के वितरण के हकदार हितधारकों में से किसी के साथ आर्थिक या व्यक्तिगत संबंध – प्रारंभिक और निरंतर– के बारे में प्रकट करें। ये विनियमन सार्वजनिक घोषणा की रीति और विषयवस्तु, हितधारकों के दावों की प्राप्ति और सत्यापन, परिसमापक द्वारा बनाए रखी, संरक्षित और प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों और रजिस्टरों, परिसंपत्तियों और प्रतिभूति हित की प्राप्ति के तरीके और हितधारकों को आगम के वितरण को निर्दिष्ट करते हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि एक परिसमापक को सामान्य रूप से नीलामी के माध्यम से परिसंपत्तियां बेचनी चाहिए। वह संपत्ति को निजी बिक्री के माध्यम से तभी बेच सकता है जबकि परिसंपत्ति नष्ट होने योग्य हो; यदि परिसंपत्ति तुरंत बेची नहीं जाती है तो उसके मूल्य में काफी अधिक गिरावट होने की संभावना है या परिसंपत्ति एक असफल नीलामी के आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाए। वह एक स्टैंडअलोन आधार पर संपत्ति बेच सकता है, या एक स्लम्प सेल में संपत्ति बेच सकता है, पार्सल में संपत्ति बेच सकता है या सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का एक सेट बेच सकता है। इन विनियमनों में यह व्यवस्था की गई है कि एक परिसमापक को देय शुल्क परिसमापन लागत का हिस्सा बनेगा। इन विनियमनों में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक परिसमापक को ऐसे शुल्क का और, ऐसी रीति से भुगतान किया जाएगा जैसा कि समाधान प्रक्रिया के दौरान सीओसी द्वारा तय किया गया हो। अन्य सभी मामलों में, परिसमापक अन्य परिसमापन लागतों की वसूली

गई राशि और वितरित की गई राशि के प्रतिशत के रूप में शुल्क का हकदार होगा।

परिसमापन विनियमनों के साथ पठित कोड निम्नलिखित रूप में परिसमापन प्रक्रिया नियंत्रित करता है:

(क) परिसमापन का प्रारंभः परिसमापन प्रक्रिया एए द्वारा पारित परिसमापन आदेश की तारीख से शुरू होती है। सीआईआरपी के लिए नियुक्त आरपी परिसमापन प्रयोजनों के लिए परिसमापक के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि उसे एए द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाए।

(ख) सार्वजनिक घोषणाः परिसमापक अपनी नियुक्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर, अंग्रेजी के एक और क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में, वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नामोद्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो, एक सार्वजनिक घोषणा करता है।

(ग) पंजीकृत मूल्यांककों की नियुक्तिः परिसमापक सीडी की संपत्ति के भौतिक सत्यापन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए मूल्यांकन मानकों के अनुसार गणना की गई संपत्ति को वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति करता है।

(घ) दावों का सत्यापनः परिसमापक दावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करता है।

(ङ) दावे की स्वीकृति/अस्वीकृतिः परिसमापक, सत्यापन के बाद, दावे को पूर्णतः या अंशतः, जैसा भी मामला हो, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। दावे की अस्वीकृति की स्थिति में, वह इस तरह के अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा और इस तरह के निर्णय के सात दिनों के भीतर लेनदारों को अपने निर्णय की सूचना देगा। लेनदार निर्णय प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर परिसमापक के निर्णय के खिलाफ एए से अपील कर सकता है।

(च) हितधारकों की सूची तैयार करनाः परिसमापक सभी हितधारकों की सूची तैयार करता है और उसे दावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि से 45 दिनों के भीतर एए को दायर करता है। वह उसकी सार्वजनिक घोषणा भी करता है।

(छ) प्रारंभिक रिपोर्टः परिसमापक समय और अनुमानित परिसमापन सहित पूंजी संरचना और सीडी की परिसंपत्तियों और देनदारियों और परिसमापन निष्पादित करने के लिए कार्रवाई की योजना का विवरण देते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे परिसमापन शुरू करने की तारीख से 75 दिनों के भीतर एए को प्रस्तुत करता है।

(ज) परिसंपत्ति ज्ञापनः परिसमापक परिसमापन शुरू होने की तारीख से 75 दिनों के भीतर परिसंपत्ति ज्ञापन तैयार करता है, जिसमें संपत्ति, बिक्री के अपेक्षित तरीके और प्राप्ति की अपेक्षित राशि का विवरण होता है और उसे एए के पास दायर करता है।

(झ) प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनाः परिसमापक उस तिमाही जिसमें वह नियुक्त किया जाता है की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर एए को पहली प्रगति रिपोर्ट सौंपता है और बाद में हर तिमाही के अंत के बाद 15 दिनों के भीतर तब तक प्रगति रिपोर्ट (टें) देता है जब तक कि वह परिसमापक के रूप में कार्य करता है।

(ञ) आगम का वितरणः परिसमापक परिसमापन सम्पदा में परिसंपत्ति की बिक्री पर वसूली से प्राप्त आय, धनराशि की प्राप्ति से 6 माह के भीतर, हितधारकों में वितरित करता है।

(ट) परिसमापन प्रक्रिया का समापनः परिसमापक 2 वर्ष की अवधि के भीतर सीडी को परिसमाप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा नहीं होने पर वह एए को ऐसे परिसमापन जारी रखने के लिए एक आवेदन करेगा, साथ ही एक रिपोर्ट में यह भी बताएगा कि परिसमापन क्यों पूरा नहीं हुआ है और यह भी बताएगा कि परिसमापन के लिए और कितना अतिरिक्त समय लगेगा।

(ठ) अंतिम रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरणः परिसमापन प्रक्रिया के पूरा होने पर, परिसमापक अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें परिसमापन के लेखा परीक्षित खातों, सीडी की परिसंपत्तियों का निपटान, बिक्री विवरण इत्यादि शामिल होते हैं और उसे सीडी समाप्त किए जाने के आवेदन के साथ एए को प्रस्तुत करता है।

(ड) लावारिस आयः एए द्वारा विघटन आदेश पारित किए जाने से पहले परिसमापक इस बात के लिए एए को आवेदन करता है कि परिसमापन के कोई भी दावारहित आगमों या अवितरित परिसम्पत्तियों या परिसमापन की तारीख को उसके हाथों में हितधारकों को देय किसी अन्य बैलेंस को भारत के सार्वजनिक लेखे में कम्पनी परिसमापन खाते में अदा करने के लिए एक आदेश जारी किया जाए।

(ढ) विघटनः एए तब एक आदेश पारित करता है कि सीडी उस आदेश की तारीख से भंग कर दिया जाएगा और सीडी तदनुसार भंग कर दी जाएगी।

(ण) परिसमापक विघटन आदेश के बाद 8 साल की अवधि के लिए अभिलेखों और कार्यवृत्त की भौतिक के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि संरक्षित करता है।

स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया

कोड में कहा गया है कि एक कारपोरेट व्यक्ति, जो स्वेच्छा से अपने आप परिसमापन करना चाहता है और जिसने कोई चूक नहीं की है, स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है। आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के साथ पठित कोड, जिसे 31 मार्च, 2017 को अधिसूचित किया गया था, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

विनियमनों में यह व्यवस्था की गई है कि कारपोरेट व्यक्ति उस स्थिति में स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है, जब कारपोरेट निकाय के अधिसंख्य निदेशक या नामित भागीदार इस आशय की घोषणा करते हैं कि (i) कारपोरेट निकाय का ओर कोई ऋण नहीं है या वह अपने ऋण का प्रस्तावित परिसमापन के तहत बेची जाने वाली संपत्तियों की आय से पूर्ण भुगतान करने में सक्षम होगा, और (ii) कारपोरेट निकाय को किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए परिसमाप्त नहीं किया जा रहा है। यदि परिसमापक की यह राय है कि परिसमापन किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए किया जा रहा है या कारपोरेट निकाय परिसमापन में बेची जाने वाली परिसंपत्ति के आगमों से अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाएगा, तो वह एए को आवेदन करेगा कि परिसमापन की प्रक्रिया निलंबित की जाए और ऐसा कोई आदेश पारित किया जाए जो वह उपयुक्त समझे। परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित अधिकांश प्रावधान (संहिता की धारा 35 से 53) स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही पर भी लागू होते हैं।

विनियमों में कारपोरेट निकाय के लिए आईपी को उस स्थिति में एक परिसमापक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है जबकि वह कारपोरेट निकाय से स्वतंत्र नहीं हो। ये विनियमन आईपीई, जिसमें आईपी एक भागीदार या निदेशक है, के भागीदारों या निदेशकों को उसी परिसमापन प्रक्रिया में अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिबंधित करता हैं। ये परिसमापक, और परिसमापन में मदद करने वाले पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (ओं) और पेशेवर (रों) के लिए यह अपेक्षित करते हैं कि वे हितधारकों में से किसी के भी या कारपोरेट निकाय के साथ आर्थिक या व्यक्तिगत संबंध – प्रारंभिक और निरंतर– के बारे में प्रकट करें।

ये विनियमन सार्वजनिक घोषणा की रीति और विषयवस्तु, हितधारकों के दावों की प्राप्ति और सत्यापन, परिसमापक द्वारा बनाए रखी, संरक्षित और प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों और रजिस्टरों, परिसंपत्तियों की वसूली और हितधारकों को आगम के वितरण, अवशिष्ट परिसंपत्तियों के विवरण, और आखिरकार, कारपोरेट निकाय के विघटन को निर्दिष्ट करते हैं। परिसमापक के लिए यह अपेक्षित करते हैं कि वह कारपोरेट निकाय के विघटन के बाद कम से कम आठ वर्ष के लिए रिपोर्टों, रजिस्टरों और लेखा–बहियों की भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रति या तो अपने पास या आईयू के पास संरक्षित रखे।

ग.3 हिमायत और जागरूकता

जबकि सरकार और आईबीबीआई नीति बना सकते हैं और अर्थव्यवस्था में कतिपय लेनदेन के लिए विधिक और विनियामक ढांचा तैयार कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है कि नीति और नियम जमीनी वास्तविकताओं के साथ तालमेल रखें और हितधारक नीति और विनियमनों के अनुसार लेनदेन करें। किसी भी सुधार के शुरुआती दिनों में, इस तरह का नियोजन हितधारकों के लिए नीति और विनियमनों के संदेश को ले जाने और उन्हें संभव उपयोगों और उपयोग के तरीके से अवगत कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हितधारकों को कोड, विनियामक ढांचे और इकोसिस्टम से अवगत होना चाहिए, जो सभी भारतीय संदर्भ में नए हैं।

अध्यक्ष, आईबीबीआई ने अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान देष भर में भांति–भांति के संस्थानों (आरबीआई, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईपीए, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, अकादमियों) द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता पर आयोजित 45 आयोजनों में (कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, राउंडटेबल, वर्कशॉप, इत्यादि) में विभिन्न हैसियतों (फैकल्टी, पैनलिस्ट, वक्ता, सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि, आदि) से भाग लिया। इन आयोजनों का विवरण तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है।

जबकि आईबीबीआई नीति–निर्माण में हितधारकों का इनपुट प्राप्त करने के लिए उनके साथ जुड़ता है, विनियामक के कार्य के बारे में वापस उन्हें रिपोर्ट करना और उन्हें विनियामक द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सूचित करना और प्राप्त परिणामों के बारे में बताना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, आईबीबीआई अपनी स्थापना के बाद से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर रहा है। उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आईबीबीआई की वेबसाइट पर बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार के लिए रखी गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अक्टूबर – दिसंबर, 2016 और जनवरी – मार्च, 2017 की अवधि के लिए दो न्यूजलेटर प्रकाशित किए गए थे। न्यूजलेटर ने एक व्यापक दिवाला और शोधन अक्षमता कानून और उसके आगे कोड के अधिनियमन की अनुभूत जरूरत के बारे में जानकारी प्रदान की। इसने कोड के कतिपय प्रावधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित विनियमनों को स्थापित करने के संबंधी आईबीबीआई प्रारंभिक कार्यों को भी प्रस्तुत किया।

तालिका 5: अध्यक्ष, आईबीबीआई ने आयोजनों में भाग लिया

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	आयोजक	आयोजन	विषय
1	17.10.16	मसूरी	एलबीएसएनएए	प्रशिक्षण	दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए विनियामक संरचना
2	21.10.16	नई दिल्ली	एनएलयू	प्रशिक्षण	प्रतिस्पर्धा कानून एवं शोधन अक्षमता कानून
3	24.10.16	मुंबई	बीएसई	राउंडटेबल	मसौदा सीआईआरपी एवं परिसमापन विनियम
4	24.10.16	मुंबई	एमआईएनटी, एचटी मीडिया	कान्फ्रेंस	दिवाला और शोधन अक्षमता सुधार
5	25.10.16	चेन्नई	आईसीएसआई	राउंडटेबल	मसौदा आईपी एवं आईपीए विनियमन
6	26.10.16	कोलकाता	आईसीएमएआई	राउंडटेबल	मसौदा आईपी एवं आईपीए विनियमन
7	28.10.16	नई दिल्ली	एसोचैम	राउंडटेबल	मसौदा सीआईआरपी एवं परिसमापन विनियमन
8	12.11.16	नई दिल्ली	सीएलबीए	कान्फ्रेंस	प्रतिस्पर्धा कानून एवं क्षेत्रीय विनियमन
9	17.11.16	गांधीनगर	आईसीएसआई	कन्वेंशन	शासन को समर्थ करना और आईबीसी
10	17.11.16	अहमदाबाद	आईसीएआई	सेमिनार	आईबीसी
11	28.11.16	नई दिल्ली	आईबीबीआई	समारोह	आईपीए के पंजीकरण की शुरुआत
12	30.11.16	नई दिल्ली	आईबीबीआई	समारोह	आईपी के पंजीकरण की शुरुआत
13	01.12.16	मानेसर	आईआईसीए	वार्तालाप	आईबीसी विनियमन
14	10.12.16	भुवनेश्वर	आईसीएमएआई	कान्फ्रेंस	आईबीसी वैश्विक मानकों की तरफ बढ़ना
15	10.12.16	भुवनेश्वर	आईसीएमएआई	राउंडटेबल	सीआईआरपी एवं परिसमापन विनियमन
16	11.12.16	भुवनेश्वर	आईसीएसआई	सेमिनार	आईबीसी
17	16.12.16	मुंबई	आईसीएसआई	कॉन्क्लेव	आईबीसी
18	16.12.16	मुंबई	आईजीआईडीआर	कान्फ्रेंस	आईबीसी
19	16.12.16	मुंबई	आईजीआईडीआर	पैनल	आईबीसी का कार्यान्वयन
20	16.12.16	मुंबई	मिंट, एचटी मीडिया	कान्फ्रेंस	आईबीसी
21	16.12.16	मुंबई	मिंट, एचटी मीडिया	पैनल	तानित परिसम्पत्ति निवेष
22	17.12.16	नई दिल्ली	आईसीएसआई	कान्फ्रेंस	आईबीसी
23	23.12.16	मुंबई	आईसीएमएआई	सेमिनार	आईबीसी
24	27.12.16	तिरुपति	इंडियन इकोनोमिक एसोशिएसन	मेमोरियल	ऋण बाजार एवं दिवाला
25	12.01.17	कोलकाता	सीआईआई	सेमिनार	आईबीसी . प्रभाव विश्लेषण
26	12.01.17	कोलकाता	एमसीसीआई	सत्र	आईबीसी . एक अंतर्दृष्टि
27	13.01.17	कोलकाता	बीसीसी–आई	सेमिनार	आईबीसी
28	13.01.17	कोलकाता	आईसीएमएआई	सेमिनार	आईबीसी
29	14.01.17	कोलकाता	आईसीएसआई	सेमिनार	आईबीसी
30	15.01.17	नई दिल्ली	आईसीएआई	सेमिनार	आईबीसी
31	28.01.17	मुंबई	आईसीएआई	सेमिनार	आईबीसी
32	02.02.17	दिल्ली	एनआईपीएफपी – ट्राई	प्रशिक्षण	विनियामक के कार्यकारी कार्य
33	10.02.17	नई दिल्ली	आईआईएम, काशीपुर	कान्फ्रेंस	विनियामक उद्देश्यों एवं संरचना को वाहतुकारी करना
34	12.02.17	गाजियाबाद	आईएमएस, गाजियाबाद	कान्फ्रेंस	कारपोरेट अभिशासनः पुरानी एवं भावी
35	17.02.17	मुंबई	आरबीआई	राउंडटेबल	मसौदा आईयू विनियमन
36	18.02.17	नई दिल्ली	एसोचैम	राउंडटेबल	मसौदा आईयू विनियमन
37	28.02.17	नई दिल्ली	एसोचैम	राउंडटेबल	स्वैच्छिक परिसमापन के लिए मसौदा विनियमन
38	07.03.17	नई दिल्ली	पीएचडीसीसीआई एवं आईसीएसआई	सेमिनार	आईपी के लिए अवसर एवं चुनौतियां

39	10.03.17	नई दिल्ली	भारतीय वित सलाहकार समिति	सेमिनार	आईबीसी
40	19.03.17	लखनऊ	आईसीएमएआई	कान्फ्रेंस	सीएमए और आईपी के साथ भारत को मजबूत करना
41	24.03.17	मुंबई	सीआईआई	कान्फ्रेंस	आईबीसी . प्रभाव विश्लेषण
42	25.03.17	मुंबई	आईसीएसआई	सेमिनार	आईबीसी
43	26.03.17	नई दिल्ली	बाईआईसीए	वार्तालाप	आईबीसी संभावित चुनौतियां एवं संभावनाएं
44	26.03.17	नई दिल्ली	ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी	अखिल भारतीय बैठक	आर्थिक कानून
45	27.03.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	आईपी वर्कशॉप	आईबीसी

घ बोर्ड के कार्य

कोड कार्यों एवं दायित्वों के साथ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। तथापि, यह प्रत्याशित था कि बोर्ड की स्थापना करना तथा इसे प्रचालन में लाने में कुछ समय लगेगा। इसके संबंध में समय के नुकसान से बचने के लिए, कोड ने सरकार को इसकी स्थापना होने तक बोर्ड की शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक वित्तीय क्षेत्र का विनियामक पदनामित करने में सक्षम बनाता है। इसने स्पष्ट रूप से बोर्ड को विनियामक के पदनाम की व्यवस्था दी, क्योंकि बोर्ड की संरचना, क्षेत्र, दायित्व एवं कार्य, जैसा कि कोड में परिकल्पित है, उस वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के सदृश हैं। सरकार ने अल्पकालिक प्रावधान की बजाय, 1 अक्टूबर, 2016 को बोर्ड की स्थापना की।

एक वित्तीय विनियामक की तरह, आईबीबीआई ने मौटे तौर पर तीन कार्य निर्धारित किए हैं, नामतः (क) अर्ध–विधायी कार्यः बोर्ड बाजार बिचवइयों एवं प्रोसेस के लिए विनियमन बनाता है; (ख) कार्यपालक कार्यः बोर्ड सेवा प्रदायकों को रजिस्टर करता है और दिवाला प्रक्रिया हेतु विनियमित करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण एवं सतत् व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बाजार बिचवईयों के लिए व्यावसायिक विकास एवं विशेषज्ञता हेतु उपाय करता है; और (ग) अर्ध–न्यायिक कार्यः जो सेवा प्रदायकों को अपने व्यवस्थित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिनिर्णित करता है।

अर्ध–विधायी कार्य

कोड, आईबीबीआई को दिवाला एवं शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों में विनियमन एवं दिशानिर्देश बनाने तथा आईपीए, आईपी और आईयू को दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। यह इस शर्त के अधीन होता है कि विनियमनः (क) कोड के प्रावधानों को क्रियान्वित करते हों; (ख) कोड एवं इसके अधीन बने नियमों के अनुसार हों; (ग) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा तैयार किए गए हों और (घ) यथाशीघ्र 30 दिन हेतु संसद के प्रत्येक सदन में रखे गए हों।

आईबीबीआई की स्थापना से पहले, अधिकांश विनियमनों के मसौदे, जो शुरु में जारी किए गए थे, एमसीए द्वारा स्थापित कार्यसमूहो द्वारा तैयार किए गए थे। तथापि, इन विनियमनों को अंतिम रूप देने से पहले, आईबीबीआई ने हितधारकों का विनियमन हेतु प्रभावी रूप से काम में लाने के लिए पारदर्शी एवं परामर्शी प्रक्रिया को अपनाया। परामर्शी प्रक्रिया कारक पारदर्शी प्रक्रिया जमीनी वास्तविकता और सामूहिक चयन को सक्षम बनाता है। जनता की भागीदारी, विशेष रूप से हितधारकों की भागीदारी एवं विनियमित, विनियमन बनाने में सुनिश्चित करती है कि विनियमन उन इच्छुक एवं विनियमनों से प्रभावित लोगों व्यक्तियों की कानूनी जरुरतों से अवगत होते हैं। आईबीबीआई मौटे तौर पर तीन मार्गों के जरिए काम करता है, (क) यह हितधारकों के साथ हल करने के लिए मांगे गए उक्त विनियमनों के मुद्दों की समझ को पुनः मान्य बनाने के लिए कई गोलमेजो में मसौदा विनियमनों पर और मुद्दों के समाधान हेतु ऐसे विनियमनों की उपयुक्तता पर चर्चा करता है; (ख) यह प्रत्येक मसौदा विनियमन एवं उप–विनियमन पर इलेक्ट्रॉनिक मंच के जरिए जनता की टिप्पणियां प्राप्त करता है; और (ग) यह मसौदा विनियमनों पर संगत एसी की सलाह लेता है। विनियमन बनाने की प्रक्रिया जनता की टिप्पणियों, गोलमेज पर प्राप्त फीडबैक तथा एसी की सलाह पर विचार करने के बाद विनियमनों को अंतिम रूप देने तथा स्वीकृत करने में जीबी को सहयोग करती है। आईबीबीआई ने वर्ष 2016–17 में दस विनियमनों को अधिसूचित किया, जैसा कि तालिका 6 में प्रस्तुत है।

तालिका 6: वर्ष 2016–17 में अधिसूचित विनियमन

अधिसूचना की तारीख	विनियमन
21.11.2016	आईबीबीआई (दिवाला व्यावासायिक एजेंसी) विनियमन, 2016
21.11.2016	आईबीबीआई (मॉडल उप–नियम और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का अधिशासी बोर्ड) विनियमन, 2016
23.11.2016	आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016
30.11.2016	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
15.12.2016	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
31.01.2017	आईबीबीआई (अधिशासी बोर्ड बैठक हेतु प्रक्रिया) विनियमन, 2017
31.01.2017	आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017
31.01.2017	आईबीबीआई (अनुसंधान सहयोगियों एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियमन, 2017
31.03.2017	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017
31.03.2017	आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएँ) विनियमन, 2017

सलाहकार समिति

एसीज सामान्य तौर पर उभरते विचारों के लिए तथा व्यवस्थापक को व्यवसायिक विवेक एवं बाजार जानकारी प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ बोर्ड के रूप में काम करता है। आई बी बी आई ने आई बी बी आई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 की अधिसूचना तथा तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए दो स्थायी सलाहकार समितियों का निम्नुसार गठन किया:

(क) सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति: तालिका 7 में दी गई रचनानुसार 18 अक्टूबर, 2016 को इसका गठन किया गया।

तालिका 7: सेवा प्रदायकों संबंधी सलाहकार समितियों का गठन

क्रम सं:	नाम और पद	समिति में पद
1	श्री मोहनदास पई, अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन	अध्यक्ष
2	श्री के.वी. आर मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
3	डॉ० बिमल एन. पटेल, निदेशक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	सदस्य
4	डॉ अजय एन. शाह, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी	सदस्य
5	श्री अमरजीत सिंह चन्ढोक, वरिष्ठ अधिवक्ता	सदस्य
6	श्री जे रंगनायकुलु, कार्यकारी निदेशक, सेबी	सदस्य
7	श्री रवि नारायण, उपाध्यक्ष, एनएसई	सदस्य
8	अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	सदस्य
9	अध्यक्ष, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान	सदस्य

(ख) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान संबंधी सलाहकार समिति: इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को तालिका–8 में दिए गए गठन के अनुसार किया गया था।

तालिका 8: कॉर्पोरेट दिवाला समाधान संबंधी सलाहकार समिति का गठन:

क्रम सं:	नाम और स्थिति	समिति में पद
1	श्री उदय कोटक, कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोटक महिन्द्रा बैंक	अध्यक्ष
2	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
3	श्री आशीष कुमार चौहान, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बीएसई लिमिटेड	सदस्य
4	श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष, क्रेडिट इंफामेशन ब्यूरों (इंडिया) लिमिटेड	सदस्य
5	डॉ० ओंकार गोस्वामी, अध्यक्ष, सीईआरजी एडवाइजरी, प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य
6	श्री सोमशेखर सुर्दशन, कानूनी परामर्शदाता	सदस्य
7	अध्यक्ष, भारतीय लागत सेवा संस्थान	सदस्य
8	अध्यक्ष, एनसीएलटी और एनसीएलएटी बार एसोसिएशन	सदस्य

कार्यपालक कार्य

दिवाला पेशेवर

आईपी विनियमन 29 नवंबर, 2016 को लागू किया गया। 18 दिवाला पेशेवरों को पंजीकृत किया गया था और 30 नवंबर, 2016 को एक कार्यक्रम में श्री तपन रे, सचिव, एमसीए के हाथों से पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए थे। 31 दिसंबर, 2016 तक विनियमन 9 के तहत 977 व्यक्ति दिवाला पेशेवर के साथ में पंजीकृत थे उनका पंजीकरण छह माह के लिए वैध था। उनके पंजीकरण 30 जून, 2017 को समाप्त थे। 31 दिसंबर, 2016 से व्यक्ति, जिनके पास वांछित योग्यता एवं अनुभव है, और जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें विनियमन 7 के तहत दिवाला पेशेवर (आईपी) के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है। इस श्रेणी में, 96 व्यक्तियों को आईपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 31 मार्च, 2017. को पंजीकरण में प्रगति का विवरण, तिमाही आधार पर तालिका 9 में प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च, 2017 तक पंजीकृत आईपी का क्षेत्रवार वितरण तालिका 10 में बताया गया है।

तालिका 9: दिवाला पेशेवरों का पंजीकरण (संख्या)

तिमाही	तिमाही के दौरान पंजीकृत आई पीज				तिमाही के अंत में आई पी			
	आईसीएआई के आईआईआईपी	आईसीएसआई आईपीए	आईसीएमएआई के आईपीए	कुल	आईआईआईपी के आईसीएआई	आईसीएसआई के आईपीए	आईसीएमएआई के आईपीए	कुल
अक्टूबर–दिसम्बर, 2016	713	221	43	977	713	221	43	977*
जनवरी–मार्च, 2017	33	51	12	96	33	51	12	96

*इन दिवाला पेशेवरों का पंजीकरण 30 जून, 2017 को समाप्त है।

आईपीए के साथ नामांकित कोई व्यक्ति आईपी के रूप में कार्यकलाप शुरू करने के लिए पंजीकरण की मांग करते हुए आवेदन करता है। आवेदन पर विचार करने पर, आईबीबीआई पंजीकरण मंजूर कर सकता है। तथापि, यदि यह प्रथम दृष्टया यह राय रखता है कि मांगे गए पंजीकरण को स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो इसे आवेदक को सूचित किया जाता है, जिससे उसे यह बताने को कहा जाता है कि उसे पंजीकरण क्यों दिया जाना चाहिए। आवेदक की बात पर विचार करने तथा उसकी बात सुनने पर यदि आईबीबीआई आवेदन को अस्वीकार करना चाहता है तो वह इसका कारण बताते हुए इसे अस्वीकार कर सकता है। वर्ष 2016–17 में, आईबीबीआई ने दो आवेदनों को अस्वीकार करने के ऐसे दो आदेश जारी किए – एक में यह आधार था कि आवेदक एक स्वस्थ एवं उचित व्यक्ति नहीं था और दूसरे में यह आधार था कि आवेदक रोजगार में था।

तालिका 10: दिवाला पेशेवरों का क्षेत्रीय वितरण (संख्या)

शहर / क्षेत्र	विनियमन के तहत आईसीएआई का आईआईआईपी		विनियमन के तहत आईसीएसआई आईपीए		विनियमन के तहत आईसीएमएआई का आईपीए		जोड़	
	9	7	9	7	9	7	9	7
नई दिल्ली	224	5	77	19	18	7	319	31
उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर	109	5	36	13	2	3	147	21
मुम्बई	100	11	29	4	4	0	133	15
पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर	75	4	26	5	9	0	110	9
चेन्नई	41	0	5	1	1	0	47	1
दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर	53	2	23	5	2	0	78	7
कोलकाता	81	6	18	3	6	1	105	10
पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर	30	0	7	1	1	1	38	2
कुल	**713**	**33**	**221**	**51**	**43**	**12**	**977**	**96**

स्पष्ट है कि दिवाला पेशा नया है और कोड के तहत प्रक्रियाएं अधिक जटिल हैं, आईबीबीआई ने कॉर्पोरेट दिवाला क्षेत्र में दिवाला पेशेवरों की क्षमता निर्माण का प्रयास किया है। इस संबंध में बाजार एवं आईपीए के प्रयासों एवं पहलों को पूरा करने के लिए आईबीबीआई ने दिवाला पेशेवरों के लिए एक दो–दिवसीय कार्यशाला शुरू की है। इस तरह की पहली कार्यशाला 27 एवं 28 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में शुरू की गई थी।

दिवाला व्यावसायिक कम्पनियां

31 मार्च, 2017 को, तीन दिवाला व्यावसायिक कम्पनियों को बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई थी, जैसा कि तालिका 11 में दर्शाया गया है।

दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी विनियमन को 22 नवंबर, 2016 को लागू किया गया। दो आईपीए, नामतः इंडियन इंस्टीट्यूट इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईसीएआई का आईआईआईपी) और आईसीएसआई इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी[19] (आईसीएसआईआईपीए) पंजीकृत की गयी और 28 नवंबर, 2016 को एक कार्यक्रम में, श्री अरुण जेटली, वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री के हाथों पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए थे। दूसरा आईपीए नामतः, इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउण्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएसएआई का आईपीए) 30 नवंबर, 2016 को पंजीकरण मंजूर किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च, 2017 को तीन आईपीए पंजीकृत थे; जैसा कि तालिका 12 में दर्शाया गया है।

तालिका 11: 31 मार्च, 2017 को मान्य आईपीई

क्रम सं.	मान्यता देने की तारीख	आईपीई का नाम
1	01.03.2017	आईआरआर इंसोलवेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2	01.03.2017	एएए इंसोलवेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
3	30.03.2017	विटवर्थ इंसोलवेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड

तालिका 12: 31 मार्च, 2017 को पंजीकृत आईपीए

क्रम सं.	पंजीकरण की तारीख	आईपीए का नाम	निम्न द्वारा समर्पित
1	28.11.2016	इंडियन इंस्टीट्यूट इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
2	28.11.2016	इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी	भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
3	30.11.2016	इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउण्टैंट ऑफ इंडिया	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

[19]आईपीए का नाम बाद में बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कर दिया गया।

सीमित दिवाला परीक्षा

अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के तहत, कोई व्यक्ति आईपी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होता है यदि उसने सीमित दिवाला परीक्षा (परीक्षा) उत्तीर्ण की हो। आईबीबीआई ने 30 नवंबर, 2016 को पाठ्यक्रम फॉर्मेट तथा परीक्षा बारम्बारता प्रकाशित किया और 31 दिसंबर, 2016 को परीक्षा शुरू की। इसने परीक्षा में बैठ रहे व्यक्तियों के लाभ के लिए सामान्य प्रश्न पत्र तैयार किए।

अन्य पाठ्यक्रम आदि 31 दिसंबर, 2016 से 30 जून, 2017 तक आयोजित परीक्षाओं पर लागू है। परीक्षा को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उद्देश्य से ऑनलाइन (अनुशासित माहौल में कंप्यूटर–आधारित) आयोजित किया जाता है। यह इस दिन देश में 100 से अधिक स्थानों में उपलब्ध रहता है। इसमें परीक्षा समय दो घंटा होती है। परीक्षा को एनआईएसएम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 31 मार्च, 2017 तक, 789 उम्मीदवारों ने कुल 1183 प्रयास किए और 266 (34%) ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा में उम्मीदवारों के निष्पादन को तालिका 13 में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 13: सीमित दिवाला परीक्षा, 2016–17

क्षेत्र	कुल प्रयास	सफल प्रयास संख्या
पूर्वी	159	32
उत्तरी	491	109
पश्चिमी	354	34
दक्षिणी	179	91
अखिल भारतीय	**1183**	**266**

अर्धन्यायिक कार्य

उल्लेखनीय अवधि में कोई अर्द्य न्यायिक कार्य नहीं किया गया था।

ड परिणामों का विश्लेषण

यह अनुभाग कोड के तहत इसके अधिनियमन के समय से 31 मार्च, 2017 तक शुरू किए गए एवं शोधित सीआईआरपी के संबंध में प्राप्त मापको के ब्यौरों को दर्शाता है। अनुभाग, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईबीबीआई और उच्च न्यायालय द्वारा इसके तहत कोड एवं विभिन्न नियमों और विनियमनों की व्याख्या के संबंध में उभरते विधिसंग्रह के संक्षिप्त रूप को भी दर्शाता है।

कारपोरेट दिवाला समाधान

सीआईआरपी विनियमन को 1 दिसंबर, 2017 को लागू किया गया। 31 मार्च, 2017 तक 37 सीआईआरपी शुरू किए गए थे। इन सीआईआरपी का श्रेणीवार आरम्भन तालिका 14 में उपलब्ध है।

तालिका 14: सीआईआरपीज का प्रांरभ

निम्न द्वारा शुरू किए गए सीआईआरपी	कारपोरेट देनदारों की संख्या
वित्तीय लेनदार	8
ऑपरेशनल क्रेडिटर्स	7
कॉर्पोरेट देनदार	22
कुल	**37**

स्वीकृत आवेदनों में अंतर्निहित डिफॉल्ट कुछ लाख रुपए से कुछ हजार करोड़ रुपए तक व्यवस्थित स्वीकृत आवेदनों से आधारभूत चूक ब्यौरे तालिका 15 और 16 में दर्शाए गए हैं। एक आवेदन को अपील पर बंद कर दिया गया था। शेष आवेदन 31 मार्च, 2017 को प्रक्रियाधीन थे। शुरू किए गए सीआईआरपी के क्षेत्रवार ब्यौरे तालिका 16 में दर्शाए गए हैं।

सीआईआरपी सामान्य तौर पर 180 दिन लेता है। चूंकि, सीआईआरपी पिछली तिमाही में स्वीकृत किए गए थें। वर्ष के दौरान कोई सीआईआरपी पूरा नहीं हुआ है। अतः, 31 मार्च, 2017 तक समापन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी।

उभरता विधि-संग्रह

यह अनुभाग, कोड से संबंधित मामलों में 31 मार्च, 2017 तक न्यायिक एवं अर्ध–न्यायिक निकायों के चुनिंदा निर्णयों के सार को प्रस्तुत करता है।

उच्च न्यायालय

इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लि० बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य डब्ल्यूपी(एलडीजी) सं. 2017 का 143

कोड की धारा 7 के तहत इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन को एनसीएलअी द्वारा 17 जनवरी, 2017 को स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता, इसकी स्वीकृति से व्यथित था, उसने कोड के प्राधिकृत को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है। जिसमें उसने तदर्थ रहित हेतु रोक की मांग की है। इसने स्वीकृति के विरुद्ध एनसीएलएटी में भी एक अपील दायर की है। याचिका को खारिज करते समय अपने आदेश, दिनांक 23 फरवरी, 2017 के तहत उच्च न्यायालय ने नोट किया कि : *"चूंकि मुख्य आदेश चुनौती का विषय–वस्तु बन गया है, प्राधिकार की चुनौती विवेकसम्मत बन गई है"* यह भी मत दिया गया कि आईआरपी की नियुक्ति के कार्य को स्थगित करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ पक्षपात नहीं होगा।

अधिनिर्णायक का प्राधिकरण

आईसीआईसीआई बैंक लि० बनाम मैसर्स इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीपी सं 01/1 एवं बीपी/एनसीएलटी/एमएएच/2016)

जैसा कि एफ सी, आईसीआईसीआई बैंक ने सीडी, इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सीआईआरपी शुरू करने के लिए कोड की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है। तथापि, सीडी ने आपत्ति दायर की है कि सीडी के दायित्व और सीडी के विरूद्ध उपचारी कार्रवाई महाराष्ट्र रिलीफ अण्र्डटेकिंग (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1958 (एम आर यू अधिनियम) के तहत एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा, एमआरयू अधिनियम की धारा 4 में गैर–परिवर्तनीय खण्ड सीडी के दायित्वों से संबंधित किसी उपचारी एवं सभी कार्यवाहियों को स्थगित करता है। आगे यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि कोड एवं एम आर यू एमआरयू अधिनियम का उद्देश्य (बेरोजगारी को रोकना) अधिक प्रशंसनीय है, उसके गैर–परिवर्तनीय खण्ड कोड में गैर–परिवर्तनीय खण्ड से बाधित नहीं होंगे।एए ने नोट किया कि कोड एमआरयू अधिनियम के बाद अस्तित्व में आया और इसलिए, कोड में गैर–बाधाकारी खण्ड एमआरयू अधिनियम कोड अस्थायी रूप से प्रवृत्त किसी अन्य कानून में प्रचलित हैं। यह भी नोट किया जाता है कि एमआरयू अधिनियम का उद्देश्य मौजूदा कर्मचारियों की बेरोजगारी को रोकना है और सीआईआरपी में सीडी की स्वीकृति का तात्पर्य रोजगार को समाप्त करने से नहीं है। दिनांक 17 जनवरी, 2017 के आदेश के तहत आवेदन को स्वीकार करते समय एए ने तर्क दिया कि *''यह स्पष्ट है कि कारपोरेट देनदार ने भुगतान करने में चूक की है; जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और उसने सूचना उपयोगिता के साथ चेक का रिकॉर्ड रखा है और उसने दिवाला समाधान व्यवसायिक का नाम भी लिया है, जिसने अंतरिम समाधान व्यवसायिक के रूप में काम किया, जिसकी यह पीठ है, उसने नोटिस किया कि चूक हुई है तथा प्रस्तावित समाधान व्यवसायिक के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं है, इसलिए, धारा 7 की उप–धारा (2) के तहत आवेदन को पूर्ण रूप में स्वीकृत किया गया है। तदनुसार, यह पीठ विलम्बन काम घोषित करते हुए इस आवेदन को एतद्द्वारा स्वीकार करती है।"* कोड के तहत सीआईआरपी में स्वीकृत यह पहला सीडी है।

तालिका 15: सीआईआरपी में आवेदकों की स्वीकृति

क्रम सं.	स्वीकृति की तारीख	आवेदनकर्ता	कारपोरेट देनदार का नाम	आधारभूत चूक (रु. करोड़ में)
1	17.01.2017	एफसी	इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लि०	101.92
2	18.01.2017	सीडी	निक्को कारपोरेशन लि०	405.01
3	18.01.2017	सीडी	यूबी इंजीनियरिंग लि०	116.80
4	19.01.2017	एफसी	भूपेन इलेक्ट्रॉनिक लि०	4.82
5	23.01.2017	सीडी	सिनर्जी–डोरवे ऑटोमोटिव लि०	741.33
6	25.01.2017	सीडी	रेव स्कैन्स प्रा० लि०	13.66
7	30.01.2017	एफसी	श्रीमेटालिक लि०	108.27
8	10.02.2017	सीडी	कामिनेनी स्टील एण्ड पावर इंडिया प्रा० लि०	1405.01
9	10.02.2017	सीडी	वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर लि०	1102.78
10	14.02.2017	सीडी	हिंद मोटर्स लि०	6.29
11	16.02.2017	सीडी	केशव स्पौज एण्ड इनर्जी प्रा० लि०	85.48
12	17.02.2017	ओसी	मिडास टच एक्सपोर्ट प्रा० लि०	0.15
13	17.02.2017	एफसी	स्टॉरलॉग इंटरप्राइजेजे लि०	27.78
14	20.02.2017	सीडी	हिंदू मोटर्स मोहाली प्रा० लि०	3.09
15	23.02.2017	एफसी	रायपुर पावर एंड स्टील लि०	17.37
16	24.02.2017	सीडी	छपारिया इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	38.35
17	24.02.2017	ओसी	यूनिमार्क रेमीडीज लि०	0.61
18	27.02.2017	ओसी	रेई एग्रो लि०	0.10
19	02.03.2017	सीडी	श्री राजेश्वर वीविंग मिल्स प्रा० लि०	15.83
20	03.03.2017	सीडी	वीएनआर इंफ्रा मेटल्स प्रा० लि०	88.33
21	06.03.2017	ओसी	एमसीएल ग्लोबल स्टील प्रा० लि०	9.11
22	06.03.2017	सीडी	अल्ट्रा ड्राईटेक इंजीनियरिंग लि०	18.39
23	08.03.2017	सीडी	फेसर स्टील लि०	34.58
24	09.03.2017	सीडी	गुप्ता कोल इंडिया प्रा० लि०	2580.07
25	09.03.2017	सीडी	हिंद मोटर्स इंडिया लि	3.33
26	15.03.2017	ओसी	जनता केमिकल्स प्रा० लि०	0.23
27	15.03.2017	एफसी	कादेवी इंडस्ट्रीज लि०	171.10
28	16.03.2017	सीडी	रिकॉर्ड्स एवं मेडिकेयर सिस्टम प्रा० लि०	101.09
29	17.03.2017	सीडी	जेईकेपीएल प्रा० लि०	104.46
30	17.03.2017	सीडी	जेओडीपीएल प्रा० लि०	1332.50
31	20.03.2017	सीडी	मार्मागाँव स्टील प्रा० लि०	81.52
32	21.03.2017	सीडी	गुप्ता इनर्जी प्रा० लि०	691.34
33	22.03.2017	सीडी	ब्लोसम ऑयल एवं फैट्स लि०	318.28
34	29.03.2017	ओसी	पूजा टेक्स–प्रिंट्स प्रा० लि०	0.14
35	30.03.2017	एफसी	एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लि०	7.27
36	31.03.2017	एफसी	होटल गौदावन प्रा० लि०	45.34
37	31.03.2017	ओसी	स्वाइबर ऑफशोर प्रा० लि०	0.48

तालिका 16: सीआईआरपी का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	सीआईआरपी की संख्या		
	बन्द	जारी	जोड़
विनिर्माण	1	19	
खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद		1	1
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद		1	1
इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण		2	2
गढ़े हुए मेटल उत्पाद		1	1
मशीनरी एवं उपस्कर		2	2
कपड़ा, चमड़ा एवं परिधान उत्पाद		3	3
लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक एवं काग़ज उत्पाद		0	0
मूल मेटल	1	5	6
अन्य		4	4
रीयल इस्टेट, किराए पर देना एवं व्यावसायिक कार्यकलाप		3	3
निर्माण		1	1
थोक एवं खुदरा कारोबार		4	4
होटल एवं रेस्टोरेंट		2	2
बिजली एवं अन्य		1	1
परिवहन, भण्डारण एवं संचार		4	4
अन्य		2	2
कुल	**1**	**36**	**37**

अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए इन्साल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इस पीठ में देखा कि चूक की गई है और प्रस्तावित रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, इसलिए, धारा 7 की उप–धारा (2) के अंतर्गत आवेदन को पूर्ण रूप में लिया जाता है, तद्नुसार यह खंडपीठ एतद्द्वारा ऋण स्थगन की घोषणा करते हुए इस आवेदन को स्वीकार करती है.... **यह कोड के अंतर्गत सीआईआरपी में स्वीकार की गई पहली सीडी है।**

निखिल मेहता एंड सन्स (एचयूएफ) एवं अन्य बनाम एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लि० [सीपी नं. (आईएसबी)–03 (पीबी)/2017]

निखिल मेहता एंड सन्स (एचयूएफ) एवं अन्य ने एएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० की सीआईआरपी शुरू करने के लिए संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया। एनसीएलटी ने 23 जनवरी, 2017 के आदेश के तहत आवेदन को खारिज कर दिया।

आवेदक ने प्रतिवादी की परियोजनाओं में संपत्तियां (कार्यालय स्थान, दुकान तथा फ्लैट) बुक किए। पक्षों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, आवेदक फ्लैट का कब्ज़ा लेने तक मासिक निष्चित रकम अदा की जाएगी। प्रतिवादी ऐसा निष्चित रकम के भुगतान में चूक की।

एनसीएलटी ने पाया कि *"वित्तीय ऋण"* के रूप में अहर्क बनाने के लिए अनिवार्य घटक यह है कि इस *"राशि को समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए संवितरित" किया जाता है। इसमें ऐसे वित्तीय लेन–देन शामिल होंगे, जहाँ कोई राशि आज प्राप्त की जाती है, उस राशि को भविष्य में किसी एक अथवा अनेक किस्तों में एक समयअवधि में अदा किया जाएगा। वर्तमान मामला संपत्ति की बिक्री अथवा खरीद का एक विशुद्ध एवं साधारण करार का है। इसमें देखा गया कि : "सिर्फ किसी निश्चित राशि देने और अपने वायदे को तोड़ा गया, ऐसे लेन–देन को "वित्तीय ऋण" का दर्जा प्राप्त नहीं होगा'* क्योंकि लेन–देन में राशि के समय मूल्य के लिए प्रतिफल नहीं होता, जो *"वित्तीय ऋण"* की अभिव्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमतकारी संघटक है।

कर्नल विनोद अवस्थी बनाम एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड [सी.पी. नंबर (आईबी) –10 (पीबी)/2017]

कर्नल विनोद अवस्थी ने कोड की धारा–9 के तहत एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सीआईआरपी शुरू करने के लिए फ्लैट का स्वामित्व देने तथा आष्वस्त प्रतिफल के भुगतान में चूक के संबंध में आवेदन दायर किया, जैसा कि पक्षों के बीच निष्पक्ष समझौता ज्ञापन में अपेक्षित है। एनसीएलटी ने दिनांक 20 फरवरी, 2017 के आदेश के तहत आवेदन को खारिज किया।

एनसीएलटी द्वारा यह देखा गया कि कोड के तहत *"प्रचालनत्मक ऋण"*, अथवा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एक दावा है, जिसमें नियोजन के संबंध में देयताएं अथवा अस्थायी रूप से प्रवृत्त किसी कानून के तहत उत्पन्न देयताओं की चुकौती के संबंध में ऋण शामिल हैं और केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को देय हैं। अतः, प्रचालनत्मक ऋण, चार श्रेणियों, जैसे कि वस्तु, सेवाओ, रोजगार एवं सरकारी देयताओं तक सीमित होता है। यह वित्तीय ऋण से भिन्न कोई ऋण नहीं होता है। इसलिए, पूर्वोक्त आष्वस्त प्रतिफलों का गैर–भुगतान एक प्रचालनत्मक ऋण नहीं है और आवेदक एक ओसी नहीं है।

के. के. वी. नागा प्रसाद बनाम लंको इन्फ्राटेक लिमिटेड (सीपी (आईबी) नं० 9/9/एचडीबी/2017)

कोड सीडी की धारा 9 के तहत मै० लंको इन्फ्राटेक लिमिटेड की सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। एए ने दिनांक 21 फरवरी, 2017 के आदेश के तहत आवेदन को खारिज किया, जैसा कि प्रश्नाधीन *"देयता" पहले से मौजूदा विवाद के अधाधीन था। एए ने पाया किः "अधिकरण पक्षों के विवादित दावों में अनावश्यक पूछताछ नहीं कर सकता क्योंकि आईबीसी का उद्देश्य एक समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्तियों, व्यक्तियों, आदि के पुनर्गठन एवं दिवाला समाधान को सुनिश्चित करना है।"*

आईबीबीआई

एबीसी के मामले में

आईबीबीआई ने आईपी के रूप में पंजीकरण हेतु एबीसी के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि एबीसी रोजगार में संलग्न है। यह देखा गया कि एक व्यक्ति को दो भूमिकाएँ – व्यवसाय एवं रोजगार – एक साथ में अदा नहीं करनी चाहिए। यह उस अपेक्षा की तरह है, जिसमें यह आवश्यकता की तरह है कि रोजगार में रत *''व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में और विलोमतः कार्य नहीं कर सकता। ऐसी अपेक्षा के पीछे विधि मान्य उद्देश्य यह है कि एक व्यावसायिक की उसकी व्यावासायिक बाहायताओं के संबंध में निष्ठा और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह आईपी के मामले में और अधिक महत्व को स्वीकार करता है जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत समग्र कार्मिक सेवाएं प्रदान करते है। यह संहिता, उदाहरणार्थ, समाधान आरम्भन के 180 दिनों के भीतर पेश किए जाने वाले समाधान योजना को अधिवेशित करता है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कारपोरेट व्यक्ति को परिसमापन में धकेला जाता है।"*

एक्स वाई जेड के मामले में

आईबीबीआई ने आई पी के रूप में पंजीकरण हेतु एक्स वाई जेड के आवेदन को अस्वीकार किया। इसने नोट किया कि कंपनी रजिस्ट्रार (आर ओ सी) ने कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के तीन आदेशों के गैर–अनुपालन हेतु अन्यों के साथ आवेदक के विरूद्ध आवेदक के खिलाफ तीन फौजदारी कार्यवाहियां दायर की है और ये कार्यवाहियां लंबित है। यह देखा गया है कि आवेदक के विरूद्ध तीन फौजदारी कार्यवाहियों की लंबितता उसकी प्रतिष्ठा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और उसे एक आईपी बनने के लिए सही एवं उपयुक्त व्यक्ति नहीं बनाती है।

'' आईबीबीआई ने यह पाया कि आईपी कंपनियों एवं व्यक्तियों के समाधान, समापन और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कम्पनी को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के उदाहरण को लें। जब कोई कंपनी इस प्रक्रिया से गुजरती है, तो आई पी कम्पनी के कार्यों के प्रबंधन में निहित होता है और वह अपने निदेशक–मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करता है। ऐसी कम्पनी भारत में लगभग रू 5 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण वाली बड़ी कंपनियों में से एक हो सकती है। वह ऐसी कम्पनी की संपत्ति का अभिरक्षक बन सकता है और कम्पनी के कार्यों को एक चालू कम्पनी के रूप में प्रबंधन करता है। इसके अलावा, वह यह पुष्टि करने के लिए प्रत्येक समाधान योजना की जांच करता है कि इसमें वर्तमान में प्रवृत्त कानून के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। इन जिम्मेदारियों में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं आचरण की आवश्यकता होती है। जिम्मेदारियों के साथ– साथ, विनियमनों मे बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं आचरण को ध्यान में रखना आवश्यक है,क्या एक आवेदक सही एवं उपयुक्त व्यक्ति है।"

च कोड का प्रभाव

कोड संबंधित व्यक्ति के आर्थिक मूल्य बनाये रखते समय सभी हितधारकों को इक्विटी एवं निष्पक्षता के ढांचे में दिवाला को हल करने के लिए एक सामूहिक तंत्र प्रदान करता है। इसका उद्देश्य, जहां कहीं भी संभव हो, दिवाला का एक समयबद्ध एवं व्यवस्थित समाधान प्रदान करना है और जहां कहीं आवश्यकता हो, निकास की सहज सुविधाएं प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्णतः उद्यमिता को बढ़ाना एव ऋण उपलब्धता करना हैं।

कोड 2016–17 में अधिनियमित किया गया था। कारपोरेट दिवाला के संबंध में इकोसिस्टम एवं विनियामक ढांचे को 2016–17 में तैयार किया गया था। सीआईआरपी से संबंधित प्रावधानों को 1 दिसंबर, 2017 को लागू किया गया था। कारपोरेट प्रक्रियाओं को वर्ष की अंतिम तिमाही में शुरू किया गया। इसमें सीआईआरपी के निष्कर्ष हेतु विशिष्ट रूप से 180 दिन लगते हैं। परिणामतः 2016–17 में सीआईआरपी संपन्न नहीं हुई। अतः समीक्षाधीन अवधि के लिए कोड के प्रभाव का निर्धारण अतिशीघ्र होगा। इस बिन्दु पर डेटा की कमी भी किसी मात्रात्मक निर्धारण को समय पर रोकता है। तथापि, नीचे कोड को लागू किए जाने में संभावित प्रभाव के बारे में कुछ संभावनाएं दर्शायी गयी हैं, जैसा कि बीएलआरसी रिपोर्ट द्वारा भी कोड के उल्लिखित उद्देश्यों के संबंध में दर्षाया गया है।

जैसा कि इसके दीर्घ शीर्षक में उल्लिखित है, कोड के निम्नलिखित चार आधारभूत उद्देश्य हैं;

(क) आस्तियों के मूल्य को अधिक से अधिक करना : कोड, देनदारो को सामूहिक प्रयास करने तथा अपने निपटान पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में सुधार लाने की मांग करके सीडी की आस्तियों के मूल्य को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यदि पुनरुद्धार संभव नहीं है, तो कोड अन्य दक्ष प्रयोगों के लिए संसाधनों को मुक्त करती है। दोनों में से किसी भी मामले में, सीडी के आस्तियों के मूल्य में सुधार आता है। यह प्रक्रिया को पुर्नोधार करने तथा शीघ्र निष्कर्ष हेतु प्रोसेस को शीघ्र शूरू करके मूल्य की गिरावट को रोकता है। वास्तव में, देनदारो की संभावित हानि को कम करने की दृष्टि से प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के लिए सीडी प्राप्त करेगा। यह सूचना की समानता का प्रावधान करता है जो सर्वोकृष्ट मूल्य का पता लगाने में सक्षम होगा।

कोड, आरपी और परिसमापक को, यह निष्चित करना यदि सीडी ने विगत में अनियमित लेनदेनों जैसे अधिकतम लेनदेन, कपट से लेनदेन, कम मूल्य के लेनदेन, और लूट–खसोट वाले लेनदेन किए हों, और यदि ऐसा है, तो उसे उपयुक्त निर्देशन हेतु ए ए को आवेदन दायर करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया से हितधारकों को न केवल खोया मूल्य प्राप्त होगा बल्कि प्रबंधन को ऐसे लेनदेनों में शामिल होने से भी रोकेगा। यह कारपोरेट अधिशासन को स्वच्छ बनाएगा और हितधारकों के विश्वास में सुधार लायेगा।

(ख) उद्यमिता को बढ़ावा देना

फर्म, सी एवं आई के समक्ष यथा नियोजित सेवा प्रदान करने में असफल रहती है और बाद में, अपनी देनदारियों का भुगतान करने में चूक करती है। कोड असफलताओं को रोकने के लिए प्रोत्साहित करके एवं विफल कारोबार को बन्द किए असफलता की घटनाओं को कम कर जहाँ कहीं भी संभव हों तथा जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, बंद कारोबार से संसाधनों को मुक्त, करता है। यह ईमानदार उद्यमी को सही रूप में बाहर निकलने में सक्षम बनाता है, यदि उसका उद्यम उत्कृष्ट सोच एवं प्रयासों के बावजूद असफल रहता है। इस प्रकार, असफलता की संभावना किसी उद्यमी को एक नई सोच के साथ नया व्यवसाय शुरू करने से नहीं रोकता।

(ग) ऋण की उपलब्धता को बढ़ाता हैः–

कारपोरेट वित्त इस समय अति उपेक्षणीय कारपोरेट ऋण, गैर–बैंक ऋण तथा गैर–सुरक्षित ऋण में मनमानी कर रहा है। जैसा कि धारा ख में स्पष्ट किया गया है, इसमें एक विकट टीबीएस लक्षण होता है। समाधान एवं परिसमापन के प्रावधान के जरिए, कोड देनदारो को भावी अर्जनों, समाधान पष्चात परिसमापन आस्तियों के विक्रय से किसी एक से अपनी देयताओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह क्रेडिटरों, बीमाकृत और अबीमाकृत, बैंक और गैर–बैंक, वित्तीय एवं प्रचालनात्मक, विदेशी एवं घरेलू – को न्यून्तम लागत पर क्रेडिट को बढ़ाने में, विशेष रूप से जब उन्हें, यदि सीडी चूक करता है, तो सीआईआरपी शुरू करने के लिए कोड के तहत अधिकार होने पर, प्रेरित करता है।

इसके अलावा,एनपीए एक त्रुटिपूर्ण चक्र बनाता हैं, जहां व्यवहार्य परियोजनाओं वाले उद्यमियों पर मूल्य भार होता है। और देनदार उन जोखिम पूर्ण उद्यमों को वित्तीय सहायता नहीं देते, जबकि उंची लागतों पर उधार लेने के इच्छुक होते है। समाधान एवं परिसमापन के प्रावधान के जरिए, यह अपेक्षा की जाती है कि कोड साहूकारों को भावी अर्जनों पश्च समाधान अथवा परिसमापन आस्तियों की बिक्री में से किसी एक से निधियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। कोड बढ़ते एनपीए की समस्या को दूर करने में भी मदद करेगा और संसाधनों के ईष्टतम उपयोग को सक्षम बनाएगा।

(घ) सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करनाः हितधारकं का संविदाओं अथवा विशेष नियमों के तहत सीडी की आस्तियों पर विभिन्न अधिकार होते हैं। सरकार परिसमापन के मामले में पूर्ववर्ती तंत्र में जल प्रपात के शीर्ष में थी। कोड परिसमापन के मामले में जल प्रपात में हितधारकों की प्राथमिकता को परिवर्तित करता है और पुनः निर्धारित करता है। चूंकि हर कोई अपनी देयताओं को हितधारक को उसकी देयता पूर्णतः अदा करने के बाद प्राप्त होता है, कोड परिसमापन को रोकता है और समाधान को सुगम बनाता है। यह कुछेक हितधारकों के लिए सीआईआरपी के स्तर पर कतिपन न्यूनतम संरक्षण निर्धारित करता है। इसमें निष्पक्षता एवं समानता के ढांचे में दिवालेपन का समाधान अपेक्षित है।

सुस्पष्ट सांविधिक उद्देश्यों से परे, कोड असफल हो रहे सीडी को बचाता है और इससे रोजगार एवं आय को बचाता है। सीआईआरपी के अभाव में, सीडी स्वभाविक मृत्यु से आहत होगा। कोड सी एवं आई को भी बढ़ावा देता है और विकास को इस सीमा तक बढ़ाता है कि विकास सीआईआरपी पर निर्भर होता है। कोड का महत्वपूर्ण प्रभाव लेनदारों और देनदारों, दोनों में व्यवहारिक परिवर्तन कर सकता है। उदाहरणार्थ, यह अपेक्षा की जाती है कि फर्म पर नियंत्रण खोने के डर से प्रमोटरों एवं प्रबंधकों को फर्म पर नियंत्रण खोने के भय से समय पर अपने ऋण की चुकौती करने में मैनेजर समय पर अपने कर्ज को चुकाने के लिए

अधिक सावधानी बरतनी होगी।यह कल्पना की जाती है कि फर्मों की कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सुधार आना चाहिए। वर्तमान में, ट्रेड क्रेडिट विशेष तौर पर 30 दिनों के लिए होता है, परन्तु कई फर्में अपने आपूर्तिकर्ताओं को समय पर चुकौती नहीं करते, क्योंकि वे आश्वस्त होते हैं कि आपूर्तिकर्ताओं के पास संसाधन नहीं होता फिर भी उनकी आपूर्ति जारी रहती है। जबकि, कोड इसे ओसी के लिए दिवाला याचिका में जाने के लिए आसान बनाता है, फर्मों को अपनी कार्यशील पूंजी प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कार्यशील पूंजी चक्रों को कम किया जा सकेगा और आपूर्ति कड़ी को अधिक दक्ष बनाया जा सकेगा।

दूसरे उदाहरण में, यह अपेक्षा की जाती है कि निजी बातचीत के जरिए अधिक से अधिक सीआईआरपी को हल किया जाना है, जिन्हें अधिक सक्षम और समपन्न उत्कृष्ट परिणाम समझा जाता है, जब इसकी शोधन अक्षम कानून की औपचारिक प्रक्रिया से तुलना की जाती हैं। न्यायालय से बाहर की वार्ताओं में, लेनदारों और क्रेडिटरों को समाधान के ढांचे में अधिक सुगमता प्राप्त होती है; जैसा कि कोड के तहत प्रक्रियाओं के अधीन किए गए समाधान से तुलना की गई है। दक्ष समाधान योजना, जिन्हें निजी रूप से अमल में लाया जाता है, वे कम्पनी अधिनियम (धारा 230–234, कम्पनी अधिनियम, 2013) के तहत विभिन्न योजनाएँ शामिल हो सकती हैं, जो कि प्रतिबिम्बित फर्म में पहले से उपलब्ध होते हैं। कोड, देनदारों और लेनदारों में व्यावसायिक बदलाव लाते हुए विकृत अथवा परिदृश्य का भय दिखाता है।

यह भी अपेक्षा की जाती है कि कोई विषत्तिवाली फर्मों को हितधारक विपत्ति की घड़ी में व्यवसाय को शीघ्र बेचना पसन्द करते हैं, शेयरधारक संकट के शुरुआती चरण में कारोबार को बेचना पसंद कर सकते हैं, जबकि वे जानते हैं कि विषत्ति का कोड के तहत कैसे हल किया जा रहा है। जबकि यह पूरी तरह से गैर–आईबीसी लेनदेन हो सकता है, अर्थात् खरीदे गए निजी इक्विटी की बिक्री को बढ़ाता है।, परन्तु इसमें कल्पना की जाती है कि कोड प्रमोटरों के प्रोत्साहन को आकार प्रदान करेगा। ऐसे परिवेश में अपेक्षा की जाती है कि प्रतिबाधित फर्मों को पुनर्गठन की दिशा में अधिक कारगर तरीके से देनदारों के साथ बातचीत करनी होगी। ये आभिलाम अस्पष्ट हैं; परन्तु दिवालिएपन के सुधार के लिए वांछित परिणामों में से हैं।

उपरोक्त के अलावा, यह अपेक्षा की जाती है कि कोड असफल कारोबार से वसूलियों को बढ़ाएगा। कोड के अधिनियमित होने तक, भारत में कारपोरेट अथवा व्यक्तिगत समाधान प्रक्रिया से वसूली दरें, जैसा कि बीएलआरसी द्वारा उल्लेख किया गया है, विश्व में सबसे कम थी, जिसमें देनदार निवल वर्तमान मूल्य आधार पर केवल 20% ऋण मूल्य को वसूल करने में सक्षम थे। क्रेडिटरों के दृष्टिकोण से, अच्छी वसूली की जा सकती है, यदि फर्म को अच्छे मूल्य पर बेचा गया हो। इस प्रकार, परिसमापन को प्रेरित करने वाली देरियों के मामलों में, मूल्य कमी आती है। फर्म के मामले में परिसमापन हेतु, देरी होने पर वसूली कम होती है। इस प्रकार, इस तरह की देरी, मूल्य विनाष को उत्पन्न करती है। दिवालिए के समाधान को एक समयबद्ध तरीके से कोड से दिवाला हुए फर्म में सभी हितधारकों के लिए वसूलियों में वृद्धि हो सकती है।

संक्षेप करते हुए एक प्रभावी दिवाला तंत्र का उद्देश्य व्यवहार्य व्यवसायों की सुरक्षा और बाजार से गैर–व्यवहार्य व्यवसायों के त्वरित निकास को सुनिश्चित करना है, जिससे अधिक उत्पादक फर्मों के लिए आस्तियों का पुनः विस्तार करके नये उद्यमियों के लिए स्थान बनाते हुए व्यवहार्य व्यवसाय की सुरक्षा और बाजार से गैर–व्यवहार्य व्यावसायों के शीघ्र निर्गम को सुनिश्चित करता है। इन दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में, लेनदारों और देनदारों के हितों को संतुलित करने, वसूली को बढ़ाने और वित्तीय रूप से दुःखी देनदारों के लिए एक सेफ्टी नेट प्रदान करने के कानून की आवश्यकता है। जैसे कोड के क्रियान्वयन से निकट भविष्य में परिणाम प्राप्त होते है, ऊपर उल्लिखित सभी परिणाम संभवतः स्पष्ट देखें जा सकते हैं।

छ बोर्ड का कार्य निष्पादन

आईबीबीआई कोड को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार परितंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। यह एक अनोखा विनियामक है, जो बाजार प्रक्रियाओं के साथ–साथ व्यावसायिकों को नियंत्रित करता है। इसमें सांविधिक दायित्वों एवं कार्यों का एक झुण्ड है।

बोर्ड द्वारा निष्पादित अर्ध–विधायी कार्यों, कार्यपालक कार्यों तथा अर्ध–न्यायिक कार्यों के ब्यौरे रिपोर्ट के भाग घ में दिए गए हैं।

बोर्ड का एक अति महत्वपूर्ण कार्य, दिवालिया परितंत्र में दिवाला एवं समाधान प्रक्रियाओं तथा सेवा प्रदायकों के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करना है। इसे लागू करने के लिए बोर्ड ने महत्वपूर्ण विनियमन तैयार किए हैं, जैसा कि सारणी 6 में उल्लेख किया गया है।

सेवा प्रदायकों के पंजीकरण एवं विनियमन के ब्यौरे इस रिपोर्ट खंड–घ घाटा में दर्शाए गए हैं।

सलाह एवं हितधारक परामर्श

यह विचार करना कि कोड द्वारा देश में दिवाला एवं शोधन अक्षमता तंत्र के लिए पूर्ववर्ती कानूनी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया गया था, हितधारकों को स्वयं परिवर्तन से अवगत होने तथा नियम बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हेतु उनके इनपुट लेने के लिए नियुक्त करना भी महत्वपूर्ण था। जैसा कि रिपोर्ट के खंड सी 3 में विस्तार से दिया गया है, आईबीबीआई ने हितधारकों को विभिन्न प्रयत्रों में; नामतः, सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज, कार्यशालाओं, आदि तथा विभिन्न क्षमताओं में, जैसे कि संकाय, पैनलालिस्ट, वक्ता, मुख्य अतिथि आदि में व्यवहारिक रूप से काम किया।

बाजार संस्थाओं को प्रोन्नत करना

कोड, ने बाजार बिचवइयों का एक पूर्ण नया सेट बनाने की सोचा है जो कोड, नामतः, आइपी, आइपीए और आइयू के तहत दिवाला एवं शोधन अक्षमता तंत्र के साथ काम करेगा। कोड को 28 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया था और इसके प्रावधानों को, जहाँ तक कॉरपोरेट का संबंध है, दिसंबर, 2016 से लागू किया गया था। प्रोसेस को शुरू करने के लिए, आईपी एवं आईपीए आवश्यक थे। इसमें कोड को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए नवप्रवर्तनः तत्काल समाधान की जरूरत थीं। व्यावाहारिक कार्यवाही करते हुए, बोर्ड ने सेवा प्रदायकों, अर्थात् आइपी एवं आईपीए के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर, 2016 तक विनियमनों को तैयार किया। बोर्ड ने सांविधिक रूप से विनियमित व्यावसायिकों, नामतः, सनदी लेखाकार, कम्पनी सचिव, लागत लेखाकार तथा अधिवक्ताओं को, जिन्होंने 15 वर्ष तक काम किया हो, आइ पी के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी। परन्तु उनके पंजीकरण को केवल छह माह के लिए वैध किया। इस प्रकार, तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए तत्काल रूप में 977 आईपी का एक कैडर सृजित किया गया था, इसके साथ ही बोर्ड द्वारा आईपीए पंजीकृत किए गए थे।

सीमित दिवाला परीक्षा

कोड के तहत, सीआईआरपी दरें शुरू करने के लिए आईपी कैडर का इक्विटी से समझौता नहीं करने के साथ उपयुक्त बनाने की महत्वपूर्ण जरूरत को देखते हुए बोर्ड ने कम से कम समय में सीमित दिवाला प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) को बोर्ड द्वारा परीक्षा को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसे 31 दिसंबर, 2016 को शुरू किया गया था। आईबीबीआई द्वारा गठित परीक्षा समिति, तब से नियमित आधार पर प्रश्न बैंक को बढ़ावा दें रही है। आईबीबीआई ने दक्षता एवं यथार्थता के हित में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया और कई स्थानों से दैनिक आधार पर ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की।

डेटा का संग्रहण एवं प्रसार

आईबीबीआई ने विनियमनों, सेवा प्रदायकों तथा परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी का अपनी सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करना शुरु किया। आईबीबीआई ने तिमाही सूचनापत्र में कोड के तहत, जैसे कि स्वीकृत कोड सीआईआरपी तथा स्वीकृत कई आईपी, आईपीए और आईपीई के तहत विभिन्न प्रोसेसों के संबंध में जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, सूचनापत्र ने एक सार प्रस्तुत किया। आईबीबीआई कोड के तहत सीआईआरपी प्रोसेस, आईपी, आईपीए, आईपीई तथा अन्य संगत हितधारकों के संबंध में एक व्यापक डेटाबेस रखता है तथा इसे अद्यतन बनाता है।

ज अधिशासी बोर्ड का निष्पादन

संगठन–कार्यालय, कर्मचारीयों, परिसंपत्तियों एवं अन्य संसाधनों और इसकी अधिशासी व्यवस्था के बीच भेद करना एक मानक कार्य है। अधिशासी बोर्ड संगठन को चलाने उसके उद्देश्यों को तथा संगठन को उन उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार बनाते हुए काम करता है। इस दृष्टिकोण के साथ– साथ आईबीबीआई (अधिशासी बोर्ड बैठक हेतु प्रक्रिया) अधिनियमन, 2017 कों 30 जनवरी, 2017 में अधिसूचित किया था जिसमें जीबी की विशिष्ट उत्तरदायित्वों को तथा कारोबार करने के तरीकों को विनिर्दिष्ट करता है।।

जीबी द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों में निम्न शामिल हैं:

(क) कोड के तहत बनाया जाने वाले विनियमन;

(ख) बोर्ड के वार्षिक लेखे;

(ग) बोर्ड का वार्षिक बजट;

(घ) बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट;

(ड़) शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(च) विभिन्न कार्यकलापों हेतु नियम पुस्तकों का प्रचालन;

(छ) विभिन्न कार्यकलापों के निपटान हेतु समय सेवा;

(ज) रु. 5 करोड़ से अधिक का व्यय;

(झ) कार्यालय परिसरों का स्थान;

(ञ) कर्मचारियों की संख्या एवं श्रेणी तथा उनका क्षतिपूर्ण; और

(ट) अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों निवास हेतू

बैठकों की प्रक्रिया: विनियमनों में अपेक्षा है कि जीबी की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें तथा प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बैठक होगी। विनियमन, बैठक के आयोजन हेतु प्रक्रिया, सदस्यों को दिए जाने वाली सूचना के ब्यौरे, कोरम तथा बैठक में मतदान प्रक्रिया को निर्धारित करता है। विनियमन सदस्यों को कार्यसूची के परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कार्य संचालन के जरिए बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को सुविधा भी प्रदान करता है।

बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण पत्र

विनियमन बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण पत्र निर्दिष्ट करता हैं। इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीबी को ऐसे तरीके में संचालित किया जाता है जो इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता से समझौता नहीं करता अथवा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन में सदस्य (यों) की योग्यता में जन विश्वास को कम नहीं करता।

अधिशासी बोर्ड की बैठकें

अधिशासी बोर्ड की पहली बैठक 7 अक्टूबर, 2016 को हुई थी। वित्त एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने जीबी की पहली बैठक में सदस्यों को संबोधित किया और कोड को लागू करने तथा उसमें आईबीबीआई की भूमिका के बारे में अपने विचार साझा किए।

वित्त एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल 7 अक्टूबर, 2016 को आईबीबीआई की पहली बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए।

इसके बाद,जीबी की वर्ष 2016–17 में चार बैठक हुई। जीबी की बैठक में उपस्थिति का विवरण तालिका 17 में उपलब्ध हैं।

तालिका 17: बोर्ड बैठक में उपस्थिति

क्रम सं.	नाम	पद	2016–17 में बोर्ड बैठक की संख्या	
			कार्यालय में आयोजित होने पर	भाग किया
1	डॉ० एम.एस. साहू	अध्यक्ष	4	4
2	श्री अजय त्यागी	*पदेन* सदस्य	3	2
3	श्री अमरदीप एस. भाटिया	*पदेन* सदस्य	4	4
4	श्री जी. एस. यादव	*पदेन* सदस्य	4	3
5	श्री उन्नी.कृष्णनन ए.	*पदेन* सदस्य	4	4
6	सुश्री सुमन सक्सेना	पूर्णकालिक सदस्य	1	1
7	डॉ० नवरंग सैनी	पूर्णकालिक सदस्य	0	0

चूंकि, समीक्षाधीन अवधि रचना काल था, जब हाल में आईबीबीआई गठन हुआ ही था, जीबी की शुरूआती बैठकों में मुख्य विनियमनों को सीआईआरपी के आरम्भन एवं एवं इसे सुगम बनाने के लिए आईपी के नामांकन हेतु सक्षम बनाने पर जोर दिया। जीबी ने सीडी के समापन से संबंधित विनियमनों पर भी विचार किया। प्रशासनिक मुद्दो, जैसे कि बोर्ड का संगठनात्मक स्वरूप, कार्यालय परिसर, अनुसंधान एशोसिएटों एवं परामर्शदाताओं की भर्ती भी महत्वपूर्ण पहलू थे, जिन पर जीबी द्वारा विचार किया गया और निर्णय किया गया।

आगे की सोचना

दिवाला एवं शोधन अक्षम तंत्र के क्रियान्वयन को समर्थन हेतु एक संचालनत्मक एवं ठोस व्यवस्था को बढ़ावा देना कोड के तहत बोर्ड का अधिदेश है। आने वाले वर्ष में आईबीबीआई कोड जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है के प्रावधानों का क्रियान्वयन को सुगम बनाते हुए, 2016–17 में की गई प्रगति को समेकित करेगा।

इनमें निम्न शामिल होगा:

(क) अगला वर्ष कई सीआईआरपी एवं परिसमापन प्रोसेसों के परिणामों को देखेगा। न्यायिक उद्घोषणाएं अपरिभाषित क्षेत्रों को हल करेंगी। हितधारक उत्कृष्ट पद्धतियां तैयार करेंगे। दिवाला तंत्र का प्रचालन नया ज्ञान पैदा करेगा। कोड में पाई गई कमियों के साथ–साथ बदमाश द्वारा किसी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना को जानकारी में लाया जाएगा और आईबीबीआई इन विकासों पर कड़ी नजर रखेगा तथा शिक्षा लेगा। यह कोड के भीतर चुनौतियों को दूर करने के लिए और बचाव के रास्ते, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए विनियामक ढाँचे में संषोधन करेगा, और सुधार करने के लिए आईपी एवं अन्य संघटकों की क्षमता का निर्माण करेगा।

(ख) अगले वर्ष स्वैच्छिक समापन और सूचना उपयोगिताओं से संबंधित विनियमनों के क्रियान्वयन के रूप में देखा जाएगा, जिन्हें 31 मार्च, 2017 को अधिसूचित किया गया था। कोड के कुछ प्रावधान, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है, को आने वाले वर्ष में अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उदाहरणार्थ, कार्य को तीव्रगामी दिवाला प्रक्रियाओं से संबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नये दिवाला तंत्र से लाभ लेने के लिए सक्षम बनाता है। आईबीबीआई इन प्रावधानों को प्रचालन में लाने के लिए सहायता ढांचे का विकास एवं सुगम बनाना है।

(ग) आईबीबीआई विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके समायोजित रूप में तथा संरचित तरीके से तैयार किए गए विनियमनों की पुनरीक्षा करने का प्रयत्न करेगा। इसमें विनियमन बनाने की प्रक्रिया को दुरस्त रखने की जरूरत है ताकि हितधारक परामर्शों एवं आपात स्थिति की मांगों के लिए क्रियान्वयन प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए प्रतिक्रिया को व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। एक संरचित इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में हितधारकों सें प्राप्त राय मुख्य स्त्रोत है जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

(घ) कोड का उद्देश्य मूल्य बढ़ाने के लिए दिवाला का समाधान है। इसमें मूल्य के वस्तुगत निर्धारण और उनके मूल्य के संदर्भ में विभिन्न विकल्पों की तुलना हेतु एक ढांचे की जरूरत है। आईबीबीआई दिवाला तंत्र में प्रयोग हेतु एक जवाबदेह और सक्षम मूल्यांकन व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

(ड़) इस बात को ध्यान में लेते हुए कि दिवाला कानून एकदम नया कानून है, आईबीबीआई इसके बारे में जागरूकता पैदा करने और दिवाला समाधान हेतु शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, व्यावसायिकों तथा अन्य हितधारकों के साथ काम करता रहेगा। यह सलाहकारी समारोहों को आयोजित करता रहेगा और उनमें भाग लेता रहेगा।

(च) कोड के उदार उद्देश्यों को लागू करने के लिए सेवा प्रदायको की जरूरत होती है, जिनमें अत्यधिक सत्यनिष्ठा हो। उन व्यक्तियों को रोकने के अलावा, जो स्वस्थ एवं उचित नहीं हैं; दिवाला परितंत्र को लागू करने के लिए आईबीबीआई उस सेवा प्रदायक को हटाएगा, जो सेवा प्रदायक के रूप में अपने आप को निरन्तर स्वस्थ एवं उपयुक्त नहीं रखता।

झ बोर्ड का वित्तीय निष्पादन

कोड के तहत आईबीबीआई को उचित लेखा और अन्य संगत रिकॉर्ड रखेगा तथा प्रत्येक ऐसे प्रपत्र में लेखों का वार्षिक विवरण रखना आवश्यक है, जैसा भी केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण (सीएवंएजी) के परामर्श से निर्धारित किया जाए। इसके अलावा अपेक्षा की जाती है कि आईबीबीआई के लेखों का लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं म०ले० परीक्षक द्वारा किया जाए। तद्नुसार, आईबीबीआई ने लेखापरीक्षा समिति एवं इसके अधिशासी बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित लेखों एवं तुलन पत्र कर लेखा–परीक्षा हेतु नि०एवं म०ले०प० को भेजा था। नि०एवं म०ले०प० ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आईबीबीआई के लेखों का लेखा परीक्षा किया आईबीबीआई के वित्तीय निष्पादन का सार तालिका–18 मे दिया गया है।

तालिका–18: आय एवं व्यय विवरण: **(आंकड़े लाख रुपए में)**

आय	2016–17	व्यय (निम्न जैंसे)	2016–17*
सहायता अनुदान–वेतन	275.00	सहायता अनुदान–वेतन	66.99
सहायता अनुदान–पूंजी	192.86	सहायता अनुदान–पूंजी	–
सहायता अनुदान–सामान्य	203.28	सहायता अनुदान–सामान्य	49.15
आईबीबीआई हेतु एमसीए द्वारा खर्च	136.47	आईबीबीआई हेतु एमसीए द्वारा खर्च	136.47
आंतरिक रूप से उत्पन्न राजस्व	89.73		
कुल	**897.34**	**कुल**	**252.61**

* अक्टूबर, 2016–मार्च, 2017 की अवधि के लिए।

आईबीबीआई को सरकार से वर्ष 2016–17 में रु. 807.61 लाख का कुल अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें राजपत्र अधिसूचनाओं पर एमसीए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया खर्च रु 186.47 लाख शामिल है। इन सेवा प्रदायकों से रु. 89.73 लाख का शुल्क इसे प्राप्त हुआ। इसने कुल रु. 252.61 लाख खर्च किए, जिसमें सीधे तौर पर किया गया खर्च रु. 136.47 लाख शामिल है।

विनियामक सामान्य तौर पर शुरू में कम दर पर शुल्क लगाता है और इसे एक उपयुक्त स्तर पर इसे बढ़ाता है, वह निचले स्जर पर शुल्क को रखता है। (शुरूआती वर्षों में लेनदेन की संख्या एवं मात्रा कम होती है), जिसे बाजार के विकास के साथ–साथ बढ़ाया जाता है, शुरूआती वर्षों में भारी पूंजी कम प्राप्त करने की जरूरत होती है। शुरूआती वर्षों में कम आय और अधिक खर्चों के सापेक्ष विनियामक सामान्य तौर पर बहिर्जात अंशदान पर निर्भर करता है। आईबीबीआई को शुरूआती वर्षों में अनुदान हेतु सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

बीएलआरसी का मानना है कि एक अच्छे व्यवहार के रूप में, बोर्ड अपनी विनियमित कम्पनियों से एकत्र किए गए शुल्क से स्वयं को वित्तपोषित करना चाहिए। उद्योग एवं कम्पनियों का समय के साथ विकास होगा।, जबकि बोर्ड द्वारा शुरू से अपने पर्यवेक्षकीय कार्यों को पूरा करना उनमोकित है। परिणामस्वरूप, एक ऐसा समय आएगा, जब बोर्ड को सरकार द्वारा आर्थिक वित्तयोषित किये जाने की जरूरत होगी।

"भारत के दिवाला एवं शोधन अक्षम बोर्ड के निर्माण" संबंधी कार्य समूह ने स्वीकार किया कि आईबीबीआई के निर्माण के शुरूआती चरण में वित्तयोषित का मुख्य स्त्रोत सरकार होगी। तथापि, कुछ वर्षों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता मध्यवर्ती उद्योग की रूपरेखा दिखाई देगी और तब आईबीबीआई समस्त आई पी, आई पी ए और आई यू पर शुल्क लगा सकेगा तथा आई मूल्य खर्चो को पुरा करेगा।

ञ संगठनात्मक मामले

स्थापना

आईबीबीआई की स्थापना कोड की धारा 188 के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 (इनस्क्रिप्ट 3) अधिसूचना के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2016 को की गई। कथित अधिसूचना में विनिर्देशित है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

इनस्क्रिप्ट–3 : आईबीबीआई की स्थापना

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 — REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2387] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 2016/आश्विन 9, 1938
No. 2387] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 2016/ASVINA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3110(अ).– केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 188 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अक्तूबर, 2016 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना की तारीख के रूप में नियत करती है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा.सं. 30/2/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2016

S.O. 3110(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 188 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints 01st October, 2016 as the date of establishment of Insolvency and Bankruptcy Board of India. The head office of the Insolvency and Bankruptcy Board of India shall be at New Delhi.

[F. No. 30/2/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

4683 GI/2016 (1)

आईबीबीआई ईकोसिस्टम का एक प्रमुख स्तंभ है जो निम्नलिखित व्यापक जिम्मेदारियों के साथ कोड के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है:

(क) आईपी, आईपीए एवं आईयू सहित सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण एवं विनियमन;

(ख) कॉर्पोरेट दिवाला, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला, एवं व्यक्तिगत शोधन अक्षमता से संबंधित प्रक्रियाओं का विनियमन;

(ग) सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण और प्रक्रियाओं से संबंधित उत्कृष्ट व्यवहारों को बढ़ावा देना;

(घ) प्रक्रियाओं की देखरेख और निरीक्षण, अन्वेषण एवं अधिनिर्णय के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी; और

(ङ) रिकार्ड एवं जानकारी का रखरखाव और अनुसंधान का आयोजन।

अधिशासी बोर्ड

सहिता की धारा 189 के अनुसार में, आईबीबीआई के अधिशासी बोर्ड निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(क) एक अध्यक्ष;

(ख) वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी अधिकारियों में से तीन सदस्य, *पदेन*;

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक सदस्य, *पदेन*; और

(घ) सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य जिसमें से न्यूनतम तीन पूर्णकालिक सदस्य हैं।

डॉ. एम.एस. साहू को कोड की धारा 189 के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से नियुक्त किया गया। श्री अरूण जेटली, केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा उसी दिन उन्हें पद की शपथ दिलाई गई।

आईबीबीआई अध्यक्ष, के रूप में डॉ. एम.एस. साहू को पद की शपथ दिलाते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री

अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से बोर्ड में निम्नलिखित *पदेन* सदस्यों को नियुक्त किया गया:

(क) श्री अजय त्यागी, अतिरिक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय;

(ख) श्री अमरदीप एस. भाटिया, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय;

(ग) श्री जी.एस. यादव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय; और

(घ) श्री उन्नीकृष्णन ए, विधि सलाहकार, विधि विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक

बाद में, बोर्ड में दो पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किये गये। वर्ष 2016–17 के दौरान, बोर्ड में नियुक्त सदस्यों का विवरण नीचे तालिका 19 में दिया गया है।

तालिका–19: अधिशासी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति के समय पद	पदनाम	प्रतिनिधित्व	नियुक्ति की तिथि
1	डॉ. एस.एस. साहू	सदस्य, सीसीआई	अध्यक्ष	लागू नही	01.10.16
2	श्री अजय त्यागी	अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय	*पदेन* सदस्य	एमओएफ	01.10.16
3	श्री अमरदीप एस. भाटिया	संयुक्त सचिव, एमसीए	*पदेन* सदस्य	एमसीए	01.10.16
4	श्री जी.एस. यादव	संयुक्त सचिव, एमएलएंडजे	*पदेन* सदस्य	एमएलएंडजे	01.10.16
5	श्री उन्नीकृष्णन ए.	विधि सलाहकार, आरबीआई	*पदेन* सदस्य	आरबीआई	01.10.16
6	सुश्री सुमन सक्सेना	पूर्व डिप्टी सीएंडएसी	पूर्णकालिक सदस्य	लागू नही	22.02.17
7	डॉ. नवरंग सैनी	महानिदेशक, एमसीए	पूर्णकालिक सदस्य	लागू नही	31.03.17

संगठनात्मक संरचना

जैसा खण्ड–बी में वर्णित, सरकार ने कोड की धारा 196 एवं 197 के साथ ही अन्य विनियामक जैसे सेबी की संरचना के अंतर्गत इसको प्रदत्त अधिकारों एवं इसके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ–साथ आईबीबीआई के संगठनात्मम संरचना एवं डिजाइन के लिए 'भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के निर्माण' पर कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह ने संगठनात्मक संरचना के डिजाइन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार किया:

(क) कार्यात्मक पृथक्करण: अर्ध–विधायी, अर्ध–कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक कार्यों को पृथक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।

(ख) कार्यात्मक विशेषज्ञता: आईबीबीआई के भीतर कार्यात्मक समूहों को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए जो समय के साथ मानव पूंजी के विकास को सुगम बनाते हैं।

(ग) आधुनिक कार्यालय: उच्च उत्पादकता को हासिल करने के लिए कार्यालय स्थान, कागज़ रहित कार्यालय के साथ वर्कफ्लो ऑटोमेशन सहित आधुनिक कार्यालय संरचना प्रदान की जानी चाहिए।

(घ) जबावदेही एवं पारदर्शिता का उच्च मानक: संगठनात्मक संरचना उद्देश्य की स्पष्टता, जीबी और जनता के कार्यनिष्पादन एवं जबावदेही के अनुकूल अधिषासी बोर्ड होना चाहिए।

आईबीबीआई कोड के अधीन पेशे के साथ ही प्रक्रियाओं के लिए विनियामक की भूमिका निभाना है। एक विनियामक के रूप में, यह एक लघु–राज्य है और एक साथ अर्ध–विधिक, कार्यकारी एवं अर्ध–न्यायिक कार्यों को सम्पादित करता है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि पेशा एवं प्रक्रिया दोनों विकसित हो रही हैं, आईबीबीआई के पास विनियमन के अलावा इसके प्रारंभिक वर्षों में काफी विकास संबंधी जिम्मेदारियां होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यसमूह की अनुशंसाओं पर विचार करने पर आईबीबीआई ने अंतर–संस्थागत मोलभाव को रोकने के लिए स्वयं को तीन अलग प्रकोष्ठ नामतः अनुसंधान एवं विनियामक प्रकोष्ठ, पंजीकरण एवं निगरानी प्रकोष्ठ और प्रशासनिक कानून प्रकोष्ठ **(आंकड़े 2)** में संरचित किया है और इनमें से प्रत्येक प्रकोष्ठ पूर्णकालिक सदस्य द्वारा नेतृत्व किया जाता है **(बॉक्स 7)**।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

बोर्ड विनियमों में केवल जीबी के लिए निपटाए जाने वाले कुछ मामलों को आरक्षित किया है। कोड की धारा 191 अध्यक्ष को बोर्ड के मामलों की सामान्य अधीक्षण और निदेष और बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जा सकने वाले अधिकारों के लिए सक्षम बनाती है। कोड की धारा 230 बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी को कोड के अधीन अपने अधिकारों एवं कार्यों की कोड उसे सम्पादित करने में सक्षम बनाती है। संहिता की धारा 240 के अंतर्गत ऐसी शर्तें, यदि कोई हो, के अधीन जो प्रत्यायोजन के आदेष में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बोर्ड ने बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए विभिन्न अधिकारों एवं कार्यों के प्रत्योजन हेतु 24 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई (अधिकारों एवं कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 जारी किया । इस तरह का प्रत्यायोजन कोड या उसके अधीन नियमों या विनियमों के तहत अधिकारों एवं कार्यों के प्रत्यायोजन के अल्पीकरण के अलावा नहीं है। किसी भी पूर्णकालिक सदस्य या अधिकारी के लिए अधिकारों एवं कार्यों का प्रत्यायोजन रिपोर्टिंग पदानुक्रम में किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है जो ग्रेड या पद में उच्च हो।

बॉक्स 7 विनियामक राज्य

सरकार के साथ अभिशासन को साझा करने के लिए नियामकों का उदय एक वास्तविकता है; हाल के पिछले दशकों में विनियामकों के माध्यम से अभिशासन में महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार हुए हैं। प्रतिभूति बाजार, बीमा, बिजली, दूरसंचार, प्रतिस्पर्धा, पेट्रोलियम एवं गैस, एयरपोर्ट आदि क्षेत्रों में विनियामक अच्छी तरह स्थापित हुए हैं और बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरत को देखते हुए अन्य कई क्षेत्र में सामने आ रहे हैं।

एक विनियामक कई अनोखी विशेषताओं के साथ एक संस्थान है। यह एजेंसियों, सरकार एवं बाजार के पदानुक्रम[20] के मध्य में रहती है। यह सरकार के साथ एक प्रधान–एजेंट सम्बंध को साझा करता है। यह सरकार की ओर से अभिशासन को एक पूर्व–परिभाषित ढांचा में आगे बढाता है। यह अधिकार एवं दायित्व के संदर्भ में सरकार को एक साथ मिलाता है। इसके पास उत्तरदायित्व – ग्राहक सुरक्षा, विकास एवं विनियमन – सरकार दिये गये दायित्वों के समान है। इसके पास सरकार की तरह विधिक, कार्यकारी एवं न्यायिक अधिकार हैं।

विनियामक के माध्यम से अभिशासन के महत्वपूर्ण लाभ हैं। यह सामान्यतः सरकार के 'सामाजिक' दायित्वों को साझा नहीं करता है; न ही 'हित' समूहों के दबाव से इसके प्रभावित होने का अनुमान है। यह सभी प्रतिभागियों को एक समान कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। यह इसको सौंपे गये कार्यों की जटिलताओं से मेल खाते हई विशेषज्ञता का निर्माण करता है और तेजी से एवं सतत रूप से प्राधिकार को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं का विकास करता है। यह अप्रिय, लेकिन आवश्यक निर्णय लेने के लिए सरकार की तुलना में बेहतर है।

ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दें भी हैं। एक इकाई में विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक निर्णय का मिलने पर इसके दुरूपयोग की भी संभावना होती है। यह लोकतांत्रिक कमियों से ग्रस्त है क्योंकि यह सीधे लोगों या उनके प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। सरकार विनियामक के माध्यम से संचालित अभिशासन के लिए पूरी तरह जवाबदेय रहती है जो प्रधान–एजेंट समस्या के उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करता है। आपातकालीन स्थिति में, सरकार को व्याख्या करने एवं राहत प्रचालनों के निष्पादन के लिए कहा जाता है। विनियामक के माध्यम से अभिशासन के फायदों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए स्पष्ट खतरे के बीच व्यापार बंद को कम करने की चुनौती है, जिसमें शासनादेश, स्वतंत्रता और जवाबदेही के लिए उचित व्यवस्था के साथ विनियामक के अत्याधुनिक डिजाइन[21] के माध्यम से जनादेश का मिलान होता है।

पिछले तीन दशकों में विनियामकों के बारे में सोच और डिजाइन काफी विकसित हुई है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 विनियामकों के डिजाइन पर कुछ पारंपरिक सोच प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यह किसी भी विनियमन, जो आईबीबीआई की लोकतांत्रिक वैधता को मजबूत करता है, की अधिसूचना से पूर्व जीबी, सलाहकार एवं कार्यकारी समिति के पूर्णकालिक सदस्यों को लोक सलाह प्रदान करता है।

एक विनियामक के डिजाइन में तीन विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला, कानून के साथ जुड़ी सहायक एजेंसियों के बीच अधिकारों का व्यापक पृथककरण – विधायिका कानून बनाती है; कार्यपालिका एवं न्यायपालिका क्रमशः संचालन एवं इनको लागू करते हैं। यह अपने अधिकारों का दुरूपयोग रोकने के लिए एक दूसरे के बीच जांच एवं संतुलन का प्रावधान बनाये रखता है। इस विषय में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि *''समान निकाय (सेबी) में विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक अधिकारों को जोड़कर अधिकारों का एकीकरण भविष्य में कई सार्वजनिक कानूनी विषयों को उठा सकता है जैसा कि एक निकाय को दूसरे निकाय के ऊपर नियंत्रण अधिकारों के पृथकरण के सिद्धांतों को बनाये रखने की एक सेन्ट्रल थीम थी''*[22]। एक विनियामक पारस्परिक जांच एवं संतुलन के रूप में सेवा देने के लिए अर्ध–विधायी, कार्यकारी एवं अर्ध–न्यायिक कार्यों को करने के लिए अधिकारों के पृथकरण के सिद्धांत का पालन करता है।

दूसरा, प्रत्येक कार्य इस प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाता है कि शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखा जाए और पक्रिया में पूर्ण एकता बनाई रखी जाए। यह देखते हुए कि विनियमनों में कानून का शाक्ति है, अर्ध–विधायी कार्य को उचित देखभाल एवं परिश्रम के साथ किया जाता है। सहायक विधान को महत्व पर प्रकाश डालते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि

''हमने पाया है कि कुछ अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के अधीन हमारे लोकतंत्र का यह एक बेहतर कार्य होगा और सभी अधीनस्थ कानून ''पारदर्शी''...... होने चाहिए। *''हम संसद को इस मुद्दे को उठाने और एक कानून की तर्ज पर कानून बनाने की सलाह देंगे। यू.एस. प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (निश्चित रूप से अच्छी तरह परिभाषित अपवादों के साथ) जिसके द्वारा सभी अधीनस्थ कानून एक पारदर्शी प्रक्रिया के अधीन हैं और इसके द्वारा सभी हितधारकों के साथ उचित विचार–विमर्श किया जाता है और सभी हितधारकों के विचार के बाद नियम एवं विनियमन बनाने के अधिकारों का उपयोग किया जाता है और साथ में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो मौटे तौर पर उनसे सहमत होने या असहमत होने के कारणों, को ध्यान में रखता है''*[23]। इसी प्रकार, अर्ध–न्यायिक कार्य सामान्य न्यायिक सिद्धांतों का पालन करके एक चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय–सीमा के साथ किये जा सकते है।

तीसरा, एक विनियामक को अपने अधिदेश पर जवाबदेही के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए बिना किसी भय या पक्ष के अपनी जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए संसाधन और अधिकारों की भी जरूरत होती है। तथापि, एक लोकतांत्रित ढांचे में प्रत्येक एजेंसी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि वह अपने अधिदेश से आगे नहीं बढ़ेगी। जवाबदेही व्यवस्था सामान्यतः स्वयं विनियामक और बाहरी एजेंसियों द्वारा किये गये कार्यप्रर्दशन का चरणबद्ध मूल्यांकन प्रदान करती है और पारदर्शिता के साथ कार्यक्रम विनिर्दिष्ट प्रकटन एवं रिपोर्ट की श्रृंखला बनी रहती है।

'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड पर कार्य समूह के निष्पादन गठन पर कोड के तहत आईबीबीआई की भूमिका पर विचार करता है और उच्च कार्यनिष्पादन के लिए इसके कुशल कार्यसंचालन हेतु आवश्यक आधुनिक ज्ञान, विनियामक डिजाइन की अनुशंसा और प्रक्रिया एवं अभिशासन व्यवस्थाओं के कार्य को सम्पादित करता है। अनुशंसाओं को व्यापक तौर पर स्वीकार एवं कार्यान्वित किया जाता रहा है।

[20]ब्रौन, डिटमार और फैब्रीजियो गिलार्डी (2006), डिटमार ब्रौन और फेब्रीजियो गिलार्डी (एड्स) डेलीगेशन ऑफ कंटेंपरेरी डेमोक्रेसीज में ''परिचय'', साइकोलॉजी प्रेस।
[21]गाइड, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, भारत सरकार की मार्च, 2013 की रिपोर्ट में उपलब्ध है।
[22]क्लैरिएंट इंटरनेशनल और अन्य बनाम सेबी {2003 की अपील (सिविल) 3183} के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का दिनांक 25 अगस्त, 2004 का निर्णय।
[23]सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मामले में दिनांक 11 मई, 2016 का निर्णय।

चित्र 2: संगठनात्मक संरचना

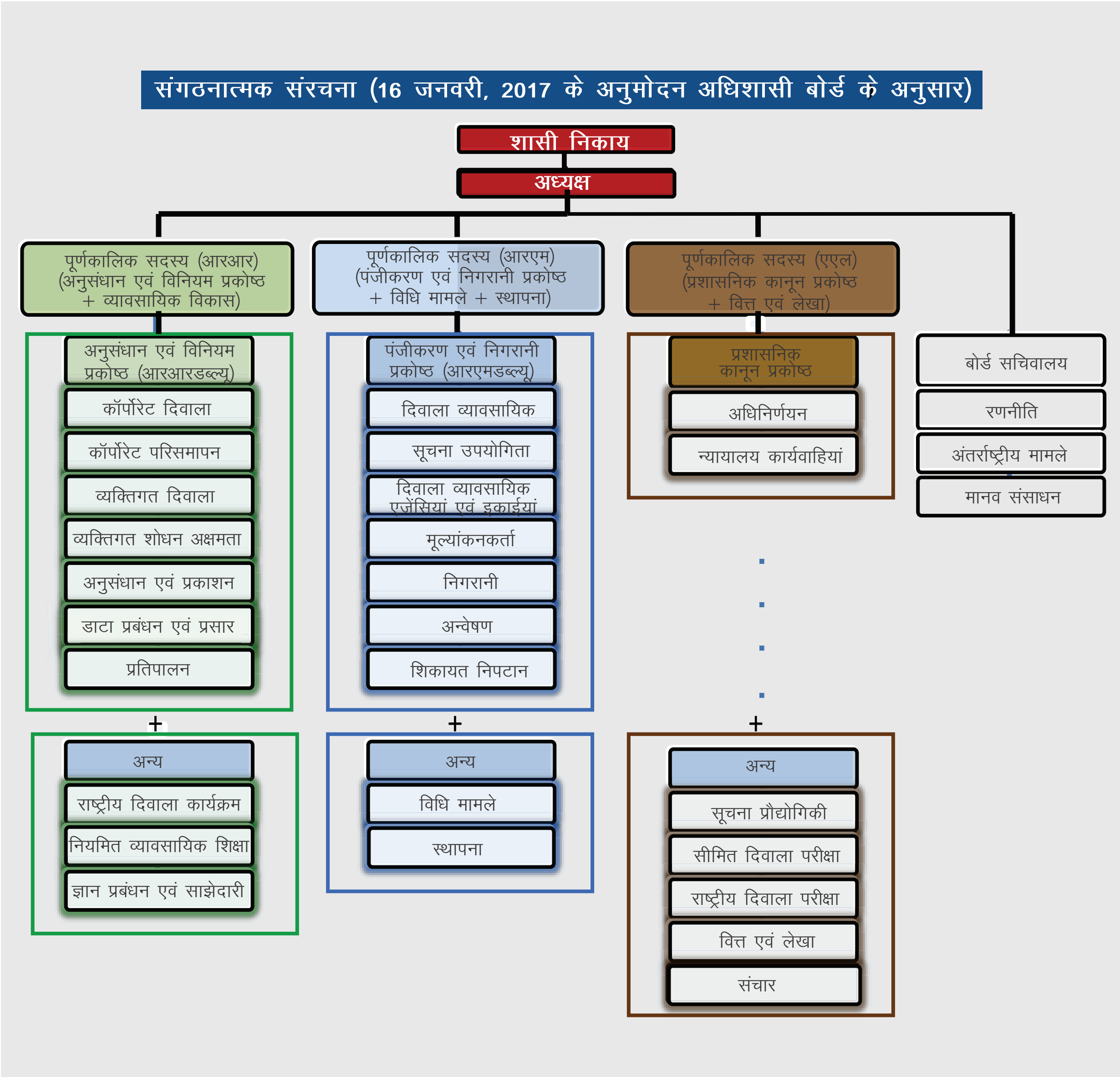

सलाहकार समिति

सलाहकार समिति (एसी) विनियामक के प्रारंभिक दिनों जब इसके पास पर्याप्त ज्ञान एवं अधिक विनियामक क्षमता नहीं होती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वे समय के साथ–साथ नई सेवाओं, नये उत्पादों, नई पहलों, नई तकनीकों के लिए एक उपयोगी उद्देश्य के साथ सेवा जारी रखते हैं और लोकतांत्रिक घाटे को कम करने के अलावा, विनियामक परिदृश्य को बदलते रहते हैं। कोड की धारा 197 बोर्ड को विनियमनों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए एसी का गठन करने में सक्षम बनाती है।

तत्कालिकता को देखते हुए, विनियमन की लंबित अधिसूचना को देखते हुए, आईबीबीआई ने 1 दिसम्बर, 2016 को कॉर्पोरेट दिवाला एवं समाधान प्रक्रिया की शुरूआत करने के लिए सेवा प्रदाताओं एवं कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं के संबंध में विनियमों पर सलाह देने के लिए निम्नानुसार 18 अक्टूबर, 2016 को दो एसी का गठन किया:

(क) अध्यक्ष के रूप में, श्री टी.वी. मोहनदास पई (अध्यक्ष, मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन) के साथ सेवा प्रदाताओं हेतू संबंधी सलाहकार समिति, और

(ख) अध्यक्ष के रूप में श्री उदय कोटक (कार्यपालक उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोटेक महिन्द्रा बैंक) के साथ कॉर्पोरेट दिवाला एवं परिसमापन संबंधी सलाहकार समिति ।

दिसम्बर, 2016 में अपनी रिपोर्ट में ''भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के गठन; पर डब्ल्यूजी ने सुझाव दिया कि आईबीबीआई के पास न्यूनतम दो एसी, एक कॉर्पोरेट दिवाला और दूसरा व्यक्तिगत दिवाला में सहायता के लिए होनी चाहिए। बोर्ड ने 30 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 अधिसूचित किया।

विनियमन एसी के गठन, बनावट एवं बैठकों, इसके अधिदेश एवं इसके सदस्यों का आचरण प्रावधान करता है। उन्होंने प्रावधान किया है कि एसी में मिश्रित सदस्यों के दो सेट नामतः (क) व्यावसायिक सदस्य, जो संबंधित क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद या पेशेवर है, और (ख) सामान्य सदस्य जो प्रसिद्ध नागरिक है और जिनका क्षेत्र में सीधी तौर पर जुड़ाव या हित नहीं है। यह स्वेच्छा से किसी विषय पर आईबीबीआई, को इसके दायरे में, सलाह दे सकता है और आईबीबीआई के एक अनुरोध पर किसी भी विषय पर व्यावसायिक समर्थन देने की सलाह दे सकता है। विनियमन आईबीबीआई को निम्ननिलिखित समितियों का गठन करने में सक्षम बनाता है:

(क) सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति;

(ख) कॉर्पोरेट दिवाला एवं परिसमापन पर सलाहकार समिति;

(ग) व्यक्तिगत दिवाला एवं शोधन अक्षमता पर सलाहकार समिति; और

(घ) अन्य कोई विषय विशिष्ट सलाहकार समिति जिसे आईबीबीआई समय–समय पर उचित समझता है

अनुशासनात्मक समिति

बोर्ड ने कारण बताओं सूचनाओं पर विचार करने एवं उसके निपटान के लिए केवल बोर्ड डब्ल्यूटीएम शामिल करने अनुशासनात्मक समिति (डीसी) की परिकल्पना की है। बोर्ड ने किसी अन्य डब्ल्यूटीएम की अनुपस्थिति में 1 फरवरी, 2017 को डॉ. एम.एस. साहू को शामिल करके एक डीसी का गठन किया है।

राजभाषा

आईबीबीआई ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए कई उपाय किये हैं। इसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी में जरूरी करना 2016–17 में बनाए गए विनियमों के सभी दस सेटों की अधिसूचना शामिल है। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मानव संसाधन

आईबीबीआई की स्थापना से पूर्व, एमसीए ने आईबीबीबाई की स्थापना में सहायता के लिए अस्थाई पुनः नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति आधार पर ट्रांजिट अवधि स्टॉफ के रूप में उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संगठनों से अधिकारियों की एक सूची प्राप्त की थी। संगठनात्मक ढांचे पर लंबित परिदृश्य को देखते हुए मानव संसाधन और विभिन्न स्तरों पर पदों के सृजन से संबंधित अधिसूचना के आधार पर बोर्ड ने तत्काल मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए एमसीए द्वारा प्राप्त सूची से पुनः नियुक्ति पर वर्ष 2016–17 के दौरान छह अधिकारियों की भर्ती की।

संगठन को कॅरियर प्रगति प्रदान करते हुए तत्काल निर्णय लेने के लिए संगठन को कम पदानक्रम रखने के लिए बोर्ड ने अधिकारियों को करियर प्रोग्रसन प्रदान करने के लिए पदानक्रम में चार स्तर बनाने का निर्णय लिया जिसमें प्रत्येक ग्रेड पर दो स्तर निम्नानुसार तालिका 20 में दिये गये हैं।

तालिका–20: आईबीबीआई में अधिकारियों का अनुक्रम

स्तर	प्रकार	ग्रेड	पद
I	कनिष्ठ प्रबंधन	ए	सहायक प्रबंधक
		बी	प्रबंधक
II	मध्य प्रबंधन	सी	सहायक महाप्रबंधक
		डी	उप महाप्रबंधक
III	वरिष्ठ प्रबंधन	ई	महाप्रबंधक
		एफ	मुख्य महाप्रबंधक
IV	शीर्ष प्रबंधन		कार्यपालक निदेशक

ग्रेड ए/बी (लेवल–1) के अधिकारी ग्रेड–सी/डी (लेवल–2) के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे और लेवल–सी/डी (लेवल–2) के अधिकारी ग्रेड–ई/एफ (लेवल–3) को रिपोर्ट करेंगे और ग्रेड–ई/एफ (लेवल–3) के अधिकारी कार्यपालक निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। विभाग/प्रभाग पर ध्यान दिये बिना समान पदनाम वाले समान ग्रेड के सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निवर्हन करेंगे।

बोर्ड ने सेबी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन एवं हितलाभ अपनाने का निर्णय लिया, यह देखते हुए कि यह सेबी की तर्ज पर संरचित है और इसके कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अनुसंधान सहायक

विनियमनों अधिसूचना के लंबित होते हुए बोर्ड ने अनुबंध आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पैनल से उन्हीं शर्तों पर जिनमें वे सीसीआई द्वारा भर्ती के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध किये गये थे। इसने आईबीबीआई (अनुसंधान सहागणों एवं परामर्षदाताओं की नियुक्ति) विनियमन, 2017 को 30 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया था। ये विनियमन तीन विभागों नामतः अर्थशास्त्र/जन नीति, कानून एवं व्यवसाय प्रबंधन में अनुसंधान सहायकों/सलाहकारों के पांच स्तरों एवं उनकी योग्यता, अनुभव, चयन, पारिश्रमिक,

कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एवं नियुक्ति के नियम व शर्तों को प्रावधान करता है । अनुसंधान सहायकों को अनुबंध आधार पर न्यूनतम छह माह एवं अधिकतम दो वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। बोर्ड ने किसी भी समय पर एक साथ सभी स्तरों के लिए 25 से अधिक अनुसंधान सहायकों/सलाहकारों की नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है।

भर्ती

तालिका 21: 31 मार्च, 2017 को अनुमोदित संख्या की तुलना में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या को प्रस्तुत करती है:

तालिका 21: 31 मार्च, 2017 को आईबीबीआई के कर्मचारी

पद	अनुमोदित संख्या	वास्तविक संख्या	
		संख्या	भर्ती की पद्धति
कार्यपालक निदेशक	3	0	लागू नहीं
जीएम/सीजीएम	10	1	पुनः नियोजन
एजीएम/डीजीएम	10	5	पुनः नियोजन
प्रबंधक/सहायक प्रबंधक	20	0	लागू नहीं
अनुसंधान सहायक एवं सलाहकार	25	7	अनुबंध
सहायक अनुभाग अधिकारी	4	1	प्रतिनियुक्ति
कुल	**72**	**14**	

क्षमता निर्माण

दिवाला एवं शोधन अक्षमता के उभरते क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आईबीबीआई ने कई सेमिनारों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों को भेजा। इसने एक विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला की शरूआत की है जिसमें आईबीबीई के हित से जुड़े मामलें पर अपने विचार साझा करने और बोर्ड के कर्मचारियों के साथ वार्तालाप के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईबीबीआई आधुनिक युग का विनियामक है। कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता के हित में, इसने अपनी स्थापना से ही अपने सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। इस संबंध में आईबीबीआई द्वारा की गई मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं:

वेबसाइट: आईबीबीआई डोमेन नाम www.ibbi.gov.in पंजीकृत किया और नवम्बर 2016 में अपने कार्यकलापों के प्रसार के लिए एक वेबसाइट प्रारंभ की।

ऑनलाइन परीक्षा: आईबीबीआई ने 31 दिसम्बर, 2016 को एक आईटी सक्षम सीमित दिवाला परीक्षा प्रारंभ की। परीक्षा कई स्थानों पर दैनिक आधार पर ऑनलाइन सम्पादित की जाती है। पंजीकरण, भुगतान, नामांकन, प्रश्नपत्र तैयार करने एवं मूल्यांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित है।

जन सलाह: आईबीबीआई विनियमनों को बनाने के लिए एक पारदर्शी एवं परामर्शदायी प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। यह टिप्पणियों एवं सुझावों को प्राप्त करने और प्रक्रियारत करने के लिए एक संरचित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर मसौदा विनियमनों को रखता है।

परिसर

आईसीएमएआई के एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एमसीए ने सीएमए भवन, 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली में आईबीबीआई की शुरूआत की। लगभग छह माह से आईबीबीआई सीएमए भवन में परिचालित रहा है। इसी समय, एमसीए ने आईबीबीआई के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से 7वां तल, मयूर भवन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली को पट्टे पर लिया और उसका नवीनीकरण किया। नवीनीकरण समाप्त होने के बाद वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 29 मार्च, 2017 को इस परिसर का उद्घाटन किया और आईबीबीबाई ने अपना कार्य संचालन सीएमए भवन से मयूर भवन में स्थानांतरित किया।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता के हित में आईबीबीआई अपनी वेबसाइट पर विनियमनों, परिपत्रों और अधिनिर्णयन तथा सेवा प्रदाताओं के विवरणों को प्रकट प्रोसेस और कोड के अंतर्गत अपनी वेबसाइट पर प्रक्रियागत करता है। इसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित प्रकटन बनाए हैं। इसने अधिनियम के अधीन किये गये आवेदन पर किसी भी नागरिक को सूचना प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत सुश्री अनीता कुलश्रेष्ठ, डीजीएम को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पदनामित किया है। अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं उनके निपटान का विवरण नीचे तालिका 22 में दिया गया है:

तालिका 22: वर्ष 2016–17 में प्राप्त आर टी आई आवेदन एवं उनका निपटान

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए सीपीआईओ द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	2
2	आवेदन जिनके लिए सीपीआईओ द्वारा जानकारी प्रदान की गई	2
3	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन	0
4	सीपीआईओ के आदेश के अधीन दाखिल पहली अपील	0

वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल 29 मार्च, 2017 को आईबीबीआई के परिसर का उद्घाटन कर रहे हैं।

degree360solutions.com

सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7 वीं मंजिल, मयूर भवन,
शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली –110001